



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13, 2001/वीज 23, 1922

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13, 2001/PAUSA 23, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001

का.आ. 27.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में
कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र
में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं. एमसीएल/एमएएमवी/सीजीएम (सीजी एण्ड पी)/मनोहरपुर/00/19 तारीख
28 अप्रैल, 2000 का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक (कोयला प्रोजेक्ट एण्ड प्लानिंग) महानदी कोलफील्ड्स लि. जामूति बिहार बुरला सम्बलपुर-
768018 (उड़ीसा) के कार्यालय में या कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अंगुल, उड़ीसा के कार्यालय में या कोयला निबंधक, 1, काउन्सिल
हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में, हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निविष्ट
सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रभारी अधिकारी
और विभागाध्यक्ष (राजस्व/सम्पदा), महानदी कोलफील्ड्स लि., जामूति बिहार, बुरला, सम्बलपुर-768018 (उड़ीसा) को भेजेंगे।

अनुसूची
मनोहरपुर ब्लॉक
घाई बी घाटी विस्तार, कोलफील्ड्स
जिला—सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)

सभी अधिकार

(रेखांक सं. : एमसीएल/एमएएमबी/ सीजीएम (कोल प्रोजेक्ट एण्ड प्लानिंग)/मनोहरपुर/00/19 तारीख 28 अप्रैल, 2000)

क्र. सं.	ग्राम	पुलिस थाना और सं.	तहसील/ उप-डिवीजन	जिला/राज्य	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणियां
1.	साहशापुर	हेमगिर/72	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	685.80	संपूर्ण
2.	कुतबागा	हेमगिर/71	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	492.83	संपूर्ण
3.	दारुबागा	हेमगिर/70	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	1341.76	संपूर्ण
4.	मनोहरपुर	हेमगिर/106	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	1433.20	संपूर्ण
5.	परमानंदपुर	हेमगिर/107	हेमगिर	सुन्दरगढ़/उड़ीसा	396.59	संपूर्ण
6.	काठापाली	हेमगिर/108	हेमगिर	सुन्दरगढ़/उड़ीसा	937.76	संपूर्ण
7.	छुमुदासन	हेमगिर/104	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	668.12	संपूर्ण
8.	जाप्ती जंगल	हेमगिर/	हेमगिर	सुन्दर गढ़/उड़ीसा	42.00	संपूर्ण
कुल :					6376.88 (लगभग)	
					या	
					2580.356 हेक्टर (लगभग)	

सीमा वर्णन

- क—ख रेखा बिन्दु “क” से आरंभ होता है जो ग्राम हरिपाशिरा, बिलिजोरी आरक्षित वन और छुमुदासन का त्रिसोमा बिन्दु है। रेखा ग्राम छुमुदासन की उत्तरी-पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा के साथ-साथ और ग्राम मनोहरपुर की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “ख” तक जाती है जो ग्राम मनोहरपुर काठापाली और दुलुंगा का त्रिसोमा बिन्दु है।
- ख—ग—घ बिन्दु “ख” से रेखा ग्राम काठापाली की पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु “ग” तक जाती है। वहां से रेखा ग्राम काठापाली, परमानंदपुर, दारुबागा की पश्चिमी सीमा, ग्राम, कुतबागा की दक्षिणी सीमा और ग्राम साहशापुर की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु “घ” तक जाती है।
- घ—ङ—क बिन्दु “घ” से रेखा, ग्राम साहशापुर, कुतबागा और दारुबागा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “ङ” तक जाती है। इसके पश्चात् रेखा ताप्ती जंगल की पश्चिमी और पूर्वी सीमा, ग्राम दारुबागा और मनोहरपुर की उत्तरी सीमा तथा ग्राम छुमुदासन की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर और पश्चिमी दक्षिण की ओर जाती है और आरंभिक बिन्दु “क” पर मिलती है।

[सं. 43015/7/2000—पी आर आई डब्ल्यू]

एस. कृष्णन, उपा सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 1st January, 2001

S.O. 27 .—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. MCL/SAMB/CGM(CP and P)/Manoharpur/00/19, dated the 28th April, 2000 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Chief General Manager (Coal Project & Planning), Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar, Burla, Sambalpur-768018 (Orissa) or at the office of the Collector and District Magistrate, Angul, Orissa or at the office of the Coal Controller, I, Council House, Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act, to the officer-in-charge/Head of the Department /Revenue/Estate), Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar, Burla, Sambalpur-768018 (Orissa) within ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Manoharpur Block

Ib Valley Extension Coalfield

District Sundargarh (Orissa)

All rights

(Plan bearing No. MCL/SAMB/CGM (Coal Project & Planning)/Manoharpur/00/19 dated the 28th April, 2000)

Sl. No.	Village	Police Station and Number	Tahsil/Sub Division	District/State	Area in Acres	Remarks
1.	Sahashapur	Hemgir/72	Hemgir	Sundargarh/Orissa	685.80	Full
2.	Kutabaga	Hemgir/71	Hemgir	Sundargarh/Orissa	492.83	Full
3.	Darubaga	Hemgir/70	Hemgir	Sundargarh/Orissa	1341.76	Full
4.	Manoharpur	Hemgir/106	Hemgir	Sundargarh/Orissa	1433.20	Full
5.	Paramanandapur	Hemgir/107	Hemgir	Sundargarh/Orissa	396.59	Full
6.	Kathapali	Hemgir/108	Hemgir	Sundargarh/Orissa	937.76	Full
7.	Ghumudasan	Hemgir/104	Hemgir	Sundargarh/Orissa	668.12	Full
8.	Japti Jungle	Hemgir	Hemgir	Sundargarh/Orissa	420.00	Full
					Total 6376.06	
					(Approximately) or	
					2580.356 Hectares	
					(Approximately)	

Boundary description

A—B : The line starts from point 'A' which is the trijunction point of villages Iripashira, Bilijori Reserve Forest and Ghumudasan. It moves along the northern, eastern and southern boundary of village Ghumudasan, eastern boundary of village Manoharpur upto point 'B' which is the trijunction point of villages Manoharpur, Kathapali and Dulunga.

B—C—D : From point 'B' the line proceeds towards south along the eastern and southern boundary of village Kathapali upto point 'C'. From here the line proceeds towards north along the western boundary of village Kathapali, Paramanandapur, Darubaga, southern boundary of village Kutabaga and western boundary of village Sahashapur upto point 'D'.

D—E—A : From point 'D' the line moves towards East along the northern boundary of villages Sahashapur, Kutabaga and Darubaga upto point 'E'. The line then moves towards north and south along the western and eastern boundary of Japti jungle and northern boundary of village Darubaga and Manoharpur and western boundary of village Ghumudasan and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/7/2000-PRIW]

S. KRISHNAN, Dy. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001

का.आ. 28.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के खान और खनिज मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 155, 4 जनवरी, 2000, के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 15 जनवरी, 2000 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में या उस पर के अधिकार (जिमें इनमें इसके पश्चात् उक्त अधिकार कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (i) के अधीन, सभी विलंगनों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे,

और, केन्द्रीय सरकार का यह समझाव हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बिलासपुर (मध्य प्रदेश), जो एक सरकारी कंपनी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है), ऐसे निवेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे अनुदान करने के लिए राजामंद है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि में या उस पर के उक्त अधिकार, तारीख 15 जनवरी, 2000 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएगी, अर्थात् :—

(1) उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर ध्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी सदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी,

(2) उक्त कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों, जैसे धनील भावि की बाबत उपगत सभी व्यय भी उक्त कंपनी वहन करेगी,

(3) उक्त कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति करेगी,

(4) उक्त कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी, और

(5) उक्त सरकारी कंपनी, ऐसे निवेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाए या अधिरोपित की जाए चालन करेगी।

[का.सं. 43015/17/96-एल डब्ल्यू/पी आर आई डब्ल्यू]

एस कृष्णन, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2001

S.O. 28.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Mines and Minerals, Department of Coal Number S. O. 155 dated the 4th January, 2000, in Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated the 15th January, 2000 issued under Sub-Section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said rights) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrance under Sub-section (1) of Section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (Madhya Pradesh), a Government Company, (hereinafter referred to as the Company), is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the said Act, the Central Government, hereby directs that the said rights in or over the land, so vested, shall, with effect from the 15th January, 2000 instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the said Company, subject to the following terms and conditions, namely :—

1. the said Company shall reimburse the Central Government all payment made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
2. a tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Company under condition (I), and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be

borne by the said Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights in or over the said land, so vesting shall also be borne by the said Company;

3. the said Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vesting.
4. the said Company shall have no power to transfer the said lands to any other person without the previous approval of the Central Government; and
5. the said Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[No. 43015/17/96-LW/PRIW]

S. KRISHNAN, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2000

का.आ. 29.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 1956 का 102 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में डा. एम. चन्द्रशेखर शेटी, संख्या 130, प्रथम मुख्य मार्ग, एम. एल. ए. ले आउट आर. टी. नगर, बंगलोर को 16 दिसम्बर, 2000 से राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक के सीनेट द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत निर्वाचित” शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“76 डा. एस. चन्द्रशेखर शेटी, राजीव गांधी स्वास्थ्य संख्या 130, प्रथम मुख्य मार्ग, विज्ञान विश्वविद्यालय” एम. एल. ए. ले आउट बंगलोर

[सं. बी.-11013/23/2000-एम ई (यू जी)]

परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 1st December, 2000

S.O. 29.—Whereas in pursuance of clause (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. S. Chandrashekar Shetty, No. 130, 1st Main Road, M.L.A. Layout R. T. Nagar, Bangalore has been elected by the Senate of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka on 16-10-2000 to be a member of the Medical Council of India with effect from 16th October, 2000.

Now, therefore, in pursuance of the provision of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading, 'Elected under clause (b) of Sub-section (1) of Section 3', the following serial number and entries shall be added, namely :—

“76. Dr. S. Chandrashekar Shetty, Rajiv Gandhi University of Health Sciences”
No. 130,
1st Main Road,
M.L.A. Layout,
Bangalore.

[No. V-11013/23/2000-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2000

का.आ. 30.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में डा. एफ. यू. ग्रहमद, प्रभारी प्राचार्य असम मेडिकल कालेज डिब्रूगढ़ को 28-9-2000 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की सभा द्वारा 28 दिसम्बर, 2000 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत निर्वाचित” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 35 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

35. डा. एफ. यू. ग्रहमद,
प्रभारी प्राचार्य,
असम मेडिकल कालेज,
डिब्रूगढ़।

[सं. बी. 11013/23/2000-एम ई (यू जी)]

पी जी कलाधरन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th December, 2000

S.O. 30.—Whereas in pursuance of clause (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. F. U. Ahmad, Principal Incharge, Assam Medical College, Dibrugarh has been elected by the Court of Dibrugarh University on 28-9-2000 to be a member of the Medical Council of India with effect from 28th September, 2000.

Now, therefore, in pursuance of the provision of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health

number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading, 'Elected under clause (b) of Sub-section (1) of Section 3', for serial number 35 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

35. Dr. F. U. Ahmad Dibrugarh University"
Principal Incharge,
Assam Medical College,
Dibrugarh.

[No. V-11013/22/2000-ME(UG)]

P. G. KALADHRAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2000

का.आ. 31—दंत चिकित्सक अधिनियम (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में एतद्-द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम के भाग-1 में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर की क्रम संख्या 47 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

47. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	मास्टर आफ डेंटल सर्जरी। निम्नलिखित दंत चिकित्सा ग्रहृताएं तभी मान्यताप्राप्त ग्रहृताएं होगी जब ये पी.एम.एन. एम.दंत चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, बागलकोट के स्नातकोत्तर छात्रों को निम्नलिखित विशेषताओं के संबंध में उनके सामने निविष्ट की गई तिथि को या उसके बाद प्रदान की गई हों।	(i) एम. डी. एस. ओरल तथा मैक्सिलोफेसियल सर्जरी (ii) प्रोस्थोडान्टिक्स (राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) बंगलौर
	(i) ओरल तथा मैक्सिलोफेसियल सर्जरी 1,2 5.2000	
	(ii) प्रोस्थोडान्टिक्स 26,28-3-2000	

[सं. बी. 12018/17/2000-पी.एम.एस.]

एस. के राव, निदेशक

New Delhi, the 22nd December, 2000

S.O. 31.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 10 of the Dentists Act (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in part-I of the Schedule to the said Act namely :—

In Part-I of the said Schedule against serial number 47 of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore and the entries relating thereto, the following entries will be added namely :—

1	2	3	4
47. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (RGUOHS), Bangalore.	Master of Dental Surgery. The following dental qualifications shall be a recognized qualification when granted	(i) M.D.S. Oral & Maxillofacial Surgery.	

1

2

3

4

on or after the date indicated against each in respect of following specialities of the P.G. students of PMNM Dental College & Hospital, Bagalkot.

(ii) Prosthodontics.
(RGUOHS), Bangalore.

(i) Oral and Maxillofacial Surgery 1,2-5-2000

(ii) Prosthodontics 26, 28-3-2000.

[No. V-12018/17/2000-PMS]

S. K. RAO, Director

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(राजभाषा अनुभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर, 2000

का.भा. 32.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों की जिसमें 80 प्रतिशत में अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, कर्नाटक परिमंडल बेंगलूर।
महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, डायंगेरे।

[मं. ई. 11016/1/99-(रा. भा.)]

कैलाश दत्ता, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Official Language Section)

New Delhi, the 19th December, 2000

S.O. 32.—In pursuance of rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) rules,

1976 the Central Government hereby notifies following office under the administrative control of Ministry of Communications, Department of Telecommunications where of more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi.

Chief General Manager Telecom
Karnataka Circle, Bangalore.
General Manager Telecom. Office.
Davangere.

[No. E-11016/1/99(O.L.)]

KAILASH DUTTA, Dy. Director

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. भा. 33.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 4) के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :—

1. भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
3. वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

4. गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय, पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा।

नियंत्रण तथा अपील) नियम 1976 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

[सं. ई.-11011/31/88-रा.भा. (का.)]
बलदेव राज, निदेशक (राजभाषा)

1. (1) इन नियमों को अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधित नियम 2000 कहा जाएगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 3rd January, 2001

S.O. 33.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Environment & Forests, the 80% staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi :—

1. Indian Institute of Forest Management, Bhopal, Madhya Pradesh.
2. Directorate of Forest Education, Dehradun.
3. Forest Conservator (Central) Regional Office, Chandigarh.
4. G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora.

[No. E-11011/31/88-OL(I)]
BALDEV RAJ, Director (O.L.)

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर, 27 दिसम्बर, 2000

का. भा. 34 —अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1976 के नियम 4 के साथ मिलाई अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण,

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2 अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1976 में, उप नियम 2 के बाद नियम 12 में निम्नलिखित नियमों को स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“2(क) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं द्वारा की गई जांच, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी न हो, तो जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति असहमति के अपने अन्तिम कारणों, यदि कोई हो, सहित सरकारी कर्मचारी को जारी आरोप-पत्र पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों की एक-एक प्रति उस सरकारी कर्मचारी को प्रेषित करेगा अथवा प्रेषित करवाएगा जिससे (सरकारी कर्मचारी) यदि वह चाहे तो इस बात को ध्यान में रखे बिना कि रिपोर्ट उसके पक्ष में है अथवा नहीं 15 दिनों के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

2(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और उप-नियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले अपने निष्कर्षों को रिकार्ड करेगा।”

[सं. 2/5(1)/98-वी]

बाणी रामचन्द्र, अवर सचिव

फुट नोट —प्रमुख नियमों को दिनांक 1-4-1976 के क. आ. स. 270(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 4-4-1976 को

प्रकाशित किया गया और तदनंतर भिन्नानुसार संशोधित
किया गया —

क्र.सं० अधिसूचना सं. दिनांक पृ.अ. सं. तारीख

1. 2/10(32)/76-I 10-02-1977 780 12-03-1977
2. 2/10(32)/76-I 16-05-1977 2127 25-06-1977
3. 2/10(27)/76-I 01-08-1977 2709 27-08-1977
4. 2/7(5)/77-I 15-02-1978 585 25-02-1978
5. 2/7(5)/77-I 27-05-1978 1780 17-06-1978
6. 2/9(12)/74-II 16-03-1979 1178 07-04-79
7. 9/1(1)/80-III 26-05-1980 1684 21-06-80
8. 9/4(1)/80-III 05-09-1980 2586 27-09-80
9. 9/4(1)/80-III 13-10-1980 3299 29-11-80
10. 9/4(1)/80-III 13-10-1980 3300 29-11-80
11. 9/4(1)/80-III 20-12-1980 215 17-01-81
12. 2/8(1)/81-I 28-08-1981 2592 03-10-81
13. 2/8(1)/81-I 16-07-1982 3113 04-09-82
14. 2/9(1)/83-I(V) 29-07-1985 4280 14-09-85
15. 2/5(1)/85-V 02-01-1986 510 08-02-86
16. 2/9(1)/83-I(V) 02-01-1986 511 08-02-86
17. 2/5(1)/86-V 17-03-1986 1399 29-03-86
18. 2/5(2)/86-V 20-10-1986 3874 15-11-86
19. 2/5(1)/90-VI 01-01-1991 93 09-02-91
20. 2/5(2)/86-VI(VI) (बाल्युम III 15-11-1991 334
01-02-92

21. 2/5(1)/91-VI 23-10-1992 2891 21-11-1992
22. 2/5(1)/95-V 24-03-1995 1029 15-04-95
23. 2/5(1)/91-V 12-10-1995 2856 28-10-95
24. 2/5(1)/91-V 27-03-1996 1241 20-04-96
25. 2/5(1)/95-V 23-12-1997 83 10-01-98
26. 2/5(1)/98-V 30-06-2000 1763 05-08-2000

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 27th December, 2000

S.O. 34—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 509 read with rule 4 of Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules 1976, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Department of Space Employees' (Classification Control and Appeal) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, in Rule 12 after sub rule (2) the following sub-rules shall be inserted namely:

2(A) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority or where the disciplinary authority is not the inquiry authority, a copy of the report of the Inquiry Authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of inquiring authority on any article of charge to the Government servant who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the Government servant.

2(B) The disciplinary authority shall consider the representation, if any, submitted by the Government servant and

record its findings before proceeding further in the matter as specified in sub-rules (3) and (4)."

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[No. 2/5(1)/98-V]

(उर्वरक विभाग)

VANI RAMACHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2000

Foot Note:—Principle Rules were published vide S.O. No. 270(F) dated 1-4-1976 in the Gazette of India (Extra-ordinary) Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1-4-1976 and have been subsequently amended by :—

Sl. No.	Notification No.	Date	S.O. No.	Date
1.	2/10(32)/76-I	10-2-1977	780	12-3-1977
2.	2/10(32)/76-I	16-5-1977	2127	25-6-1977
3.	2/10(27)/76-I	1-8-1977	2709	27-8-1977
4.	2/7(5)/77-I	15-2-1978	585	25-2-1978
5.	2/7(5)/77-I	27-5-1978	1780	17-6-1978
6.	2/9(12)/74-III	16-3-1979	1178	7-4-1979
7.	9/41/80-III	26-5-1980	1684	21-6-1980
8.	9/4(1)/80-III	5-9-1980	2586	27-9-1980
9.	9/4(1)/80-III	13-10-1980	3299	29-11-1980
10.	9/4(1)/80-III	13-10-1980	3300	29-11-1980
11.	9/4(1)/80-III	20-12-1980	215	17-1-1981
12.	2/8(1)/81-I	28-8-1981	2592	3-10-1981
13.	2/8(1)/81-I	16-7-1982	3113	4-9-1982
14.	2/9(1)/83-I(V)	29-7-1985	4280	14-9-1985
15.	2/5(1)/85-V	2-1-1986	510	8-2-1986
16.	2/9(1)/83-I(V)	2-1-1986	511	8-2-1986
17.	2/5(1)/86-V	17-3-1986	1309	29-3-1986
18.	2/5(2)/86-V	20-10-1986	3874	15-11-1986
19.	2/5(1)/90-VI	1-1-1991	99	9-2-1991
20.	2/5(2)/86-V (VI) (Vol. III)	15-11-1991	334	1-2-1992
21.	2/5(1)/91-VII	23-10-1992	2891	21-11-1992
22.	2/5(1)/95-V	24-3-1995	1029	15-4-1995
23.	2/5(1)/91-V	12-10-1995	2856	28-10-1995
24.	2/5(1)/91-V	27-3-1996	1241	20-4-1996
25.	2/5(1)/85-V	23-12-1997	83	10-1-1998
26.	2/5(1)/98-V	30-6-2000	1763	5-8-2000

का.आ. 35.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा "संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग", नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया है, अधिसूचित करती है :—

पारादीप फास्फेट लिमिटेड, निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

[मं. ई-11011/5/93-हिन्दी]

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 12th December, 2000

S.O. 35.—In pursuance of sub rule (4) of the Rule 10 of the Official Language "Use for official purposes of the Union" Rule, 1976 the Central Govt. hereby notifies the following office, under the Administrative Control of Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers, more than 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Paradeep Phosphates Ltd., Corporate Office, Bhubaneswar, Orisa.

[No. E-11011/5/93-Hindi]

NARENDER KUMAR AGGARWAL,

Addl. Industrial Adviser

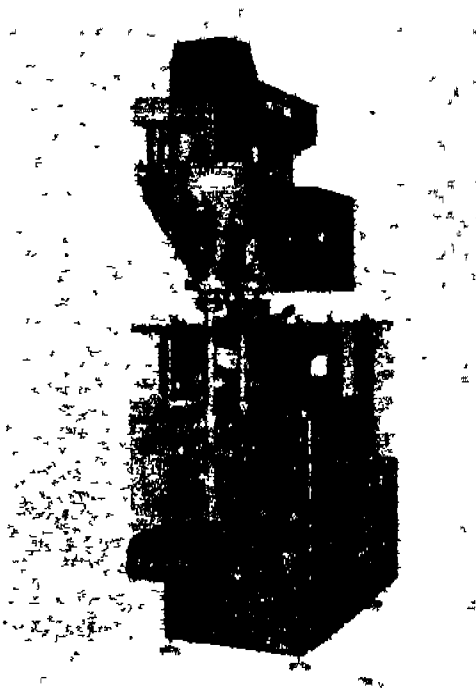
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 36.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तौसरे परन्तुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निम्क्रोम इंडिया लिमिटेड, गेट सं 707, 770, 772, कण्डाला (तालुक), सतारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित स्वचालित तोलन मशीन की बाबत माडल (वर्माभरक-भरण के साथ) माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/162 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



उक्त माडल स्वचालित तोलन मशीन वर्माभरक है। इसकी क्षमता 5 ग्रा से 125 ग्रा. रेंज की है। इसका प्रयोग अमुक्त प्रवाह वाले पदार्थों जैसे दुग्ध चूर्ण, काफी चूर्ण, पिसे हुए मसाले, दन्त मंजन, रासायनिक और भेषजी पाउडर आदि के लिए किया जाता है। इसकी भराई रेंज 60 पाउन्ड प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट और 50 हर्टज तीन फेज की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

[फा सं डब्ल्यू एम-21(95)/98]

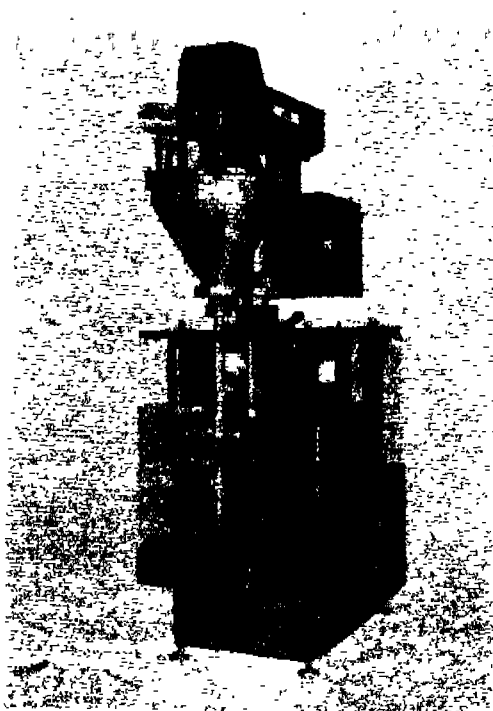
पी ए कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 36.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model in respect of automatic weighing machine (Wing with Auger filler) of model (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd., Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluk), Satra (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/162;



The model is a Automatic weighing machine (Auger filler). The capacity range is for 5g to 125g. It is used for non-free flowing products such as milk powder, coffee powder, ground spices, tooth powder, chemical and Pharmaceutical powder, etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instrument operates on three phase AC 440 volts, 50 Hz.

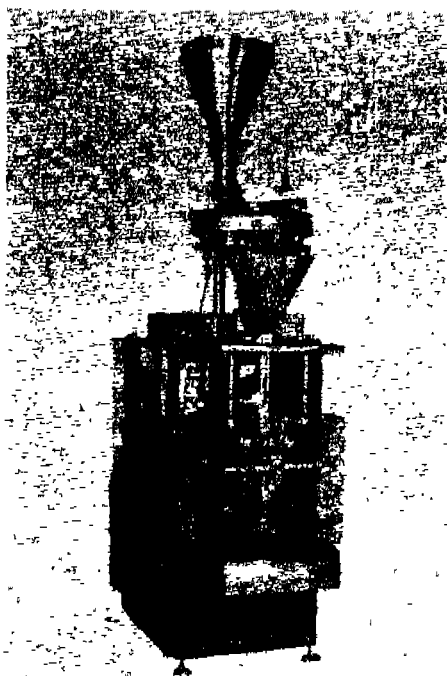
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 37.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुक), सतारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा स्वचालित, तोलन मशीन की बाबत माडल (कप भरण के साथ) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन विह्न आई एन डी/09/2000/163 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन है (कप भरक भरण के साथ) क्षमता की रेंज 5 ग्रा. से 125 ग्रा. के लिए है। इसका प्रयोग मुक्त प्रवाह वाले पदार्थों के लिए किया जाता है जैसे चाय, तत्काल तैयार काफी, दालें, अनाज तथा रासायनिक और भेषजीम पाउडर आदि। भराई रेंज 60 पाउन्ड प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट और 50 हर्टज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

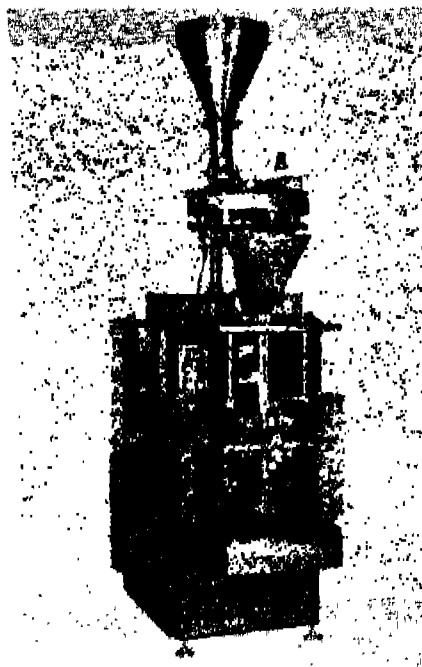
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 37.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic weighing machine (wing with cup filler) of model (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd., Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluk), Satra (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/163;



The Model is a Automatic weighing machine (wing with cup filler). The capacity range is for 5g to 125g. It is used for free following products such as tea, instant coffee, pulses, grains, detergents, chemicals and pharmaceutical powder etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instrument operates on three phase AC 440 V, 50 Hz.

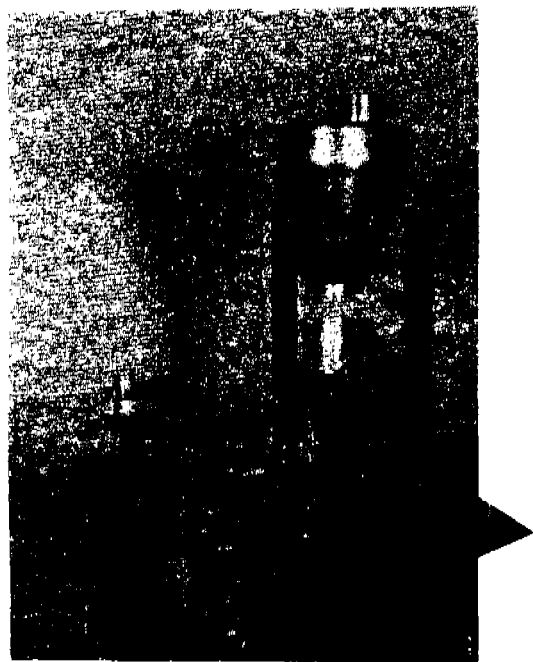
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 38.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तौसरे परंतुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्त्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुका), सातारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा आवरित करने वाली बी.डी. 16/32 का स्वचालित तोलन मशीन (इलेक्ट्रॉनिक तोल भरक) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/164 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन (इलेक्ट्रॉनिक तोल भरक) ऐसी तोलन प्रणाली है जिसमें स्वतः सूचक यंत्र रचना के प्रभाव से स्वचालित भरण, पूर्व नियत भार का वजन होता है, पूर्व नियत वजन के पाउच भर कर, पाउच सोल करती है और वितरण कर देती है। इसकी क्षमता 5 ग्रा. से 5000 ग्रा. रेंज की है। इसे मुक्त प्रवाहित होने वाले, न चिपकने वाले शुल्क रहित उत्पाद अर्थात् चाय, आलू, चिप, मिठाइयां आदि में प्रयोग किया जाता है। उपकरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

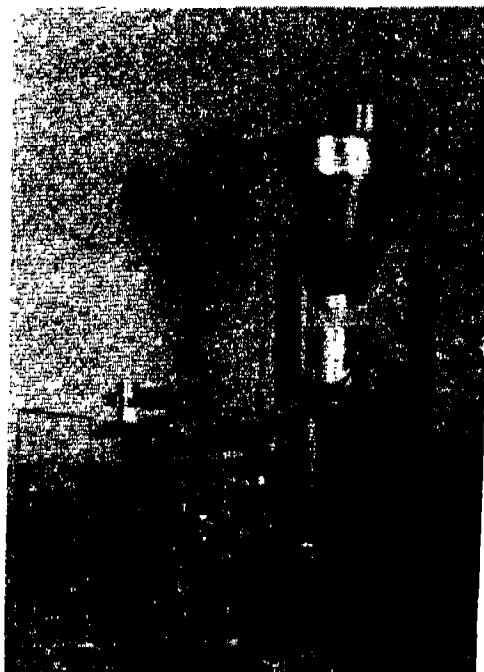
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 38.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic weighing machine (Electronic weigh filler) model of Autowrap BD 8/20 and BD 16/32 (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd. Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluka), Satara (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/164;



The model is a Automatic weighing machine (electronic weigh filler) is weighing system in which self-indicating mechanism effects an automatic feed, weights given loads, fills the pouch for a pre-set weight, seals the pouch and then dispenses. The capacity range is for 5g to 5000g. It is used for free flowing, non-sticky, non-duty products like tea, potato chips, confectionery, etc. The instruments operates on three phase AC 440 V. 50 Hz.

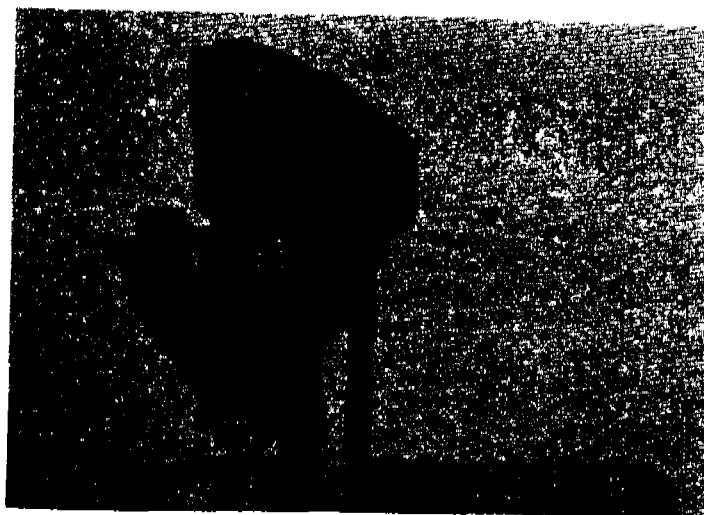
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ.39.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तीसरे परंतुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्कोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुका), सातारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित स्वचालित आवरित करने वाली बी.डी. 8/20 और बी.डी.16/32 वाली तोलन मशीन (वर्मा भरक) के माडल का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई'एन डी/09/2000/165 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन (वर्मा भरक सहित स्वतः आवरित करने वाली) ऐसी तोलन प्रणाली है जिसमें स्वतः सूचक यंत्र रचना के प्रभाव से स्वचालित भरण क्रिया दिए गए भार का लदान होता है, यह पूर्व नियत वजन के पाउन्स भरती है, पाउन्स सील करती है और आगे कर देती है। इसकी क्षमता 50 ग्रा. से 5000 ग्रा. तक की रेंज है। यह अमुक्त उत्पादों अर्थात् दुग्ध पाउडर, भेषजी पाउडर आदि के लिए प्रयोग की जाती है। भरने की रेंज 60 पाउन्स प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

[पत्र. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विभाग

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 39.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic volumetric filling and packing machine (Augar filler) model of Autowrap BD 8/20 and BD 16/32 (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd. Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluka), Satara (District), Maharashtra, and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/165,



The model is a Automatic weighing machine (autowrap with augur filler) is weighing system in which self-indicating mechanism effects an automatic feed, weights given loads, fills the pouch for a pre-set weight, seals the pouch and then dispenses. The capacity range is for 50g to 5000g. It is used for non-free flowing products like milk powder, instant coffee, ground spices, tooth-powder, pharmaceutical powder etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instruments operates on three phase AC 440 V 50 Hz.

[F No W.M.-21(95)/98]

P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

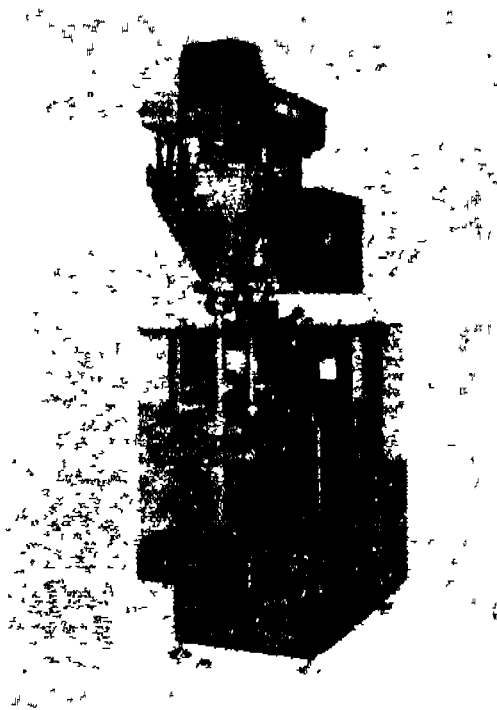
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 36.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तिसरे परन्तुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्क्रोम इंडिया लिमिटेड, गेट स 707, 770, 772, कण्डाला (तालुक), सतारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित स्वचालित तोलन मशीन की यावत माडल (वर्माभरक-भरण के साथ) माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2000/162 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



उक्त माडल स्वचालित तोलन मशीन वर्माभरक है। इसकी क्षमता 5 ग्रा. से 125 ग्रा. रेंज की है। इसका प्रयोग अमुक्त प्रवाह वाले पदार्थों जैसे दुग्ध चूर्ण, काफी चूर्ण, पिसे हुए मसाले, दन्त मंजन, रासायनिक और भेषजी पाउडर आदि के लिए किया जाता है। इसकी भारी रेंज 60 पाउन्ड प्रति मिनिट है। उपकरण 440 वोल्ट और 50 हर्टज तीन फेज की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

[फा सं. डब्ल्यू. एम -21(95)/98]

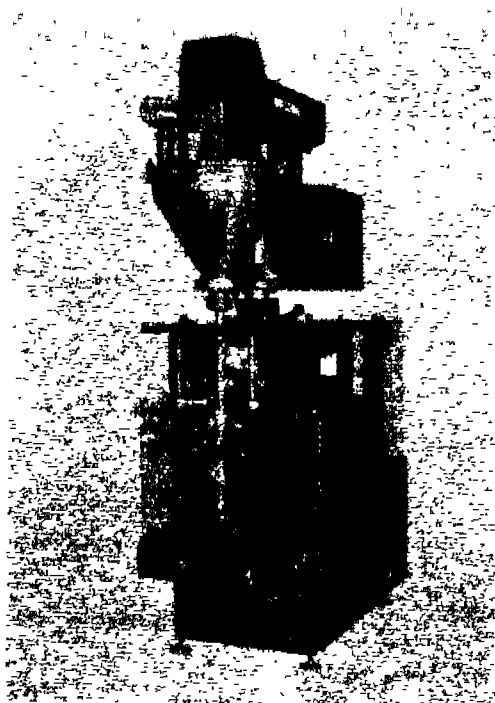
पी ए कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 36.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model in respect of automatic weighing machine (Wing with Auger filler) of model (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd., Gate No 707, 770, 772, Kandala (Taluk), Satra (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/162;



The model is a Automatic weighing machine (Auger filler) The capacity range is for 5g to 125g. It is used for non-free flowing products such as milk powder, coffee powder, ground spices, tooth powder, chemical and Pharmaceutical powder, etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instruments operates on three phase AC 440 volts, 50 Hz.

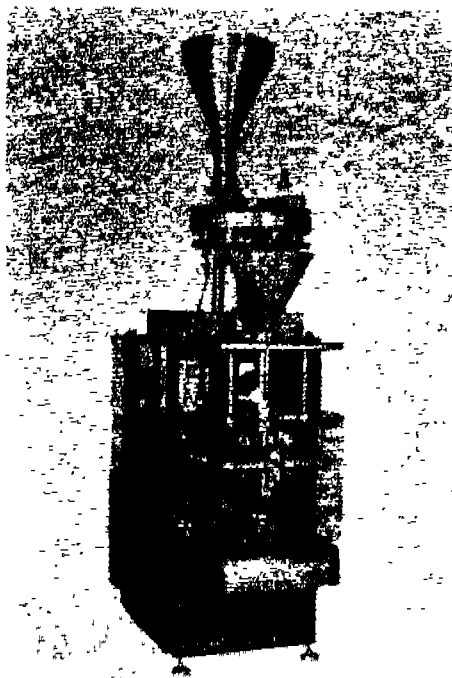
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 37.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्त्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुक), सतारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा स्वचालित, तोलन मशीन की बाबत माडल (कप भरण के साथ) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/163 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन है (कप भरक भरण के साथ) क्षमता की रेंज 5 ग्रा. से 125 ग्रा. के लिए है। इसका प्रयोग मुक्त प्रवाह वाले पदार्थों के लिए किया जाता है जैसे चाय, तत्काल तैयार काफी, दालें, अनाज तथा रासायनिक और भेषजीम पाउडर आदि। भारी रेंज 60 पाउण्ड प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट और 50 हर्टज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

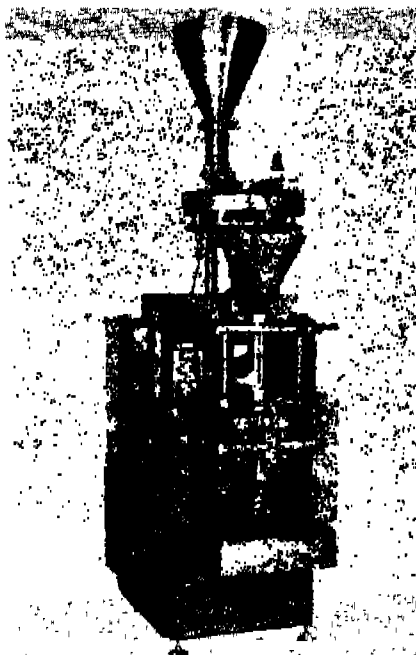
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 37.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic weighing machine (wing with cup filler) of model (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd., Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluk), Satra (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/163;



The Model is a Automatic weighing machine (wing with cup filler). The capacity range is for 5g to 125g. It is used for free following products such as tea, instant coffee, pulses, grains, detergents, chemicals and pharmaceutical powder etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instrument operates on three phase AC 440 V, 50 Hz.

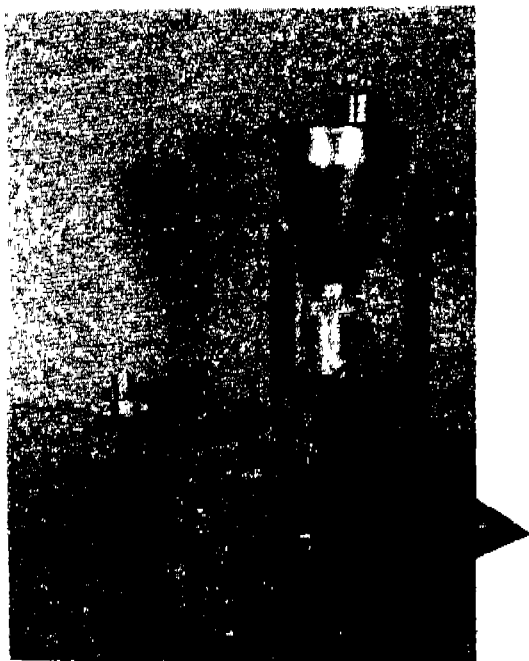
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 38.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मापक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मापक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तीसरे परंतुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निक्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुका), सातारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा आवरित करने वाली बी.डी. 16/32 का स्वचालित तोलन मशीन (इलेक्ट्रॉनिक तोल भरक) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/164 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन (इलेक्ट्रॉनिक तोल भरक) ऐसी तोलन प्रणाली है जिसमें स्वतः सूक्ष्म यंत्र रचना के प्रभाव से स्वचालित भरण, पूर्ण नियत भार का वजन होता है, पूर्ण नियत वजन के पाउन्ड भर कर, पाउन्ड सोल करती है और वितरण कर देती है। इसकी क्षमता 5 ग्रा. से 5000 ग्रा. रेंज की है। इसे मुक्त प्रवाहित होने वाले, न चिपकने वाले शुल्क रहित उत्पाद अर्थात् चाय, आलू, चिप, मिठाइयां आदि में प्रयोग किया जाता है। उपकरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

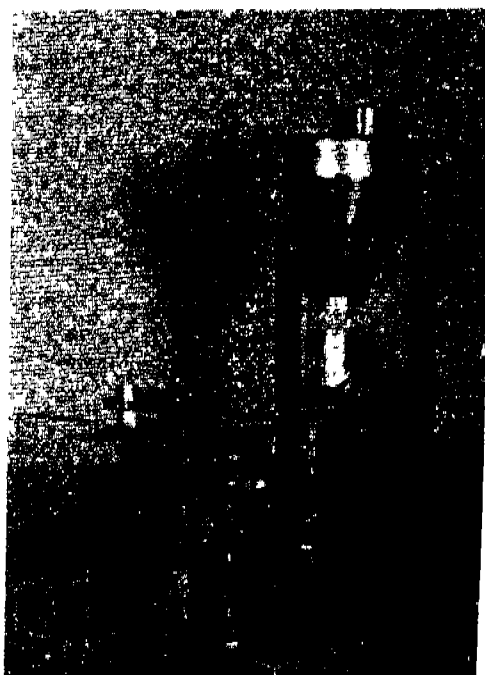
[फ़. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 38.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic weighing machine (Electronic weigh filler) model of Autowrap BD 8/20 and BD 16/32 (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd. Gate No 707, 770, 772, Kandala (Taluka), Satara (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/164;



The model is a Automatic weighing machine (electronic weigh filler) is weighing system in which self-indicating mechanism effects an automatic feed, weights given loads, fills the pouch for a pre-set weight, seals the pouch and then dispenses. The capacity range is for 5g to 5000g. It is used for free flowing, non-sticky, non-duty products like tea, potato chips, confectionery, etc. The instruments operates on three phase AC 440 V 50 Hz

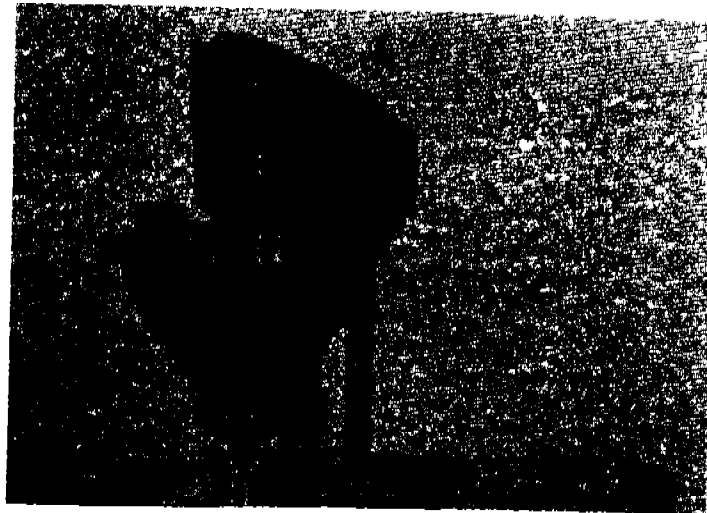
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ.39.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तीसरे परंतुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मिक्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772, काण्डला (तालुका), सातारा जिला, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित स्वचालित आवरित करने वाली बी.डी. 8/20 और बी.डी. 16/32 वाली तोलन मशीन (वर्मा भरक) के माडल का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/2000/165 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन (वर्मा भरक सहित स्वतः आवरित करने वाली) ऐसी तोलन प्रणाली है जिसमें स्वतः सूचक यंत्र रचना के प्रभाव से स्वचालित भरण क्रिया दिए गए भार का लदान होता है, यह पूर्व नियत वजन के पाउन्स भरती है, पाउन्स सील करती है और आगे कर देती है। इसकी क्षमता 50 ग्रा. से 5000 ग्रा. तक की रेंज है। यह अमुक्त उत्पादों अर्थात् दुग्ध पाउडर, भेषजी पाउडर आदि के लिए प्रयोग की जाती है। भरने की रेंज 60 पाउन्स प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

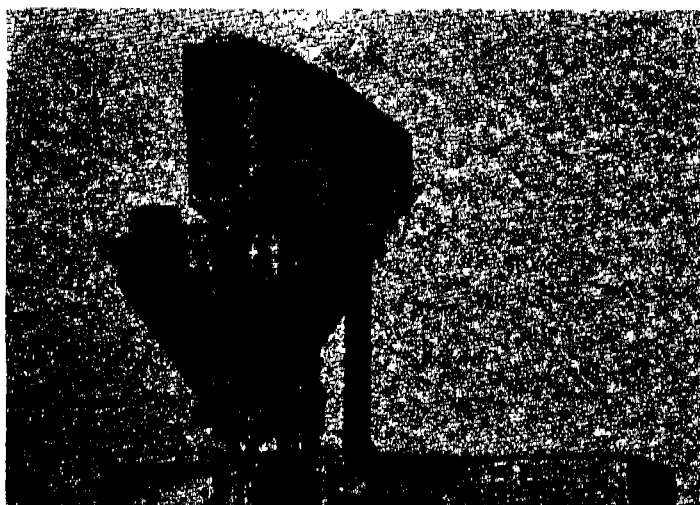
[पत्र. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 39.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic volumetric filling and packing machine (Augar filler) model of Autowrap BD 8/20 and BD 16/32 (herein referred to as model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd. Gate No. 707, 770, 772, Kandala (Taluka), Satara (District), Maharashtra, and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/165;



The model is a Automatic weighing machine (autowrap with augur filler) is weighing system in which self-indicating mechanism effects an automatic feed, weights given loads, fills the pouch for a pre-set weight, seals the pouch and then dispenses. The capacity range is for 50g to 5000g. It is used for non-free flowing products like milk powder, instant coffee, ground spices, tooth-powder, pharmaceutical powder etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instruments operates on three phase AC 440 V. 50 Hz.

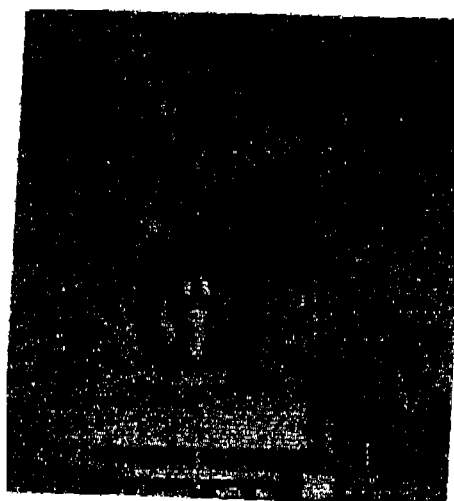
[F. No. W.M.-21(95)/98]

P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 40.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के तीसरे परंतुक और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स निग्रोम इंडिया लि., गेट सं. 707, 770, 772 काण्डला (तालुका), सेतारा (जिला), महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित आयतनी भरक और पैकिंग मशीन (कप भरक) के स्वतः आवरित बी डी 8/20 और बी डी 16/32 के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/166 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन कप भरक स्वतः आवरित करने वाली के साथ आयतनी भरण प्रणाली है जिसमें स्वतः सूचक यंत्र रचना के प्रभाव से स्वचालित भरण क्रिया, दिए गए भार का वजन होता है। यह पूर्व निर्धारित तोल का पाउच भरक कप पाउच सील करती है और वितरित करती है। क्षमता 2 ग्रा. से 500 ग्रा. रेंज की है। इसे मुक्त प्रवाह उत्पादों अर्थात् चाय, मसाले, चोनी, चावल, नमक, दाने, डिटरजेंट आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। भरने की रेंज 60 पाउच प्रति मिनट है। उपकरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तीन फेस की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है।

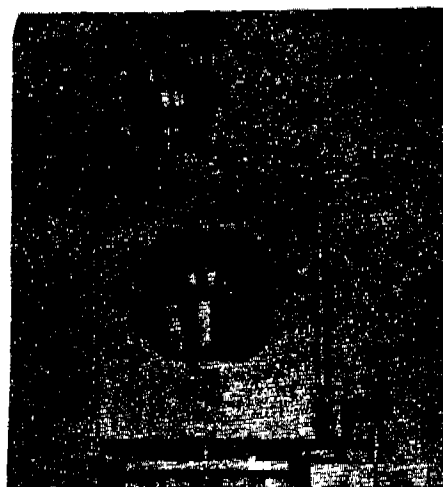
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(95)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 40.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model in respect of automatic, volumetric filling and packing machine (Cup Filler) model of Autowrap BD 8/20 and BD 16/32 series (herein referred to model) manufactured by M/s. Nichrome India Ltd., Gate No 707, 770, 772, Kandala (Taluka), Satara (District), Maharashtra and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/166;



The Model is a Automatic weighing machine (autowrap with cup filler) is volumetric filling systems in which self-indicating mechanism effects an automatic feed, weights given loads, fills the pouch for a pre-set weight, seals the pouch and then dispenses. The capacity range is for 2 g to 500 g. It is used for free flowing products like tea, spices, sugar, rice, salt, granules, detergents, etc. The range of filling is 60 pouches per minute. The instruments operates on three phase AC 440 V. 50 Hz.

[F. No. W.M.-21(95)/98]

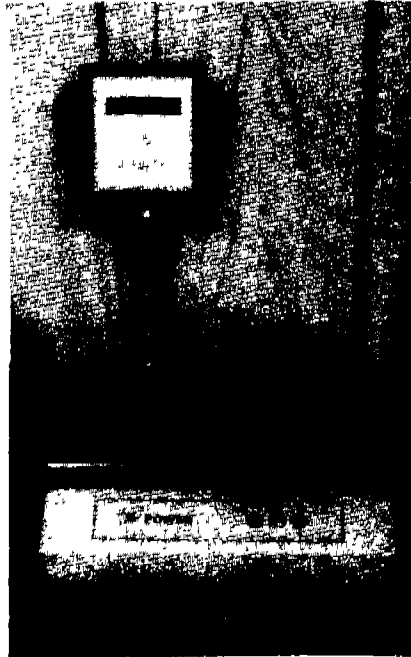
P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 41.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा माडल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पावर स्केल, 2, पंचाल एस्टेट, ग्रीन काम्पलैक्स के समीप, रीटा नगर, वास्त्राल रोड, अमराईवाडी, अहमदाबाद-380026 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाली “पी एस टी” शृंखला के स्वतःसूचक, अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन (टेबल टॉप प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “पावर” है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन बिह्न आई एन डी/09/2000/108 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

इस मॉडल (आकृति देखें) 10 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता और 50 ग्रा. की न्यूनतम क्षमता का तोलन उपकरण है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी शृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे, जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल (एन) की संख्या 1,00,000 से कम या उसके बराबर है (एन \leq 1,00,000) तथा जिसका “ई” मान 1×10^{-6} , 2×10^{-6} और 5×10^{-6} है, जहाँ के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(128)/98]

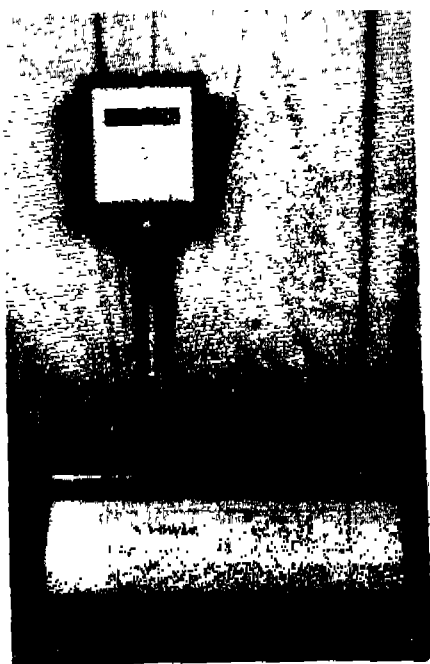
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 41.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating, non-automatic, (Table Top Type) weighing instrument with digital indication of 'PST' series belonging to high accuracy (Accuracy Class II) and with brand name "POWER" (hereinafter referred to as the model), of manufactured by M/s. Power Scale, 2 Panchal Estate, Near Green Complex, Rita Nagar, Vastral Road, Amraiwadi, Ahmedabad -380 026 and which is assigned the approval mark IND/09/2000/108;

The said model (figure given) is weighing instrument with a maximum capacity of 10 kg. and minimum capacity of 10 g. The verification scale interval (e) is 1 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply;



And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of same design with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval (n) less than or equal to 1,00,000 ($\leq 1,00,000$) and with 'e' value to 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. W.M.-21(128)/98]

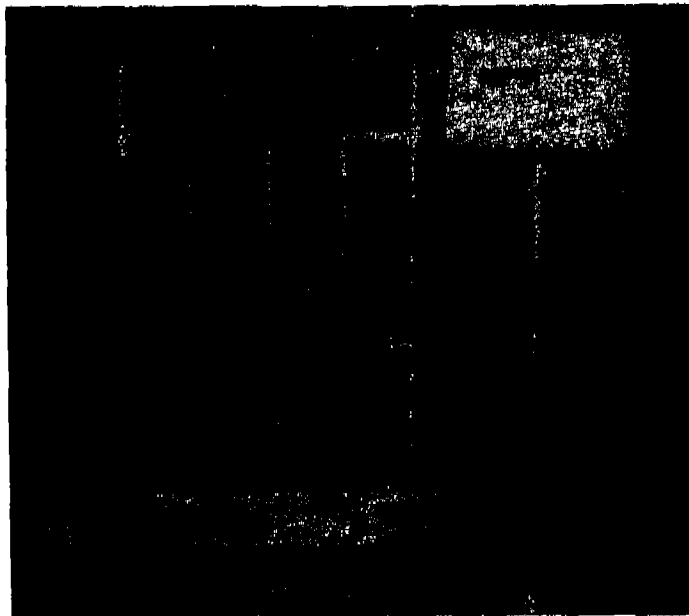
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

का. आ. 42.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा माडल अनुमोदन और परीक्षण के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पावर स्केल, 2, पञ्चाल एस्टेट, ग्रीन काम्पलैक्स के समीप, रीटा नगर, वास्त्राल रोड, अमराईवाडी, अहमदाबाद-380026 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाली "पी एस टी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित स्वतः सूचक, अस्वचासित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "पावर" है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन निम्न आई एम डी/09/2000/109 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

इस मॉडल (आकृति देखें) 60 कि ग्रा अधिकतम क्षमता और 200 ग्रा की न्यूनतम क्षमता का तोलन उपकरण है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) मान 10 ग्रा है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक, आन्तरिक तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाले ऐसे उपकरण भी होंगे, जिनकी अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनको विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल (एन) की संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है (एन \leq 10,000) तथा जिसका "ई" मान 1×10^{-5} , 2×10^{-5} और 5×10^{-5} है, जहाँ के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा सं डब्ल्यू एम -21(128)/98]

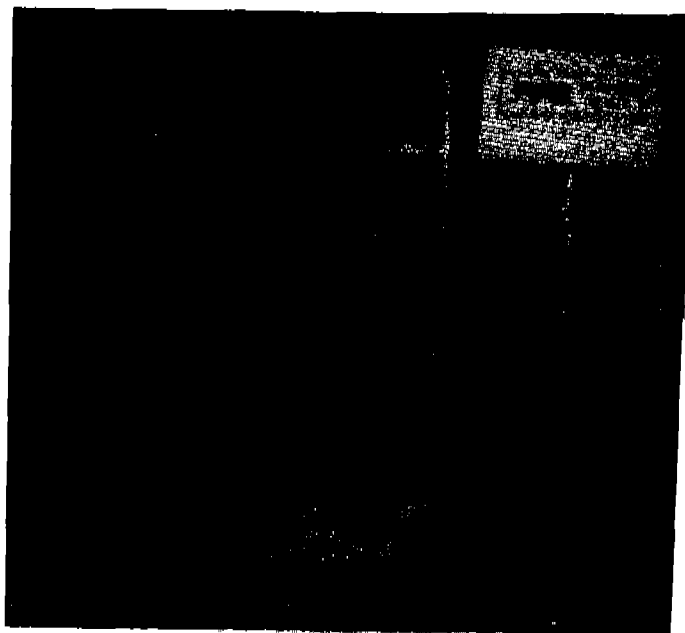
पी ए कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 3rd January, 2001

S. O. 42.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating, non-automatic, (Platform type) weighing instrument with digital indication of 'PST' series belonging to medium accuracy (Accuracy class III) and with brand name "Power" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s. Power Scale, 2 Panchal Estate, Near Green Complex, Rata Nagar, Vastral Road, Amraiwadi, Ahmedabad -380026 and which is assigned the approval mark IND/09/2000/109;

The said model (figure given) is weighing instrument with a maximum capacity of 60 kg. and minimum capacity of 200 g. The verification scale interval (e) is 10 g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply ;



And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity up to 5 tonne with number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ($n \leq 10,000$) and with 'e' value to 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model have been manufactured.

[F. No. W.M.-21(128)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 43.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसके साथ राष्ट्रीय बाट और माप प्रयोगशाला, व्यापार और उद्योग विभाग, मिडिल सेक्स, इंग्लैंड द्वारा मॉडल के अनुमोदन और परीक्षण परीणाम, मंजूरी और अनुमोदन भी है, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) और (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इंडियन एंडमिट्रियल मशीन्स, सं. 22 चौथा, "सी" मुख्य और विस्तार, महालक्ष्मी, ले आउट, बंगलौर-560086 द्वारा विनिर्मित "50 बी एम 01" श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित स्वचालित तोलन उपकरण के माडल (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन बिह्न आई एन डी/09/2000/134 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



यह माडल स्वतः क्रिय यांत्रिकत्व जिसका प्रभाव पूर्व निर्धारित मात्रा में पदार्थ की तोल और उसकी बोरो में भराई और इलेक्ट्रानिक सूचन के द्वारा कुल निकाले गए बोरो का कुल संख्यांक भी सूचित करने सहित स्वचालित तोलन मशीन का है। मशीन जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के मध्य और मशीन का उत्पादन 3-20 भराई प्रति मिनट है जो कि पदार्थ के परिणाम, घनत्व, प्रकृति और उत्पाद की मात्रा पर निर्भर होगी। यह मुक्त प्रवाह के ठोस उत्पादों जैसे चाय, मसाले, खाद, रसायन, प्लास्टिक, चिप्स, खाद्यान्न, चीनी, पशुओं के चारे आदि की भराई के लिए है। यह 440 वोल्ट 2 किलो वाट प्रति घण्टा, 50 हर्ट्ज तीन फेज की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करती है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(19)/2000]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 43.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, along with the model approval and test results, granted and approved by the National Weights and Measures Laboratory, Department of Trade and Industry, Middlesex, England is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model in respect of automatic weighing machine with digital indication of model 50—BM—01 series (herein referred to as the model), manufactured by M/s. Indian Industrial Machines, No. 22, 4th "C" Main, Further Extension, Mahalakshmi layout, Bangalore, 560086 and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/134,

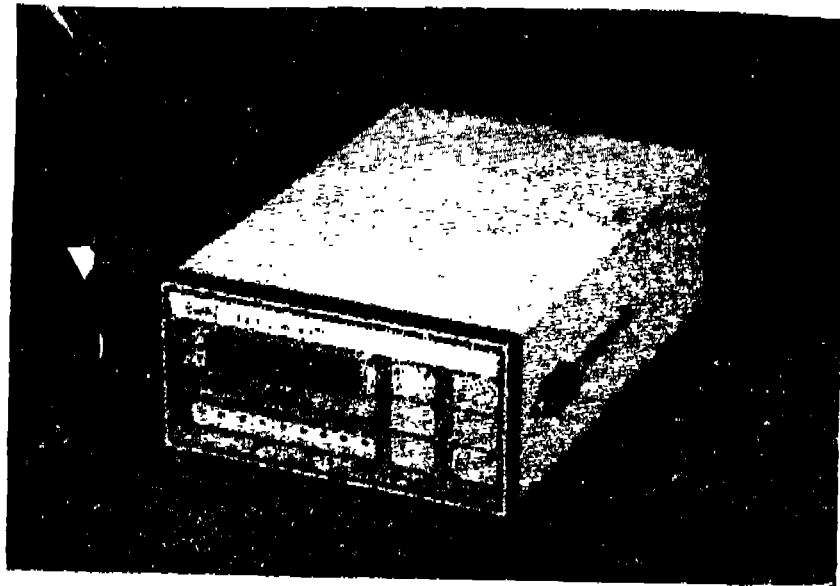


The said model is a automatic weighing machine with a self acting mechanism which effects an automatic feed, weighs pre-set quantity of material and fills into the bag and acts indicates the total number of bags discharged through an electronic indicator. The machine has maximum capacity ranging from 10 kg to 100 kg and the output of the machine is 3-20 fills per minute depending on the bulk density of the material, nature and quantity of the products. It fills free flowing solid products such as tea, spices, fertilizers, chemicals, plastic chips cereals, sugar, animal feeds, etc. It operates on three phase AC 440 V-2Kw/h 50 Hz.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 44.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसके साथ राष्ट्रीय बाट और माप प्रयोगशाला, व्यापार और उद्योग विभाग, मिडिल सेक्स, इंग्लैंड की मॉडल के अनुमोदन और परीक्षण परिणाम, मंजूरी और अनुमोदन भी है, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) और (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स. इंडियन इंडस्ट्रियल मशीन्स, सं. 22 चौथा, "सी" मुख्य और विस्तार, महालक्ष्मी, से आउट, बंगलौर-560086 द्वारा विनिर्मित "डिजिकाम 2000" माडल के अंकीय सूचन सहित स्वतःसूचक अस्वचालित तोलन मशीन (हूपर/टंकी/खत प्रकार) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/135 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



यह माडल स्वचालित तोलन मशीन (टंकी/हाइलो/हूपर प्रकार) का है जिसमें भारग्राही टंकी/हाइलो/हूपर के रूप में है। मशीन लटकते हुए आधानों या एक या अधिक भार सेलों के समर्थन से या मुक्त प्रवाह युक्त ठोस पदार्थों का भरण स्वतः क्रिया यंत्रिकत्व प्रभाव का तोलन आधान के उपयोग के लिए है। सात खंडीय प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एल ई डी) प्रदर्श द्वारा तोलन परिणाम उपदर्शित करता है, स्थापन बिन्दु उडान मध्य, अल्पत्रमांक, दशमलव बिन्दु आदि के भरण बिन्दुओं को दर्ज करने के लिए डिब्बी पेड का प्रबंध किया गया है। भरण और विसर्जन के नियंत्रण के लिए अंकीय निवेश और अंक रूप निर्गम का प्रबंध किया गया है। मशीन की अधिकतम तोलन क्षमता 25 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम है। यह मुक्त प्रवाह के ठोस उत्पादों जैसे चाय, मसाले, खाद, रसायन, प्लास्टिक, चिप्स, खाद्यान्न, चीनी, पशुओं के चारे, उसी तरह द्रव के उपयोग के लिए है। यह 440 वोल्ट—2 किलोवाट प्रतिघण्टा, 50 हर्ट्ज तीन फेज की प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करती है।

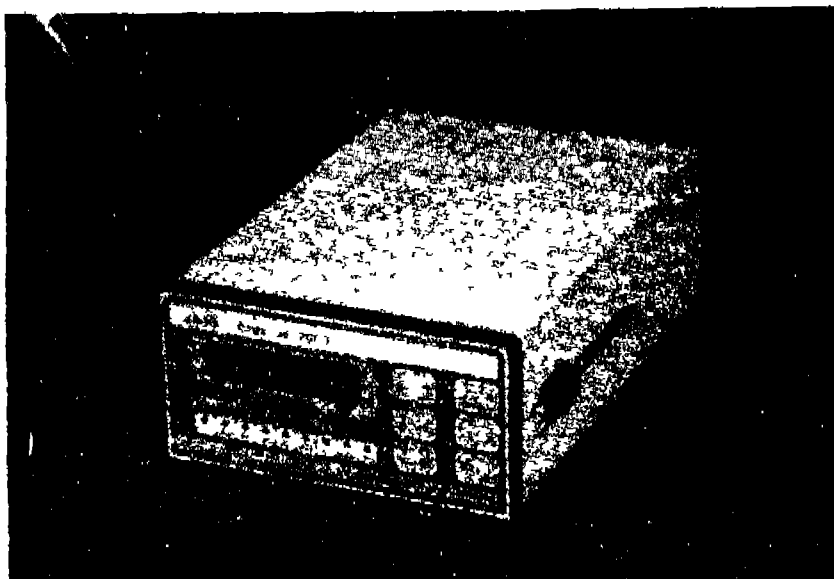
[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(19)/2000]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 44.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, along with the model approval and test results, granted and approved by the National Weights and Measures Laboratory, Department of Trade and Industry, Middlesex, England is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) and sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model in respect of automatic weighing machine with digital indication (hooper/tank/silo type) of "Digicon 2000" series (herein referred to as model), manufactured by M/s Indian Industrial Machines, No 22, 4th "C" Main, Further Extension, Mahalakshmi layout, Bangalore-560086 and which is assigned the approval of Model mark IND/09/2000/135,



The said model is an automatic weighing machine (tank/silo/hooper type) having a load receptor in the form of tank/silo/hooper. The machine is used for weighing and discharging of more than one material from the containers suspended from or supported by one or more loadcells and having a self-acting mechanism to effect the feeding of free flowing solid materials or liquid to the weighing container. The results of the indicator are given by using seven segment (LED) Light emitting Diode display. A membrane keypad is provided for entering set points, in-flight, least count, decimal point, etc. Digital inputs and outputs are provided for feeder and discharge controls. The machine has a maximum capacity weighing from 25 kg to 5000 kg. It is used for filling free flowing solid products such as tea, spices, fertilizers, chemicals, plastic chips, cereals, sugar, animal feeds, as well as liquids. It works on three phase AC 440 V-2Kw/h 50 Hz.

[F No WM -21(19)/2000]

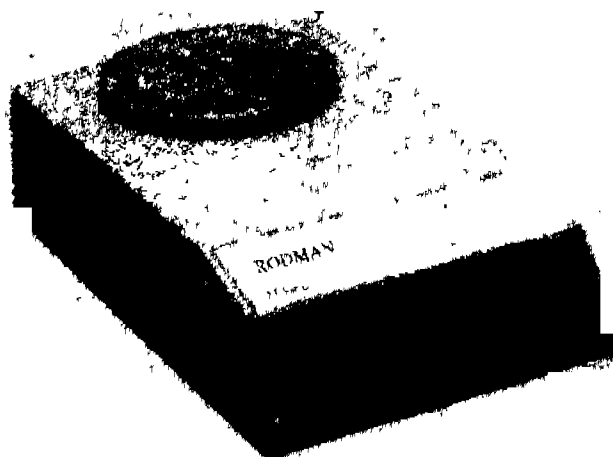
P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

क्रा. आ. 45.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रोडमैन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 8336, 31 उजागर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, डब्ल्यू.टी.पी. रोड देआनार, मुम्बई-400088 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले एम श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित स्वतःसूचक अस्वचालित इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरण (मेजतल प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम रोडमैन है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/167 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

यह माडल (आकृति देखें) जिसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 मिलीग्राम प्रकार का तोलन उपकरण है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 मिलीग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही घृताकार जिसका व्यास 100 मि.मी. है। प्रकाश उत्सर्जक प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 220 वोल्ट और 50 हर्टज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है;



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे उपकरण भी होंगे, जिनकी अधिकतम क्षमता 50 किलोग्राम तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान के अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 1,00,000 से कम या उसके बराबर है (एन \leq 1,00,000) तथा जिसका "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ और $5 \times 10^*$ है, जिसमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(97)/2000]

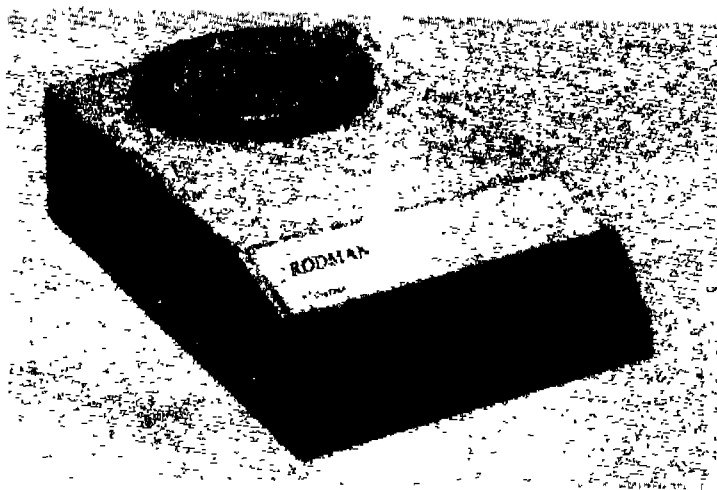
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 45.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating, non-automatic, (Table Top Type) weighing instrument with digital indication of "M" series of High accuracy (Accuracy Class II) and with brand name "RODMAN" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s Rodman Technologies Pvt. Ltd, P.O. Box 8336, 31 Ujagar Industrial Estate, W.T.P Road, Deonar, Mumbai-400 088 and which is assigned the approval mark IND/09/2000/167;

The said model (see figure) is a weighing instrument with a maximum capacity of 300g. and minimum capacity of 200 mg. The verification scale interval (e) is 10mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of circular dia of 100 millimeter. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply ;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of same series with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval (n) less than or equal to 1,00,000 ($n \leq 1,00,000$) and with 'e' value to 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. W.M.-21(97)/2000]

P A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 46.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एलप्रो इंजीनियर्स, 4 भूतल शुभलक्ष्मी काम्पलैक्स, शंघवी हाई स्कूल के सामने, नारनपुरा, अहमदाबाद—380013 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग III) वाले “डिजिटोला” श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित, स्वतः सूचक, अस्यचालित तोलन उपकरण (टेबलटॉप प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “डिजिटोला” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/175 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

यह माडल (आकृति दी गई है) अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 250 × 250 मि. मी. हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है;



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के, ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे, जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान के अन्तराल (एन) की संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है ($एन \leq 10,000$) तथा जिसका “ई” मान 1×10^{-6} , 2×10^{-6} और 5×10^{-6} है, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(62)/2000]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 46.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, (table top type) weighing instrument with digital indication of "Digitoola" series of Medium accuracy (Accuracy class III) and with brand name "Digitoola" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Elpro Engineers, 4 Ground Floor, Subhalaxmi Complex, Opp : Sanghavi High School, Naranpura, Ahmedabad-380 013 and which is assigned the approval mark IND/09/2000/175;

The said model (figure given) is a weighing instrument with a maximum capacity of 20 kg. and minimum capacity of 40 g. The verification scale interval (e) is 2 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of side 250 × 250 millimeter. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz, alternate current power supply ;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ($n \leq 10,000$) and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[No. W.M.-21(62)/2000]

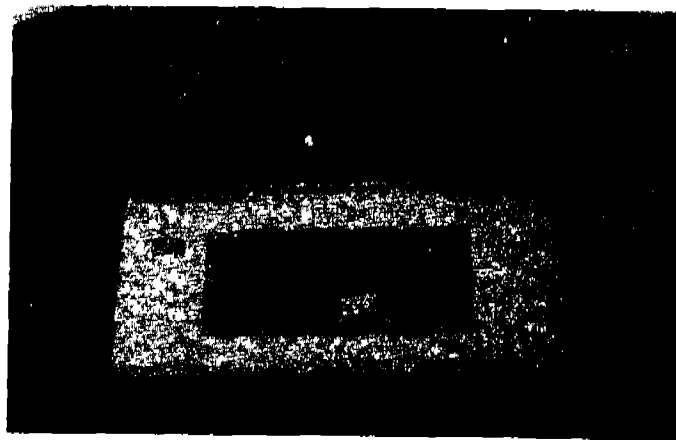
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 47.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स यूरेका वेईंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गाला सं. 107, विशाल इंडस्ट्रियल एस्टेट, कार्यालय : गोददेव मार्ग, गैस गोदाम के समीप, सिन्डीकेट बैंक के सामने, आर्यभट्ट (पूर्व) थाणे (जिला) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग III) वाले "ई डब्ल्यू पी" श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित, स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यूरेका" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/172 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है.

यह माडल (आकृति दी गई है) अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्रा और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। सत्पादन मापमान अन्तराल (ई) मान 10 ग्रा. है। इसमें एक आघेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आघेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 500 × 500 मि. मी. हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है,



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्पादन मापमान के अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है (एन \leq 10,000) तथा जिसका "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ और $5 \times 10^*$ है, जिनमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21(111)/2000]

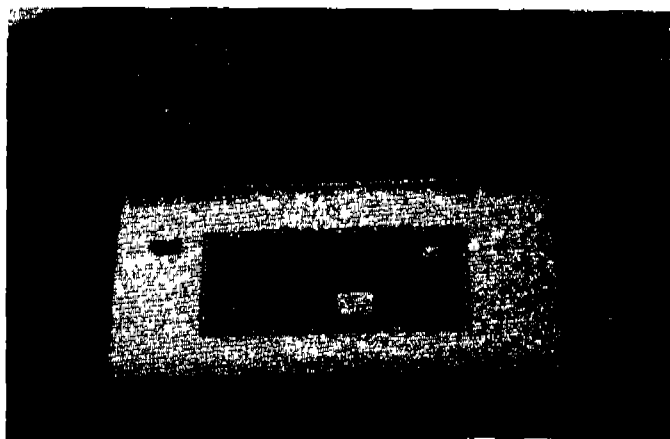
पी ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 47.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, (table top type) weighing instrument with digital indication of "EWT" series of High accuracy (Accuracy class II) and with brand name "Eureka" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s. Eureka Weighing Systems Private Limited, Gala No. 107, Vishal Industrial Estate, Off Goddeo Road, Near Gas Godown, Opp Syndicate Bank, Bhayandar (East) Thane (District) and which is assigned the approval mark IND/09/2000/171;

The said model (figure given) is a weighing instrument with a maximum capacity of 1 kg. and minimum capacity of 5 g. The verification scale interval (e) is 100 mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of side 275×275 millimeter. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply,



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument similar accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ($n \leq 10,000$) and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured

[No. W.M.-21(111)/2000]

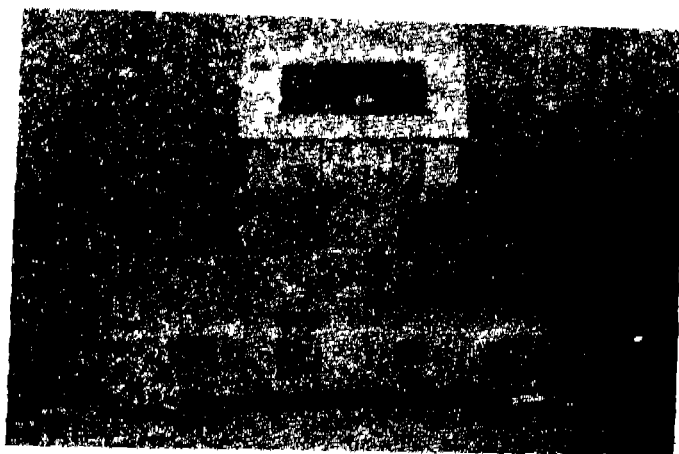
P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 48.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स यूरेका जेईग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड गान्धी मार्ग 107 विशाल इंडस्ट्रियल एस्टेट, कार्यालय गोददेव मार्ग गैस गोदाम के समीप, सिड्डीकेट बैंक के सामने, भाग्यंदर (पूर्व) थाणे (जिला) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग II) वाले "ई डब्ल्यू पी" श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित, स्वतः पूरक जालबालित तोलन उपकरण (मेजनाल प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यूरेका" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और इसका अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/2000/171 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त माडल (आकृति दी गई है)। इसकी अधिकतम क्षमता 1 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 ग्रा. है का तोलन उपकरण है। स्थापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 मि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्त है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही वर्गीकार है जिसकी भुजाएं 275 × 275 मि. मी. हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि.ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके स्थापन मापमान के अन्तराल (एन) की संख्या 1,00,000 से कम या उसके बराबर है (एन $\leq 1,00,000$) तथा जिसका "ई" मान 1×10^{-5} , 2×10^{-5} और 5×10^{-5} है, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(111)/2000]

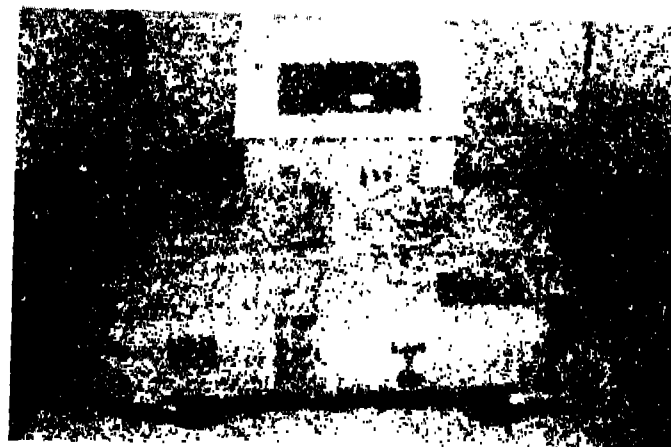
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 48.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, (Flat form) weighing instrument with digital indication of "EWP" series of Medium accuracy (Accuracy class III) and with brand name "Eureka" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s. Eureka Weighing Systems Private Limited, Gala No. 107, Vishal Industrial Estate Off. Goddeo Road, Near Gas Godown, Opp Syndicate Bank, Bhavandar (East) Thane (District) and which is assigned the approval mark IND/09/2000/172.

The said model (figure given) is a weighing instrument with maximum capacity is 50kg. and minimum capacity of 200g. The verification scale interval (e) is 10g. It has tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of side 500×500 millimetre. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 5 tonne with number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ($n \leq 10,000$) and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[No. W.M.-21(111)/2000]

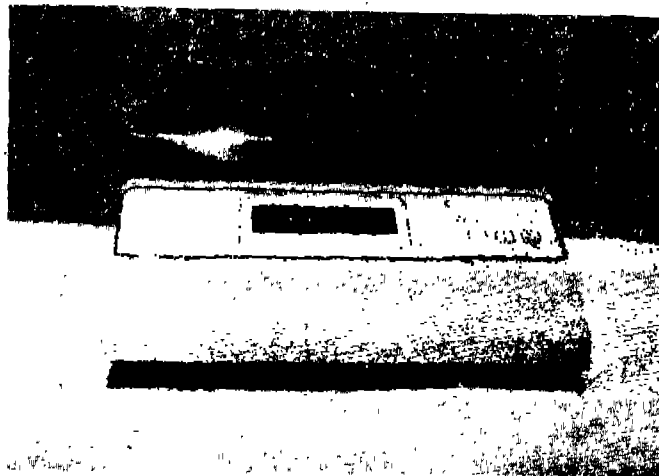
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 49.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा-

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स यश इंजीनियर्स, 30-बी, रवीन्द्र नगर, महाबल के पास, स्वामी सम्राट मन्दिर, जलगाव, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग II) वाले "सी आर टी" श्रृंखला के अंकीय सूचन सहित, स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण (मेजतल प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "प्रिज्म" है, (जिसे इसमें इंग्रे. पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2000/185 दिया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) जिसकी अधिकतम क्षमता 25 किलो ग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम का तोलन उपकरण है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 2 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यवहलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही आयताकार है, जिसकी भुजाएं 290 × 230 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि.ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिसमें अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान के अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 1,00,000 से कम या उसके बराबर है (एन ≤ 1,00,000) तथा जिसका "ई" मान 1×10^{-5} , 2×10^{-5} और 5×10^{-5} है, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(121)/2000]

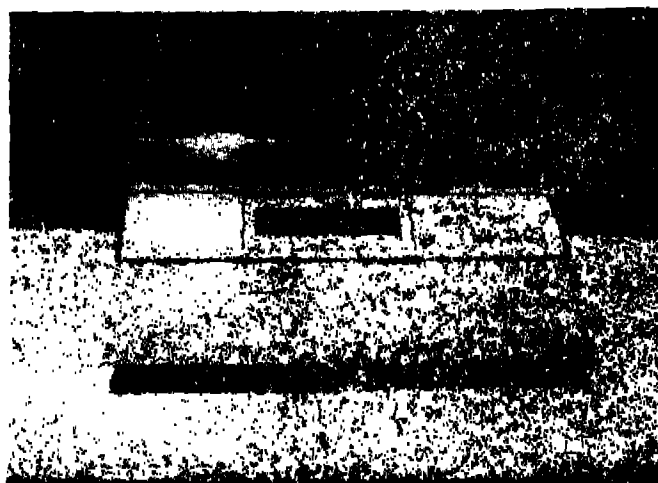
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 49.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of model of the self-indicating, non-automatic, (table top type) weighing instrument with digital indication of "PRT" series of High accuracy (Accuracy class II) and with brand name "Prism" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s Yash Engineers, 30-B, Ravindra Nagar, Near Mahabal, Swami Samrat Mandir, Jalgaon (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2000/185:

The said model (figure given) is a weighing instrument with a maximum capacity of 25kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of side 290 × 230 millimetre. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument similar accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with number of verification scale interval (n) less than or equal to 1,00,000 ($n \leq 1,00,000$) and with 'e' value to 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[No. W.M.-21(121)/2000]

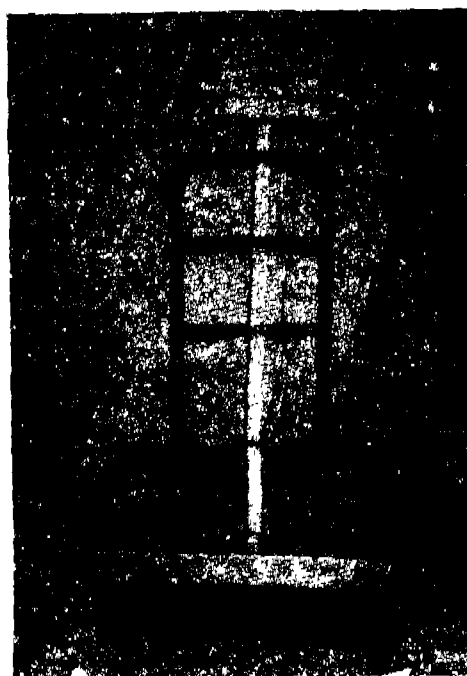
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

का. आ. 50.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स यश इंजीनियर्स, 30-बी, रवीन्द्र नगर, महाबल के निकट, स्वामी सम्राट मन्दिर, जलगांव (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग III) वाले "पी आर यो" श्रृंखला के अंकीय सूचक सहित, स्वतःसूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "प्रिज्म" है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन बिह्न आई एन डी/09/2000/186 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) जिसकी अधिकतम क्षमता 150 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम का तोलन उपकरण है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही आयताकार है, जिसकी भुजाएं 500 × 600 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान के अन्तराल (एन) की संख्या 10,000 से कम या उसके बराबर है (एन \leq 10,000) तथा जिसका "ई" मान 1×10^{-6} , 2×10^{-6} और 5×10^{-6} है, जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(121)/2000]

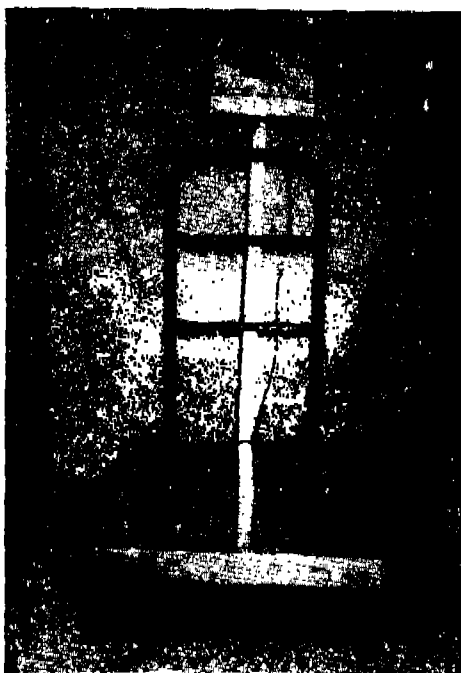
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2001

S. O. 50.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating, non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "PRP" series of Medium accuracy (Accuracy class III) and with brand name "Prism" (hereinafter referred to as the model), manufactured by M/s. Yash Engineers, 30-B, Ravindra Nagar, Near Mahabal, Swami Samrat Mandir, Jalgaon (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2000/186;

The said model (figure given) is a weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg. and minimum capacity of 400 g. The verification scale interval (e) is 20g. It has tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of side 500 × 600 millimeter. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50-Hertz, alternate current power supply ;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument similar accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 5 tonne with number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ($n \leq 10,000$) and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k and 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model have been manufactured.

[F. No. W.M.-21(121)/2000]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर 2001

का. आ. 51.— केन्द्रीय सरकार स्तव्द्वारा तेल उद्योग §विकास§ अधिनियम, 1974 §1974 का 47§ की धारा 3 की उपधारा §3§ के खण्ड §क§ द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री वी.एन. कौल, सचिव, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग को श्री अरविन्द वर्मा के स्थान पर तत्काल प्रभाव से, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. जी-35012/3/92-वित्त-2]

के पी. के. नम्बिसन, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 20th December, 2000

s. O. 51.— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints, with immediate effect and for a period not exceeding two years, Shri V.N. Kaul, Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals, as a Member of the Oil Industry Development Board, *vice* Shri Arvind Verma.

[No G-35012/2/92-Fin II]

K P K NAMBISSAN, Under Secy

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का. आ. 52.— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम और पता	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)
श्री आर.एम. पंड्या, डिप्टी कलेक्टर, गुजरात स्टेट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर, (पाइपलाइन्स प्रभाग) पो. बा. नं. 4, डाक घर, विरमगाम, जिला - अहमदाबाद, गुजरात - 382150	गुजरात राज्य

[सं. आर.-31015/49/2000-ओ आर-1]

एस. चन्द्रशेखर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2001

S. O. 52. -In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

Schedule

Name and address of the authority	Area of jurisdiction
(1)	(2)
Shri R.M. Pandya, Deputy Collector, State of Gujarat, on deputation to the Indian Oil Corporation Limited, (Pipelines Division) P.B. No.4, P.O. Viramgam Distt., Ahmedabad Gujarat - 382150	State of Gujarat

[No.-31015/49/2000 OR I]

S. CHANDRASEKHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2001

का. आ. 53.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1268 तारीख 16 जून, 2000 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में मै० पेट्रोनेट एम-एच-बी लि० द्वारा कर्नाटक राज्य में मैंगलोर से बेंगलोर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां क्रमशः तारीख 31 जुलाई, 2000, 30 जुलाई, 2000 तथा 4 अगस्त, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लंगनों से मुक्त मै० पेट्रोनेट एम-एच-बी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : कर्नाटक

जिला : दक्षिण कन्नड़

तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या	भाग हिस्सा नं० यदि कोई हो	क्षेत्रफल एकड़ : सैंट
1	2.	3.	4.	5.
मैंगलूर	केजार	23	8ए	0-09
		23	8बी	0-10
		23	12ए	0-06
		23	12बी	0-02
		23	10ए	0-05
		23	15ए	0-02
		23	15बी	0-04
		23	11	0-09
		23	13ए	0-08
		23	13बी	0-10
		47	1	0-27
		47	2	0-05
		47	14बी	0-07
		50	23	0-10
		54	1ए	0-33
		54	4	0-10
		54	5	0-24
		54	6	0-19
		54	8	0-09
		55	2	0-01
		55	4ए	0-22
		55	5ए	0-12
		55	5बी	0-07
		55	6	0-09

1	2.	3.	4.	5.
		55	16	0-16
		77	1	0-25
		77	7ए	0-04
		82	1ए	0-56
		83	1	0-10
		83	3	0-18
		83	12ए1	0-17
		80	1	0-30
		80	2	0-18
		80	3	0-10
		80	4	0-03
		80	5	0-16
		80	6	0-13
		76	5	0-22
		76	8	0-30
		76	9	0-02
		81	1	0-16
		81	2	0-02
		102	8ए	0-08
		102	12ए	0-28
		102	12बी	0-12
		102	13	0-62
		102	16	0-43
		104	5	0-35
		104	6	0-05
		152	1	0-03
		152	13	0-03
		154	2	0-01
		155	4	0-04
		159	4	0-02
		163	8	0-01
	मालावूरु	162	1	0-47
		162	2ए	0-01
		161	1	0-17

1	2.	3.	4.	5.
		161	2	0-08
		161	3बी	0-15
		161	5	0-25
		161	6ए	0-12
		161	6बी	0-15
		161	7	0-01
		161	8	0-01
		128	1	0-16
		128	2	0-43
		6	6ए	0-22
		127	1	0-14
		127	2	0-01
		5	1बी	0-21
		5	2ए	0-12
		5	2बी	0-01
		5	4	0-09
		5	3ए	0-01
		5	3बी	0-04
		8	44बी	0-17
		8	27	0-23
		8	28ए	0-25
		8	22ए	0-01
		8	22बी	0-10
		8	6सी	0-24
		8	25	0-20
		8	23	0-28
		8	24ए2	0-17
		8	24बी	0-18
		10	5	0-35
		10	6	0-03
		10	8	0-23
		11	2ए	0-41
		11	2बी	0-24
		12	4ए	0-05
		12	5ए	0-01

1	2.	3.	4.	5.
		12	5बी	0-03
		12	6ए	0-16
		12	6बी	0-01
		12	15ए	0-22
		12	15बी	0-04
		12	14	0-26
		12	22	0-26
		17	1ए	0-06
		17	2	0-05
		17	3	0-05
		17	5ए1	0-02
		17	5बी	0-01
		17	6	0-03
		15		0-05
	आध्यापाडि	9	2	0-51
		9	8	0-27
		11	7	0-84
		12	1	0-35
		12	2	0-13
		13	6	0-40
		13	8	0-03
		13	9	0-02
		13	10	0-98
		18	1	0-32
		18	4	0-15
		18	6	0-22
		20	1	0-15
		20	2	0-17
		20	3	0-12
		21	1	0-08
		21	2	0-22
		21	3	0-24
		21	10	0-50
		21	4	0-04

1	2.	3.	4.	5.
		21	5	0-01
		28	3	0-59
		28	4	0-12
		29	4	0-02
		29	5	0-06
		32	1	0-30
		32	4	0-90
		33	3	0-27
		33	5	0-14
		34	7	0-03
		34	17	0-04
		34	18ए	0-04
		34	18बी	0-08
		45	4	0-12
		45	5	0-07
		45	6ए	0-13
		45	6बी	0-29
		46	1	0-31
		46	6	0-28
		48	2	0-22
		48	3	0-21
		48	4	0-10
		48	8	0-03
		48	9	0-20
		48	10	0-14
		54	2	0-32
		54	3	0-21
		59	10ए	0-04
		59	10बी	0-30
		59	13	0-20
		60	1	0-22
		60	2	0-11
		62	5बी	0-84
		62	9सी	0-24
		62	9डी	0-43

1	2.	3.	4.	5.
		63	2बी	0-17
		63	3	0-28
		64	1	0-16
		64	3	0-18
		64	5	0-31
		84	5	0-06
		105	1ए	0-18
		105	1बी	0-18
		105	2	0-46
	कंदावरा	20	4	0-30
		22	11	0-02
		22	5सी	0-09
		88	5	0-25
		132	2	0-17
		62	1	0-37
		62	2	0-32
		62	3	0-02
		63	1	0-04
		63	2	0-02
		61	2	0-10
		61	3	0-09
		42	2बी	0-05
		42	2सी	0-34
		42	8	0-06
		42	9	0-21
		43	2	0-35
		43	4	0-08
		43	5	0-28
		43	6	0-25
		44	3बी	0-23
		45	3	0-10
		45	5	0-05
		45	6	0-13
		47	4	0-03

1	2.	3.	4.	5.
		18	सी	0-08
		18	डी	0-08
	मूल्लू	7	1ए1	0-04
		7	1डी1	0-15
		7	1डी2	0-05
		7	2	0-24
		7	1डी3	0-10
		7	1डी4	0-01
		8	1	0-27
		100	1	0-02
		100	2	0-91
		100	4	0-90
		95		0-01
		14		0-02
	बडागाउलिपाडि	53	1	0-15
		53	2	0-17
		53	3	0-10
		159	1	0-27
		51	22	0-02
		32	4	0-01
		32	13	0-02
		32	14	0-07
		26	3	0-05
		26	4	0-01
		21	10ए	0-24
		21	4	0-24
		21	16	0-08
		209	1	0-15
		31	7	0-03
		29	1	0-01
		28	1	0-01
	भोगार	40	3	0-01

1	2.	3.	4.	5.
		40	8	0-03
		41	11	0-01
		43	5	0-02
		43	7	0-09
		28	5	0-01
		28	7	0-19
		27	1	0-04
बंटवाल	करियांगला	2	2	0-04
		2	5	0-02
		3	1सी	0-04
		3	5	0-01
		3	14	0-07
		4	10	0-03
		7		0-47
	बडागावल्लुरु	41	2	0-09
		42	30	0-06
		52	8	0-03
		72	2ए	0-49
		72	8	0-08
		72	7	0-04
		76	1ए	0-23
		86	9	0-16
		86	22	0-45
		155	3	0-19
		163	3	0-19
		208	2	0-37
		216		0-08
		47		0-17
बेलतांगडि	बेलाल	250	2	0-05
		256		0-86
	उजिरे	316	3ए	0-41

1	2	3	4	5
		318	11	0-03
		561	2	0-17
	धर्मस्थल	21	4ए	0-30
		21	8ए	0-56
		21	9	0-13
		84	2बी	0-29
		162	3सी	0-01
		297	4ए3	0-07
		298	2	0-07
		164	2ए	0-07
		79	3ए	0 22
		182		0-50
	पूद्वेत्त	226		0-07
		227		0-35
		120		0-38
		121		0-64
		122	1	1-09
		123		1-04
		124	3	0-27
		125		0-17
		127	1सी	1-73
	नेरिया	70	1ए	0-91
		70	2	0-34
		71	3	0-32
		71	8	0-36
		69		0-25

[सं. आर.-31015/3/98-ओ आर-II भाग]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2001

S. O. 53.—Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1268 dated the 16th June, 2000, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) Act, 1962, (50 of 1962), (hereinafter referred to as said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands, specified in the Schedules appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum products from Mangalore to Bangalore in the state of Karnataka, by M/s. Petronet MHB Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 31.7.2000, 30.7.2000 and 4.8.2000 respectively;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of publication of this declaration, in the Petronet MHB Limited, free from all encumbrances.

1	2	3	4	5
		55	16	0-16
		77	1	0-25
		77	7A	0-04
		82	1A	0-56
		83	1	0-10
		83	3	0-18
		83	12A1	0-17
		80	1	0-30
		80	2	0-18
		80	3	0-10
		80	4	0-03
		80	5	0-16
		80	6	0-13
		76	5	0-22
		76	8	0-30
		76	9	0-02
		81	1	0-16
		81	2	0-02
		102	8A	0-08
		102	12A	0-28
		102	12B	0-12
		102	13	0-62
		102	16	0-43
		104	5	0-35
		104	6	0-05
		152	1	0-03
		152	13	0-03
		154	2	0-01
		155	4	0-04
		159	4	0-02
		163	8	0-01
	MALAVURU	162	1	0-47
		162	2A	0-01
		161	1	0-17

SCHEDULE**STATE : KARNATAKA****DISTRICT : DAKSHINA KANNADA**

Name of Taluk	Name of Village	Survey No.	Part/ Hissa No. (If any)	EXTENT Acre - Cents
1	2	3	4	5
MANGALORE	KENJAR	23	8A	0-09
		23	8B	0-10
		23	12A	0-06
		23	12B	0-02
		23	10A	0-05
		23	15A	0-02
		23	15B	0-04
		23	11	0-09
		23	13A	0-08
		23	13B	0-10
		47	1	0-27
		47	2	0-05
		47	14B	0-07
		50	23	0 - 10
		54	1A	0 - 33
		54	4	0-10
		54	5	0-24
		54	6	0-19
		54	8	0-09
		55	2	0-01
		55	4A	0-22
		55	5A	0-12
		55	5B	0-07
		55	6	0-09

1	2	3	4	5
		161	2	0-08
		161	3B	0-15
		161	5	0-25
		161	6A	0-12
		161	6B	0-15
		161	7	0-01
		161	8	0-01
		128	1	0-16
		128	2	0-43
		6	6A	0-22
		127	1	0-14
		127	2	0-01
		5	1B	0-21
		5	2A	0-12
		5	2B	0-01
		5	4	0-09
		5	3A	0-01
		5	3B	0-04
		8	44B	0-17
		8	27	0-23
		8	28A	0-25
		8	22A	0-01
		8	22B	0-10
		8	6C	0-24
		8	25	0-20
		8	23	0-28
		8	24A2	0-17
		8	24B	0-18
		10	5	0-35
		10	6	0-03
		10	8	0-23
		11	2A	0-41
		11	2B	0-24
		12	4A	0-05
		12	5A	0-01

1	2	3	4	5
		12	5B	0-03
		12	6A	0-16
		12	6B	0-01
		12	15A	0-22
		12	15B	0-04
		12	14	0-26
		12	22	0-26
		17	1A	0-06
		17	2	0-05
		17	3	0-05
		17	5A1	0-02
		17	5B	0-01
		17	6	0-03
		15		0-05
	ADYAPADY	9	2	0-51
		9	8	0-27
		11	7	0-84
		12	1	0-35
		12	2	0-13
		13	6	0-40
		13	8	0-03
		13	9	0-02
		13	10	0-98
		18	1	0-32
		18	4	0-15
		18	6	0-22
		20	1	0-15
		20	2	0-17
		20	3	0-12
		21	1	0-08
		21	2	0-22
		21	3	0-24
		21	10	0-50
		21	4	0-04

1	2	3	4	5
		21	5	0-01
		28	3	0-59
		28	4	0-12
		29	4	0-02
		29	5	0-06
		32	1	0-30
		32	4	0-90
		33	3	0-27
		33	5	0-14
		34	7	0-03
		34	17	0-04
		34	18A	0-04
		34	18B	0-08
		45	4	0-12
		45	5	0-07
		45	6A	0-13
		45	6B	0-29
		46	1	0-31
		46	6	0-28
		48	2	0-22
		48	3	0-21
		48	4	0-10
		48	8	0-03
		48	9	0-20
		48	10	0-14
		54	2	0-32
		54	3	0-21
		59	10A	0-04
		59	10B	0-30
		59	13	0-20
		60	1	0-22
		60	2	0-11
		62	5B	0-84
		62	9C	0-24
		62	9D	0-43

1	2	3	4	5
		63	2B	0-17
		63	3	0-28
		64	1	0-16
		64	3	0-18
		64	5	0-31
		84	5	0-06
		105	1A	0-18
		105	1B	0-18
		105	2	0-46
	KANDAVARA	20	4	0-30
		22	11	0-02
		22	5C	0-09
		88	5	0-25
		132	2	0-17
		62	1	0-37
		62	2	0-32
		62	3	0-02
		63	1	0-04
		63	2	0-02
		61	2	0-10
		61	3	0-09
		42	2B	0-05
		42	2C	0-34
		42	8	0-06
		42	9	0-21
		43	2	0-35
		43	4	0-08
		43	5	0-28
		43	6	0-25
		44	3B	0-23
		45	3	0-10
		45	5	0-05
		45	6	0 13
		47	4	0-03

1	2	3	4	5
		18	C	0-08
		18	D	0-08
	MULURU	7	1A1	0-04
		7	1D1	0-15
		7	1D2	0-05
		7	2	0-24
		7	1D3	0-10
		7	1D4	0-01
		8	1	0-27
		100	1	0-02
		100	2	0-91
		100	4	0-90
		95		0-01
		14		0-02
	BADAGAULIPADI	53	1	0-15
		53	2	0-17
		53	3	0-10
		159	1	0-27
		51	22	0-02
		32	4	0-01
		32	13	0-02
		32	14	0-07
		26	3	0-05
		26	4	0-01
		21	10A	0-24
		21	4	0-24
		21	16	0-08
		209	1	0-15
		31	7	0-03
		29	1	0-01
		28	1	0-01
	MOGAR	40	3	0-01

1	2	3	4	5
		40	8	0-03
		41	11	0-01
		43	5	0-02
		43	7	0-09
		28	5	0-01
		28	7	0-19
		27	1	0 - 04
BANTVAL	KARIYANGALA	2	2	0-04
		2	5	0-02
		3	1C	0-04
		3	5	0-01
		3	14	0-07
		4	10	0 - 03
		7		0 - 47
	BADAGABELLURU	41	2	0 - 09
		42	30	0 - 06
		52	8	0 - 03
		72	2A	0-49
		72	8	0-08
		72	7	0-04
		76	1A	0-23
		86	9	0-16
		86	22	0-45
		155	3	0-19
		163	3	0 - 19
		208	2	0 - 37
		216		0 - 08
		47		0 - 17
BELTHANGADY	BELAL	250	2	0 - 05
		256		0 - 86
	UJIRE	316	3A	0-41

1	2	3	4	5
		318	11	0-03
		561	2	0-17
	DHARMASTHALA	21	4A	0-30
		21	8A	0-56
		21	9	0-13
		84	2B	0-29
		162	3C	0-01
		297	4A3	0-07
		298	2	0-07
		164	2A	0-07
		79	3A	0-22
		182		0-50
	PUDUVETTU	226		0-07
		227		0-35
		120		0-38
		121		0-64
		122	1	1-09
		123		1-04
		124	3	0-27
		125	1	0-17
		127	1C	1-73
	NERIYA	70	1A	0-91
		70	2	0-34
		71	3	0-32
		71	8	0-36
		69		0-25

[No.-31015/3/98 OR II-Part]
HARISH KUMAR, Under Secy

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का.आ. 54.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय कलकत्ता के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26 दिसम्बर, 2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/47/92-बी-III]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 54.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L-12012/47/92(B-III)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 44 of 1992

PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice B. P. Sharma, Presiding Officer.

APPEARANCE:

On behalf of Management: None.

On behalf of Workmen: None.

STATE: West Bengal

INDUSTRY: Banking

AWARD

By Order No. L-12012/47/92-IR(B.III) dated 20-7-1992 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India in dismissing the services of Shri Shani, Sweeper-cum-Farash is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. When the case is called out today, none appears for the either of the parties. On the last date also no one appeared for them. It also appears from the record that on earlier several occasions, no one appeared for the union and the case was being adjourned from time to time. It is accordingly clear that the union is no longer interested to proceed with the case.

3. In the aforesaid circumstance, this Tribunal has no other alternative but to dispose of the present reference by passing a 'No Dispute' Award.

2 GI/2001—10.

4. A "No Dispute" Award is accordingly passed and the reference is disposed of.

B. P. SHARMA, Presiding Officer

Dated, Calcutta,

The 22nd November, 2000.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का.आ. 55.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय कोटा के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26/12/2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/48/94-बी-I]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 55.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Rajasthan Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L-12012/48/94-B.I]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायधीन, औद्योगिक न्यायधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज.

पीठाधीन अधिकारी श्री महेश चन्द्र भगवती आर. एच. जे. एस

निर्देश प्रकरण क्रमांक ओ. न्या./केन्द्रीय/19/95

दिनांक स्थापित 29/7/95

प्रसंग: भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल० 12012/48/94/आई. आर (बी-आई) दिनांक 19/7/95

निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1) (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

गद्य

हीरालाल द्वारा अध्यक्ष, अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारी संघ द्वारा दी बैंक आफ राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय एरोडाम सैकिल, कोटा।

एवं

—प्रार्थी श्रमिक

क्षेत्रीय प्रबंधक दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड, एरोडाम सैकिल, कोटा।

—अप्रार्थी नियोजक

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि: श्री बलदेव सिंह
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि: श्री सुरेश माथुर
अधिनिर्णय दिनांक 2/11/2000

अधिनियम

भारत सरकार, अथम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने उक्त आदेश दि. 19/7/95 के जरिये निम्न निर्देश विवाद अनुसूची औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त “अधिनियम” में सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 10(1) (घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनियमार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

“क्या प्रबन्धकर्ता दो बैंक ऑफ राजस्थान लि. कोटा द्वारा कर्मकार श्री हीरालाल गुजर दफ्तरी, शाखा हिण्डोता सिटी को दि. 1-7-93 से स्थापना भत्ता बंद करने एवं उसे लिपिक वर्ग में अयोग्य न मानकर पदोन्नति न देने की कार्यवाही उचित एवं विधिसम्मत है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?”

2. निर्देश-विवाद अनुसूची न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर पंजीबद्ध उपरान्त दोनों पक्षों को नोटिस तबकी हेतु प्रेषित किए गए जिस पर दोनों पक्षों ने न्यायाधिकरण में उपस्थित होकर अपने-अपने अग्रार्थवेदन प्रस्तुत किये।

3. प्रार्थी श्रमिक हीरालाल गुजर द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट आफ क्लेम के अनुसार वह दो बैंक ऑफ राजस्थान लि. शाखा हिण्डोता सिटी जिला सर्वाई माधोपुर में दफ्तरी के पद पर कार्यरत था। उसने हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में वर्ष 1994 में मध्यमा की परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की थी, अतः अप्रार्थी ने उसे दि. 6-2-90 से लिपिक वर्ग में पदस्थापना भत्ता स्वीकृत किया था जिसे वह निरन्तर प्राप्त कर रहा था। किन्तु शाखा प्रबन्धक हिण्डोता सिटी ने अपने पत्र दि. 26-7-93 के द्वारा उसे यह सूचित किया कि अब उसे पदस्थापना भत्ता दि. 1-7-93 से नहीं दिया जावेगा क्योंकि केन्द्रीय कार्यालय, जयपुर ने मध्यमा परीक्षा को मैट्रिकुलेशन के समकक्ष नहीं माना है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी ने उसे इसी आधार पर लिपिक वर्ग में पदोन्नति का अवसर ही उपलब्ध नहीं कराया। उसने प्रार्थना की है कि उसे 1-2-90 से मिल रहे पदस्थापना भत्ते का भुगतान दि. 1-7-93 से आगे भी करवाया जावे और मैट्रिकुलरी परीक्षा के समकक्ष मानते हुए लिपिक वर्ग में पदोन्नति हेतु योग्य भी घोषित किया जावे।

4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के इस अनर्थ तथ्य की कि मध्यमा परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ यदि उत्तीर्ण की जावे तो वह मैट्रिकुलरी परीक्षा के समकक्ष है सही मानते हुए उसे लिपिक वर्ग हेतु पदस्थापना भत्ता दिया जाता रहा है, किन्तु जब नियोजक ने सम्बन्धित अधिकारियों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में यदि हिन्दी की परीक्षा पास कर लेता है, तो वह हिन्दी की परीक्षा “हिन्दी प्रथमा” के बराबर मानी जावेगी। अप्रार्थी ने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि

प्रार्थी ने केवल मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसकी शैक्षणिक योग्यता केवल छोटी पाम है जो मैट्रिकुलेशन अथवा बी.ए. के समकक्ष नहीं है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) के पत्र संख्या एफ.नं. 9-1/78-डी दिनांकित जून, 1979 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि विभिन्न हिन्दी भाषा की परीक्षाएँ जो विभिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं, केवल हिन्दी की परीक्षा के लिए मान्य है, न कि पूर्ण बी.ए. की परीक्षा एवं डिग्री के इसके अतिरिक्त अप्रार्थी बैंक ने अपनी सभी कार्यालयों/शाखाओं को एक पत्र दि. 16-10-80 के माध्यम से भी यह सूचित किया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा, मध्यमा या उत्तमा परीक्षाएं बैंक में मान्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उत्तीर्ण की गयी मध्यमा परीक्षा, बी.ए. की परीक्षा के समकक्ष नहीं है, अतः प्रार्थी का स्टेटमेंट आफ क्लेम खारिज किया जावे।

5. प्रार्थी श्रमिक हीरालाल गुजर ने स्टेटमेंट आफ क्लेम में वर्णित तथ्यों की सन्तुष्टि में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थी ने श्री जी.पी. मान, सहा. प्रबन्धक को परीक्षित कराया है।

6. उभयपक्ष की वकल अवग की गयी तथा अभिवेद पर ग्राह्य सक्षय एवं मसंगत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री बन्नेर सिंह ने युक्ति प्रकट की है कि अप्रार्थी बैंक ऑफ राजस्थान लि. ने अपने पत्र प्रवर्ग डबल्यू. 2 द्वारा प्रार्थी द्वारा उत्तीर्ण की गयी मध्यमा परीक्षा को मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माना है और इसी आधार पर उसे पदस्थापना भत्ता स्वीकृत किया है। उसका यह भी तर्क है कि न्यायदृष्टा “आर.एन.आर. 1993(2) के पृष्ठ सं. 109 पर प्रकाशित राज. राज्य एवं अन्य बनाम शिव करण में माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा आयोजित मध्यमा एवं प्रथमा की परीक्षा मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल के समकक्ष है, अतः प्रार्थी को भी मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष माना जावे क्योंकि उसने हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में मध्यमा की परीक्षा सन् 1984 में उत्तीर्ण की है।

8. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री सुरेश माथुर ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए यह युक्ति प्रकट की है कि प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत उक्त न्यायदृष्टांत अब प्रभाव में नहीं है और माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने न्यायदृष्टांत “1995(2) डबल्यू.एल.एन. 547 पर प्रकाशित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम नन्दराम” के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रथमा की परीक्षा केवल हिन्दी स्तर के समकक्ष है, किन्तु यह पूर्ण मैट्रिकुलेशन के समकक्ष नहीं है। इस न्यायदृष्टांत में प्रार्थी पक्ष द्वारा उद्धृत न्यायदृष्टांत का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ यह

उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रारम्भ में सरकार ने अधि-सूचना दि. 13-5-74 द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रथमा परीक्षा को मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्रदान की थी, किन्तु सरकार ने बाद में अधिसूचना दि. 28-6-85 के द्वारा इस परीक्षा को मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल के समकक्ष नहीं माना और जिन व्यक्तियों ने प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी थी उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक वर्ग में पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना था और उनके द्वारा प्राप्त की गई मध्यमा परीक्षा को अयोग्य घोषित किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नन्दराम के मामले में माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने वर्गीकृत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथमा परीक्षा को केवल एम.एम.-सी./मैट्रिकुलेशन के हिन्दी स्तर के लिए सशर्त समकक्ष माना था और पूर्ण मैट्रिकुलेशन के समकक्ष नहीं माना था इसलिए इस मामले में माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जावेगा कि प्रार्थी ने मैट्रिकुलेशन अथवा सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मध्यमा की परीक्षा मैट्रिकुलेशन अथवा सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष है। कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रार्थी ने पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की है और मध्यमा अथवा प्रथमा की परीक्षा मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल के समकक्ष नहीं है।

9. यह सत्य है कि प्रार्थी श्रमिक हीरालाल गूजर ने वर्ष, 1984 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से मध्यमा की परीक्षा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की थी, किन्तु दि. 28-6-85 के परिपत्र द्वारा इसे मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल के समकक्ष नहीं माना यानि अब इसे अमान्य कर दिया है और अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को पदस्थापना भत्ता नहीं देने एवं उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से लिपिक वर्ग में पदोन्नति नहीं देने का यही आधार रहा है। न केवल राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया है, अपितु भारत सरकार, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने भी अपने पत्र संख्या एफ. नं. 9-1/78-डी दिनांकित जून, 1979 द्वारा भी इस परीक्षा को पूर्णतया मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल के समकक्ष स्वीकार नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नन्दराम के मामले में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की रोशनी में, प्रार्थी अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

10. उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त उपर्युक्त निर्देश-विवाद अनुसूची को इस प्रकार अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रबन्धतंत्र, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि., कोटा द्वारा प्रार्थी श्रमिक हीरालाल गूजर, दफ्तरी शाखा डिप्टी मैनेजर को दिनांक 1-7-93 में स्थापना भत्ता बन्द करने एवं उसे लिपिक वर्ग में अयोग्य मानकर पदोन्नति न देने की कार्यवाही सर्वथा उचित एवं

विधिसम्मत है तथा प्रार्थी, अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार प्रकाशनाथ भिजवाया जाये।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का. आ. 56. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26 दिसम्बर, 2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/104/97-बी-1]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 56.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L-12012/104/97-B. I]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI R. P. PANDEY, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR,

KANPUR

Industrial Dispute No. 15 of 1998
In the matter of dispute:

BETWEEN

Sri Suresh Chandra Mishra,
S/o Ram Bharsey Mishra,
Gram Kaktupur Rabban Post Kanpur,
District Kanpur Dehat.

AND

Manager,
State Bank of India,
Branch Gwaltoli,
Kanpur Nagar.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/104/97-IR(B) dated 16-1-98 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur in terminating the services of Shri Suresh Chandra Mishra is legal and justified? If not to what relief the workman is entitled?"

2. In the claim statement the workman has stated that he was engaged as casual labour in State Bank of India branch Gwalton Kanpur on 20-1-89 and he worked there till 16-2-90. He was again employed by the bank on 20-1-95 as canteen boy but he also discharged the duties of an employee of the bank. When the workman demanded the pay scales and other amenities like regular employees of the bank his services were terminated w.e.f. 10-6-96 by an oral order. The work which the workman was performing in the bank is still continuing. Thus the management of the bank has violated the provisions of Section 25F, 25G and 25H of the Act, because no retrenchment compensation or notice pay was given to him before termination of his services. On the basis of these allegations he has prayed that he be reinstated in service with back wages.

3. The management has filed written statement with contention that relationship of master and servant never existed between the bank and the concerned workman. It has been alleged that the workman was employed as canteen boy in the canteen run by Local Implementation Committee (hereinafter referred to as LIC for the sake of brevity). It has been alleged that the branch manager was ex officio president of that committee and that committee consisted of employees of the bank which was running the canteen. It has been alleged that it was a non statutory body, hence the employees of the LIC working in the canteen could not get the status of an employee of the bank. The workman was also appointed as canteen boy under control of LIC and his services were terminated by LIC hence he has no right to get reinstatement in the services of the bank. It has been alleged that regular employees of the bank get the benefit of House Allowance, Leave Fare Concession, Bonus, G.P.F., City Allowance, Casual leave and medical leave but canteen boys do not get such benefits which shows that canteen boy is not an employee of the bank. The concerned workman never demanded the aforesaid facilities while working as canteen boy. It is alleged that the workman is not entitled to get any relief against the bank and the reference is liable to be decided against the concerned workman.

3A. The workman has repeated the allegation made in the Statement of Claim in Rejoinds.

4. The workman himself has examined as W.W. 1 and filed 4 documents marked Ext. W-1 to W-4 in support of his case. The management examined Sri Suresh Kumar Verma as M.W. 1 and filed 5 documents marked Ext. M-1 to M-5 in support its case.

5. I have heard the representatives for both the sides and have gone through the records of the case. The authorised representative for the management has argued that Suresh Chandra Mishra the concerned workman was appointed as canteen boy by LIC of State Bank of India branch Gwalton Kanpur and his services were also terminated by that committee, hence he is not entitled to get any relief against the bank as to get reinstatement in the services of the bank. After going through the record of the case and evidence on the record, I find force in this contention.

6. The workman has himself admitted in his statement of claim that he was appointed as canteen boy on 20-1-95 and his services were terminated on 10-6-96. In his statement on oath also he has stated that he was appointed as canteen boy on 20-1-95 and he worked on that post till 10-6-96. He has also filed the copy of appointment letter dated 19-1-95 Ext. W-1 which shows that he was appointed as canteen boy by the Secretary of LIC State Bank of India Gwalton Branch Kanpur. He has also filed his termination order dated 10-6-96, Ext. W-4 which shows that his services were terminated by the then Secretary of LIC State Bank of India Gwalton Branch, Kanpur Sri Suresh Kumar Verma, branch manager State Bank of India Gwalton Branch. M.W. 1 clearly stated on oath that canteen boys are appointed by LIC which consists of the employees of the bank and branch manager of the bank is ex-officio President of that committee. He stated that LIC has a Current Account in its name in the bank and the salary of the canteen boy is paid from that current account of the LIC. He has stated that canteen boy worked under control and supervision of LIC and was not the employee of the bank nor bank has any administrative control over him. The contention of M.W. 1 appears to be correct because Suresh Chandra Mishra, the concerned workman was

appointed as canteen boy by Secretary of LIC and not by any officer of the bank. The workman has not filed any document to show that he was appointed by any officer of the bank and was ever selected for any post in the bank and was getting salary from the bank for work as a canteen boy. In view of above considerations I have no option but to hold that Suresh Chandra Mishra, the concerned workman is a canteen boy and was an employee of LIC and was not the employee of the bank. I, therefore, hold that he is not entitled to get any relief against the bank or to be reinstated in the services of the bank on any post whatsoever.

7. The representative for the management has drawn my attention towards a judgment of the hon'ble Supreme Court passed in State Bank of India versus State Bank of India Canteen Employees Union, 2000, Lab IC 1481, in which similar question was considered by Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Supreme Court held as under—

Even if LIC consist of employees of the bank and those employees are directly under the control of the bank, it cannot be held that bank is the employer of the persons working in the canteen.

A similar question was also considered by the Hon'ble Supreme Court in Employers in relation to the Management of Reserve Bank of India versus Their Workmen, 1996, Lab IC 1048 in which the Hon'ble Supreme Court held as under—

Held, in the absence of any obligation statutory or otherwise regarding the running of a canteen by the bank in the absence of any effective or direct control in the bank to supervise and control the work done by various persons the workers in the canteen run by the Implementation Committee (Canteen Committee) cannot be said to be employees of the RBI.

The law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the cases cited above fully applies to the facts of the present case. The Local Implementation Committee of the State Bank of India Gwalton Branch Kanpur is a non statutory body and in view of the law laid down in the cases cited above, I hold that Suresh Chandra Mishra Canteen boy being an employee of LIC could not get status of an employee of the bank and was not entitled to get any relief against the bank either for reinstatement or for getting back wages as the relationship of master and servant did not exist between the bank and the concerned workman.

8. In view of findings recorded above, I hold that the workman concerned is not entitled to get any relief against the State Bank of India in pursuance of the reference made to this Tribunal.

9. The reference is answered accordingly.

R. P. PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का. आ. 57.—श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार की बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट श्रीयोगिक विवाद में श्रीयोगिक अधिकरण/अस न्यायालय, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26 दिसम्बर, 2000 को प्राप्त हुआ था।

[गं. एन-12012/204/96-बी-1]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 57.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Rajasthan Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L-12012/204/96-B-I]
AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज./
पीठासीन अधिकारी - श्री महेश चन्द्र भगवती, आर.एच.
जे.एस.

निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ. न्या.-26/97

दिनांक स्थापित : 2-11-97

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के
आदेश संख्या एल-12012/204/96-आई.
आर. (बी) दिनांक 12-9-97

निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1)(घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

1. अब्दुल गनी खां एवं 2. सुनील कुमार जैथलिया
द्वारा महासचिव, दी बैंक ऑफ राजस्थान एम्प्लोईज
यूनियन, कोटा ।

—प्रार्थीगण श्रमिक

एवं

प्रबन्धन, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. केन्द्रीय कार्यालय,
जयपुर ।

—अप्रार्थी नियोजक

उपस्थित

प्रार्थीगण श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री एन.के.
तिवारी

अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री सुरेश माथुर
अधिनिर्णय दिनांक : 2-11-2000

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने
उक्त आदेश दिनांक 12-9-97 के जरिये निम्न निर्देश-
विवाद अनुसूची, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(जिसे तदुपरान्त "अधिनियम" से सम्बोधित किया जावेगा)
की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को
अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

"कदा प्रबन्धन, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. केन्द्रीय
कार्यालय, जयपुर द्वारा कर्मकार सर्वश्री अब्दुल गनी खा
पिप्पोन एवं श्री सुनील कुमार जैथलिया कलक को क्रमशः
दि. 20-2-91 एवं 10-1-91 में स्थाई नियुक्ति
मानकर विपक्षीय समझौता के पैरा 20.8 के अनुसार

वरीयता प्रदान नहीं करने एवं तत्सम्बन्धी परिलाभ नहीं
देने की कार्यवाही उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि
नहीं तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुत्तीर्ण के हकदार
है और किस तारीख से ?"

2. निर्देश-विवाद अनुसूची न्यायाधिकरण में प्राप्त होने
पर पंजीबद्ध उपरान्त पक्षकारों की नियमानुसार सूचना जारी
की गयी जिस पर प्रार्थीगण श्रमिक पक्ष की ओर से
अपना क्लेम स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया ।

3. पत्रावली अप्रार्थी के जवाब हेतु 9-10-2000 को
नियत थी परन्तु उसी रोज पक्षकारों के यह प्रकट करने पर
कि उनके मध्य राजीनामे की बात चल रही है, पत्रावली इस
प्रयोजनार्थ आज के लिए निरत की गयी । आज प्रार्थीगण
श्रमिक की यूनियन के महासचिव श्री अरविन्द सन्सेना की
ओर से न्यायाधिकरण में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया गया कि चूंकि प्रार्थी यूनियन व प्रबन्धक
पक्ष के मध्य प्रस्तुत विवाद के सम्बन्ध में लोक न्यायालय
की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति हो गयी है,
इस कारण प्रार्थी यूनियन अब इस विवाद को आगे नहीं
चलाना चाहती है, अतः इसी अनुरूप अधिनिर्णय पारित कर
दिया जावे । अप्रार्थी की ओर से भी सहृदयक प्रबन्धक
श्री जी. पी. मालू ने प्रार्थी यूनियन के उक्त प्रार्थना-पत्र
पर अपनी सहमति प्रकट की है जिसके कि हस्ताक्षर उक्त
प्रार्थना-पत्र पर भी मौजूद है व उनके अधिकृत प्रतिनिधि
श्री सुरेश माथुर ने भी इसकी पुष्टि की है । इसके अतिरिक्त
स्वयं प्रार्थी अब्दुल गनी खां ने भी प्रार्थना-पत्र पर अपने
हस्ताक्षरों से उक्त सहमति से विवाद समाप्त होने को
सम्पुष्टि की है । इस प्रकार चूंकि दोनों पक्षों के मध्य
सम्प्रेषित निर्देश-विवाद के सम्बन्ध में लोक न्यायालय
की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझौता सम्पन्न हो गया
है और प्रार्थी यूनियन अब इस विवाद को आगे नहीं चलाना
चाहती है, अतः सम्प्रेषित उक्त निर्देश-विवाद को इसी प्रकार
अधिनिर्णित किया जाता है ।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार
प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे ।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का. आ. 58.—औद्योगिक विवाद अधिनियम,
1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, कोटा के प्रबन्धन के संबंध
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय
कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार
को 26-12-2000 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-41012/19/92-आईआरएचएच (बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 58.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Kota and their workman which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L-41012/19/92-IR-DU(B-I)]
AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज./
पीठासीन अधिकारी—श्री महेश चन्द्र भगवती, आर.एच.जे.एस.
निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ. न्या./केन्द्रीय/10/93
दिनांक स्थापित : 29/3/93

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के
आदेश संख्या एल-41012/19/92-आई. आर.
(डी. यू.) दि. 22-3-93

निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1)(घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

कैलाश पुत्र श्री राम रतन द्वारा डिविजनल मेन्टेनी,
पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, स्टेशन रोड, कोटा।

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

डी. आर. एम. वेस्टर्न रेलवे, कोटा।

—अप्रार्थी नियोजक

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री ए. डी. ग़ोवर
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री राम निवास पाठक
एवं श्री सी.एम. शर्मा

अधिनिर्णय दिनांक : 6-11-2000

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने
उक्त आदेश दिनांक 22-3-93 के जरिये निम्न निर्देश-विवाद
अनुसूची, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे
तदुपरान्त “अधिनियम” से सम्बोधित किया जावेगा) की
धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को
अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

“Whether the action of Railway Admn. (DRM, Western Railway, Kota) in terminating the services of Shri Kailash S/o Shri Ram Ratan, T.S. Gangman, w.e.f. 16-7-91 is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?”

2. निर्देश-विवाद अनुसूची प्राप्त होने पर पंजीबद्ध
उपरान्त नियमानुसार दोनों पक्षों को सूचना उपस्थिति हेतु
भिजवायी गयी। दोनों पक्षों ने न्यायाधिकरण में उपस्थित
होकर अपने-अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये।

3. प्रार्थी कैलाश द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट आफ क्लेम के
अनुसार अप्रार्थी मण्डल रेल प्रबन्धक, पश्चिम रेलवे, को
(जिसे संक्षेप में आगे “अप्रार्थी नियोजक” से सम्बोधित
किया जावेगा) द्वारा एक मानक फार्म नं. 5 (मेजर
पेनल्टी चार्जशीट) दिया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा उसके
विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि प्रार्थी कर्मकार ने
जाली सर्विस कार्ड बनवाकर रेलवे में नौकरी की है एवं
इस प्रकार रेलवे प्रशासन को धोखा दिया है जोकि प्रार्थी
द्वारा किया गया एक गम्भीर कदाचार है। प्रार्थी श्रमिक का
यह भी अभिकथन है कि अप्रार्थी द्वारा नियुक्त जांच अधि-
कारी सहायक इंजीनियर, सवाईमाधोपुर ने जांच उपरान्त
उसे जाधी सर्विस कार्ड बनवाकर रेलवे प्रशासन में नौकरी
प्राप्त करने का दोषी पाया था और उसे दि. 16-7-91
को सेवा से मुक्त कर दिया तथा इस अविरोपित दण्ड
की सूचना उसे दि. 7-8-91 को प्राप्त हुई। प्रार्थी का
अभिकथन है कि जांच अधिकारी ने ना तो उसे आरोप-पत्र
से सम्बन्धित सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध करवाये एवं ना
ही उसने नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का जांच के दौरान अनु-
पालन किया। यही नहीं, सहायक श्रमायुक्त/केन्द्रीय/कोटा
ने अप्रार्थी को दि. 1-8-91 को नोटिस जारी किया था
तथा समझौते हेतु दि. 16-8-91 निश्चय की थी। इस
दिन अप्रार्थी एवं प्रार्थी दोनों को सहायक श्रमायुक्त/
केन्द्रीय/कोटा के यहां 11 बजे उपस्थित होना था किन्तु
अप्रार्थी ने दुर्भावनावश दिनांक 16-7-91 को ही उसे सेवा
से मुक्त करने का आदेश पारित कर दिया जो उसे 7-8-91
को प्राप्त हुआ और जोकि अधिनियम की धारा 33 के
प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी ने अधिनियम
की धारा 25-एफ के अन्तर्गत भी उसे सेवा से मुक्त किये
जाने का कोई नोटिस नहीं दिया अपितु असंवैधानिक तरीके
से उसे उसके बिना कोई दोष के नौकरी से हटा दिया।
अतः उसे पिछले समय के समस्त वेतन एवं अन्य संभावित
लाभों सहित पुनः सेवा में स्थापित किये जाने का आदेश
पारित किया जावे।

4. अप्रार्थी नियोजक ने अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा
स्टेटमेंट आफ क्लेम में उठाये गये सभी बिन्दुओं का खण्डन
किया है तथा पक्ष कथन किया है कि सहायक इंजीनियर,
सवाईमाधोपुर प्रार्थी के विरुद्ध दुराचरण की जांच करने हेतु
सशक्त एवं सक्षम अधिकारी था और जांच की कार्रवाही
नियमानुसार सम्पादित की जाकर ही उसे सेवा से पृथक
किया गया है।

5. प्रार्थी कैलाश ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र
प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा
प्रतिपरीक्षा की गयी है। अप्रार्थी ने श्री मित्रा सिंह,
कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक इंजीनियर, सवाई-
माधोपुर को साक्ष्य में परीक्षित करवाया है। दोनों पक्षों
की ओर से न्यायनिर्णय हेतु सुसंगत दस्तावेजात भी
प्रस्तुत किये गये हैं।

6. उभय पक्ष की बहुग श्रवण की गयी। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस, अभिलेख पर ग्राह्य साक्ष्य एवं सुसंगत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

7. प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि श्री ए. डी. ग्रोवर ने बहस के दौरान उन्हीं बिन्दुओं को उठाया है जिनका कि प्रार्थी द्वारा स्टेटमेंट आफ क्लेम एवं अपने शपथ-पत्र में उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से श्री ग्रोवर द्वारा तीन दलील पेश की गयी हैं। उनका प्रथम तर्क यह है कि प्रार्थी कैलाश को आरोप-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है अपितु सहायक इंजीनियर, सवाई माधोपुर द्वारा दिया गया है जोकि प्रार्थी का नियोजक नहीं है और ना ही आरोप पत्र देने हेतु सक्षम अधिकारी है। श्री ग्रोवर का दूसरा तर्क यह है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जांच के दौरान सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये गये और ना ही जांच में नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों की अनुपालना की गयी। यहीं नहीं, उसे अभी तक जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। तीसरी एवं अन्तिम महत्वपूर्ण दलील जो श्री ग्रोवर ने मेरे समक्ष पेश की है वह यह है कि अप्रार्थी ने समझौता कार्यवाही के लम्बित रहते हुए प्रार्थी को दि. 16-7-91 को सेवा में मुक्त करने का आदेश पारित किया है जो उसे 7-8-91 को प्राप्त हुआ है, जबकि सहायक श्रमायुक्त/केन्द्रीय/कोटा द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समझौते हेतु तारीख 16-8-91 की नियत की गयी थी। इस प्रकार अप्रार्थी ने अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को सेवा में मुक्त किये जाने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अप्रार्थी नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि श्री राम-निवास पाठक ने दलील पेश की है कि प्रार्थी कैलाश ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली सर्विस कार्ड बनवाया था और रेलवे प्रशासन को धोखा देकर वर्ष 1984 में नौकरी प्राप्त की थी, जबकि प्रार्थी ने 1984 के पूर्व 6-7-80 से रेलवे प्रशासन में कही भी नौकरी नहीं की थी। श्री पाठक का यह भी तर्क है कि यह साबित करने का भार कि प्रार्थी ने 6-7-80 से रेलवे में नौकरी प्रारम्भ की थी, पूर्णरूपेण प्रार्थी पर था और प्रार्थी इस भार का निर्वहन करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है। श्री पाठक का यह भी तर्क है कि शिड्यूल आफ पावर के अन्तर्गत ग्रुप डी के कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त करने की शक्ति सहायक इंजीनियर को प्राप्त है और वह इनके विरुद्ध विभागीय जांच करने हेतु भी सशक्त एवं सक्षम है। अतः प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि श्री ग्रोवर का यह तर्क कि सहायक इंजीनियर सवाईमाधोपुर प्रार्थी को आरोप-पत्र देने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है, पूर्णरूपेण बेबुनियाद एवं नियमों के विरुद्ध है।

9. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा उनके द्वारा दिए गए तर्कों के परिपेक्ष्य में दोनों पक्षों

द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य और दस्तावेजात का परिशीलन किया।

10. हस्तगत मामले में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रेषित विवाद का न्यायनिर्णयन करने हेतु जो मुख्य प्रश्न विनिश्चयता हेतु उत्पन्न होते हैं वे अधोलिखित हैं:—

- (1) क्या प्रार्थी कैलाश ने रेलवे प्रशासन में नौकरी प्राप्त करने हेतु रेलवे प्रशासन को धोखा देने की नियत से एक जाली सर्विस कार्ड 'प्रारम्भिक नौकरी की तारीख 6-7-80' का बनवाया और वर्ष 1984 में इस कार्ड के आधार पर रेल प्रशासन लाखेरी में 1-7-84 को केजुअल लेबर के रूप में नौकरी प्राप्त की?
- (2) क्या अप्रार्थी नियोजक ने समझौता कार्यवाही के लम्बित रहते हुए प्रार्थी श्रमिक को दि. 16-7-91 को सेवा में पृथक् कर अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है?
- (3) क्या रेल प्रशासन द्वारा प्रार्थी कैलाश की सेवाएं दि. 16-7-91 के आदेश से समाप्त करने का आदेश उचित एवं वैध है?

11. यद्यपि प्रार्थी श्रमिक ने स्टेटमेंट आफ क्लेम में अपनायी गयी दूषित जांच प्रक्रिया पर विस्तृत टिप्पणी अंकित की है, किन्तु श्री ग्रोवर ने मेरे समक्ष जांच की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने केवल यह युक्ति प्रकट की है कि सहायक अभियन्ता सवाईमाधोपुर प्रार्थी का नियोजक नहीं है और उसे प्रार्थी को आरोप-पत्र देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैंने शिड्यूल आफ पावर का अध्ययन किया। इसके ग्रुप-डी में वर्णित कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र देने की शक्ति सहायक अभियन्ता को प्राप्त है और हस्तगत मामले में भी प्रार्थी कैलाश जोकि केजुअल लेबर के रूप में कार्यरत था, को सहायक अभियन्ता सवाईमाधोपुर द्वारा आरोप-पत्र देने एवं उसके विरुद्ध विभागीय जांच कर दण्डित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री ग्रोवर का उपर्युक्त तर्क निराधार एवं नियम विरुद्ध होना पाया जाता है।

12. यद्यपि स्टेटमेंट आफ क्लेम में प्रार्थी ने यह बिन्दु उठाया है कि उसे जांच के दौरान सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये गये, किन्तु श्री ग्रोवर ने बहस के दौरान इस बिन्दु पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। उनका केवल मात्र यह तर्क है कि प्रार्थी को जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवायी गयी है और इसके अभाव में वह उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वंचित रहा था। जबकि इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री पाठक का तर्क है कि प्रार्थी को जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी थी जो दि. 7-8-91 को उसे प्राप्त हो गयी थी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी ने भी यह स्वीकार किया है कि उसे सेवा से मुक्त करने

का आदेश 7-8-91 को प्राप्त हुआ गया था जिसकी पुष्टि पर जांच रिपोर्ट अंकित है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि स्वयं प्रार्थी ने इस जांच रिपोर्ट की फोटो-प्रति न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री गोवर का यह तर्क पूर्णरूपेण आधारहीन एवं बेबुनियाद होना पाया जाता है।

13. अप्रार्थी नियोजक की ओर से सहायक अभियन्ता, सवाईमाधोपुर ने जो आरोप-पत्र प्रार्थी कैलाश को दिया था और जो अभिकथन का विवरण संलग्न किया था वह निम्न प्रकार है :—

“श्री कैलाश पुत्र रामरतन, केजुअल लेबर जोकि रेल पथ निरीक्षक सी.टी.आर./पी.क्यू.आर.एस. के यहां पर कार्यरत है, ने जाली सर्विस कार्ड बनवाकर रेलवे में नौकरी की है तथा उसने रेलवे प्रशासन को धोखा दिया है। अतः वह इस धोखा धड़ी का दोषी ठहराया जाता है क्योंकि यह गंभीर कदाचार है।”

14. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त आरोप अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जांच उपरान्त सिद्ध पाया गया है और इसी आरोप में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दि. 16-7-91 के आदेश में सेवा मुक्ति के दण्ड में दण्डित किया गया है। अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी श्रमिक कैलाश ने वर्ष 1984 में पी. डब्ल्यू.आई. लाखेरी कार्यालय में भरती होते समय जो पुराना सर्विस कार्ड प्रस्तुत किया था, वह फर्जी था क्योंकि वह कार्ड रेलवे प्रशासन द्वारा दि. 6-7-80 को जारी नहीं किया गया था। जाली सर्विस कार्ड बनवाकर रेलवे प्रशासन को धोखा देकर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दोषी पाया जाकर उसे सेवा मुक्ति के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है, किन्तु अप्रार्थी यह स्पष्ट करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है कि अप्रार्थी को यह कब ज्ञात हुआ कि प्रार्थी ने जाली कार्ड बनवाकर रेलवे में नौकरी प्राप्त की थी? अप्रार्थी न्यायाधिकरण में यह कहकर आया है कि प्रार्थी कैलाश ने जो नैमित्तिक मजदूरी का सेवाभिलेख पी. डब्ल्यू.आई. कार्यालय, लाखेरी में प्रस्तुत किया था, उसमें प्रारम्भिक नौकरी की तारीख “6-7-1980” अंकित है, जबकि प्रार्थी कैलाश ने 6-7-80 से रेलवे प्रशासन में कहीं भी नौकरी प्रारम्भ नहीं की थी। अप्रार्थी ने साक्ष्य में श्री मित्रा सिंह तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, सवाईमाधोपुर को परीक्षित करवाया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ना तो विवादित सर्विस कार्ड ही न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया है और ना ही पी.डब्ल्यू.आई. लाखेरी द्वारा विवादित जाली सर्विस कार्ड को सत्यापित करवाये जाने के सम्बन्ध में सत्यापित रिपोर्ट न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की है। बहस के दौरान भी अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री पाठक ने ऊंची आवाज में विश्वास भरे शब्दों के साथ यह दलील पेश की है कि यदि प्रार्थी आज भी यह साबित कर दे कि उसने वर्ष 1984 से पूर्व, अर्थात् 6-7-80 से रेलवे में हिन्दुस्तान में

कहीं भी नौकरी प्रारम्भ की थी तो वह आज भी प्रार्थी को उसकी सेवा में लेने को तैयार हैं। मैंने अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के इस तर्क को बहुत शान्त चित्त से सुना। ऐसा प्रतीत होना है कि श्री पाठक ने बहस करने के पूर्व उसके स्वयं के द्वारा परीक्षित साक्षी मित्रा सिंह पुत्र दुनोराम कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, सवाई-माधोपुर के शपथ पर दिये गये कथनों का अवलोकन नहीं दिया था। यदि हम श्री मित्रा सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिये गये बयानों का अवलोकन करें तो प्रतिपरीक्षा में दिये गये कथनों की प्रारम्भिक पंक्ति में ही इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके रेलवे रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी सर्वप्रथम केजुअल लेबर के रूप में 6-7-80 को भरती हुआ था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा दिया गया कथन यहां उद्धृत किये जाने योग्य है जो निम्न है :—

“हमारे रिकार्ड अनुसार प्रार्थी को 6-7-80 को केजुअल लेबर के रूप में भर्ती हुआ जो मुख्य गाड़ी परीक्षक, कोटा में भर्ती हुआ था। परन्तु लाखेरी में 1-7-84 को सेवा में नियोजित हुआ जो केजुअल लेबर के रूप में नियोजित हुआ था। प्रार्थी श्रमिक 6-7-80 को उक्त गाड़ी निरीक्षक के यहां भर्ती हुआ, इसका इन्दाज प्रार्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा कार्यालय में सर्विस कार्ड प्रस्तुत किया, उसमें लिखा है। उक्त कार्ड अनुसार 6-7-80 से 27-7-80 तक कार्यरत रहा था। मूल सर्विस कार्ड हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है।”

15. इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी कैलाश केजुअल लेबर के रूप में मुख्य गाड़ी परीक्षक, कोटा के यहां 6-7-80 को भरती हुआ था। किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कहीं भी कथन नहीं किया है कि वह यह बयान प्रार्थी कैलाश द्वारा प्रस्तुत जाली सर्विस कार्ड के आधार पर दे रहा हो। उसका तो यह कथन रहा है कि वह यह कथन उनके यहां कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दे रहा है। इस स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्षी मित्रा सिंह की साक्ष्य से ही यह साबित है कि प्रार्थी कैलाश 1-7-1984 से पूर्व 6-7-80 को भी केजुअल लेबर के रूप में मुख्य गाड़ी परीक्षक, कोटा के यहां भरती हुआ था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने प्रार्थी कैलाश के इस नैमित्तिक मजदूरी का सेवा रिकार्ड किस प्रकार जाली एवं फर्जी पाया, के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायाधिकरण में प्रस्तुत नहीं की है और ना ही इसका आधार पेश किया है। केवल मात्र यह कह देने से कि जांच के दौरान प्रार्थी का सर्विस कार्ड जाली पाया गया है, प्रार्थी को सेवा मुक्ति के दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता, जब तक कि अप्रार्थी न्यायाधिकरण में यह साबित नहीं कर दे कि उसकी इस अन्तिम राय का यह मुख्य आधार है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने उस व्यक्ति को भी जांच के दौरान परीक्षित नहीं करवाया है जिसके द्वारा यह जाली कार्ड तैयार किया गया था, ना ही

जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के सर्विस कार्ड पर जो मोहर लगी हुई है वह रेलवे के कार्यालय की नहीं है और फर्जी है और ना ही यह निष्कर्ष निकला है कि जिस अधिकारी के इस कार्ड पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, इस नाम का अधिकारी रेलवे में इस पद पर तत्समय कार्यरत में पदस्थापित नहीं था। यद्यपि अप्रार्थी द्वारा मूल सर्विस कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि इसकी फोटोकॉपी के प्रवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सर्विस कार्ड जारी करने वाले एवं बनाने वाले अधिकारी का नाम एन. के. शुक्ला है। अप्रार्थी द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि आया एन. के. शुक्ला नाम का अधिकारी तत्समय कार्ड में दर्शित स्थान पर कार्यरत था अथवा नहीं? और ना ही अप्रार्थी इस निश्चित साक्ष्य के साथ हमारे समक्ष आया है कि एन. के. शुक्ला नाम का अधिकारी उस समय रेलवे प्रशासन में कार्यरत ही नहीं था।

16. मैंने जांच रिपोर्ट का प्रवलोकन किया। जांच रिपोर्ट के पैरा 5 में जांच अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कर्मचारी कैलाश द्वारा प्रस्तुत कार्ड फर्जी है। उसने, दस्तावेजिक सर्विस दि. 1-7-84 को जारी की थी न कि 6-7-80 को। इस जांच रिपोर्ट के पैरा 4 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी कैलाश ने प्रथम भारती की तारीख 6-7-80 मुख्य गाड़ी परीक्षक; कोटा के यहां की अंकित की है, न कि कोटा-चित्तौड़ की। जब अप्रार्थी का स्वयं का साक्षी यह स्वीकार करता है कि उनके कार्यालय के रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी कैलाश मुख्य गाड़ी परीक्षक, कोटा के यहां केजुल लेबर के रूप में भारती हुआ था तो फिर इस साक्षी की साक्ष्य के परिणाम में प्रार्थी कैलाश द्वारा प्रस्तुत सर्विस कार्ड को भला जाली कैसे ठहराया जा सकता है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पूर्णरूपेण तथ्यों एवं अभिलेख के विरुद्ध है, जिसे सही स्वीकार किये जाने का अभिलेख पर कोई आधार नहीं है। अभिलेख पर अप्रार्थी ने इस आशय की शेष मात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रार्थी कैलाश ने रेलवे प्रशासन को धोखा देने की नियत से नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक जाली सर्विस कार्ड प्रस्तुत किया था।

17. जहां तक अधिनियम के धारा 33 का प्रावधानों का अप्रार्थी द्वारा उल्लंघन किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कोटा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी, दोनों को जारी नोटिस ए-11 एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सहायक श्रमायुक्त/केन्द्रीय कोटा ने नोटिस पत्र दिनांकित 1-8-91 के द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी, दोनों को यह सूचित किया था कि दोनों पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 16-8-91 की तारीख नियत की गयी है और दोनों पक्षों को उस दिन 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। दोनों पक्षों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे इस सुलह सम्बन्धी-संराधन-कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से या अपने सम्पत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों और साथ में सम्बद्ध अभिलेख, कागजात

तथा साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी भी साथ में लावे ताकि विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जा सके किन्तु अप्रार्थी ने इस नोटिस को प्राप्त करने के उपरान्त भी दि. 16-8-91 समझौते की नियत तिथि के पूर्व ही दि. 16-7-91 को प्रार्थी कैलाश की सेवा से मुक्त कर दिया जिसकी सूचना दि. 7-8-91 को प्रार्थी को प्राप्त हो गयी अधिनियम, 1947 की धारा 33 में निम्न प्रावधान प्रावधित हैं :—

"33(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a BoA or any proceeding before (an arbitrator or) a Labo Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial dispute, no employer shall,—

- (a)
- (b) for any misconduct connected with the dispute discharge or punish, whether by dismissal otherwise, any workman concerned in the dispute,

save with the express permission in writing of authority before which the proceeding is pending

18. उपर्युक्त प्रावधान में विधायिका द्वारा शब्द Sha- का प्रयोग किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधिनियम के धारा 33 के प्रावधान आज्ञापक हैं। धारा 33 के अन्तर्ग कोई भी नियोजक समझौता अधिकारी अथवा मण्डल अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सम्मुख औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित दुराचरण के मामले के सम्बन्धित रहते हुए, श्रमिक को सेवा से मुक्त अथवा अन्यथा किसी दण्ड से दण्डित नहीं कर सकता है, जब तक कि नियोजक ने लिखित में उस प्राधिकार से जिसके कि समझ समझौता कार्यवाही अथवा विवाद सम्बन्धित कार्यवाही सम्बन्धित है, अनुमति प्राप्त न करे हो। हस्तगत मामले में समझौता कार्यवाही, सहायक श्रमायुक्त/केन्द्रीय कोटा के समक्ष सम्बन्धित थी और उस समझौता कार्यवाही की तिथि 16-8-91 दोनों पक्षों की उपस्थिति हेतु नियत थी जिसमें दोनों पक्षों की सुलह दस्तावेजात, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेकर आने लिए पाबन्द किया गया था, किन्तु अप्रार्थी ने सहायक श्रमायुक्त/केन्द्रीय कोटा के इस नोटिस की पूर्ण रूपे अनदेखी कर प्रार्थी कैलाश को सम्बन्धित जांच कार्यवाही बोली पाकर दिनांक 16-8-91 के पूर्व ही दिनांक 16-7-91 को सेवा से पृथक् करने का मनमाना एवं विधि विरुद्धादेश पारित कर दिया जो पोषण किये जाने योग्य नहीं है।

19. हस्तगत मामले में एक और रोक्क तथ्य जो हम सामने उभरकर आया है वह यह है कि प्रार्थी द्वारा जांच सर्विस कार्ड पेश करने का ज्ञान अप्रार्थी को 25-11-88 को हुआ और उन्होंने जाली सर्विस कार्ड प्रस्तुत कर रेल प्रशासन में धोखा देकर नौकरी प्राप्त करने के दुष्प्रचार का आरोप-पत्र प्रार्थी को दि. 5-3-88 को ही दे दिया अर्थात् हस्तगत मामले में प्रार्थी के अपराध का

अप्रार्थी की बाढ़ में हुआ है और उस अपराध का आरोप-पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उससे पूर्व दि. 5-3-88 को ही दे दिया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी किस सीमा तक प्रार्थी के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित था और उसे येन केन प्रकारेण सेवा से मुक्त करने पर आमादा रहा।

20 अभिलेख पर ग्राह्य साक्ष्य एवं दस्तावेजों के उपर्युक्त दिवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सम्प्रेषित निर्देश-विवाद अनुसूची को इस प्रकार अधिनिर्णय कर उत्तरित किया जाता है कि अप्रार्थी रेलवे प्रशासन (डीआरएम, वेस्टर्न रेलवे) कोटा द्वारा प्रार्थी श्रमिक कैलाश पुत्र श्री रामरत्न, टी. एस गेगमन को दि० 10-7-91 से सेवा से पृथक् करने का कृत्य पूर्णरूपेण अनिष्ट एवं अवैध है और उसे सगरत निछले पल्लिभो एवं सेवा की निरन्तरता सहित पुनः सेवा में पदस्थापित होने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

अधिनिर्णय आज दिनांक 6-11-2000 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 59.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि के प्रबन्धन के सदस्य नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/अथवा न्यायालय, कोटा के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

स. एल-12012/53/99-आई आर (बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

59- In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Rajasthan Ltd and their workman which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-12012/53/99-IR(B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण/केन्द्रीय/कोटा/राज. पठमन अधिकारी श्री महेश चन्द्र भगवती, आर एच.जे.एस.

निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ. न्या. 26/99

दिनांक स्थापित 13-9-99

प्रसंग :- भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल-12012/53/99-आई.आर.

(बी-1) दिनांक 16-8-99

निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1)(घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

बाबूलाल लुहार पुत्र श्री रामगोपाल

—प्रार्थी श्रमिक

एवं

बी जनरल मैनेजर, बी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड, सेन्ट्रल ऑफिस, संरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर।

—अप्रार्थी निरोजक

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री डी.आर. त्रिवेदी
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री जी. पी. मालू
अधिनिर्णय दिनांक : 2-11-2000

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपनी उक्त आदेश दिनांक 16-8-99 के जरिये निम्न निर्देश/विवाद अनुसूची, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तदुपरान्त "अधिनियम" से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of Rajasthan Bank, Jaipur through its Branch Manager, Morak Branch, District Kota for not allowing to work to Shri Babulal Luhar from 16-5-98 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from what date?"

2. निर्देश विवाद अनुसूची इस न्यायाधिकरण को प्राप्त होने पर संजीवित उपरान्त पक्षकारों को सूचना जारी की गयी जिस पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्ताव केम स्टेट-मेंट प्रस्तुत किया गया।

3. यह पताचली अप्रार्थी के जवाब के लिए दि. 9-10-2000 को नियत थी परन्तु इसी दौरान पक्षकारों द्वारा यह प्रकट करने पर कि उनके मध्य राजीनामे की बात चल रही है, पताचली आज की पेशी के लिए उक्त प्रयोजनार्थ नियत की गयी। आज प्रार्थी श्रमिक स्वयं बाबूलाल लुहार मध्य अधिकृत प्रतिनिधि श्री डी. आर. त्रिवेदी व अप्रार्थी प्रबन्धक श्री जी. पी. मालू ने संयुक्त रूप से एक समझौता न्यायाधिकरण में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि चूंकि प्रस्तुत निर्देश-विवाद के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य लोक न्यायालय की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझौता सम्पन्न हो गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है, अतः प्रस्तुत शुद्ध समझौते के प्राप्ति पर अधिनिर्णय पारित कर दिया जावे।

4. दोनों पक्षों को प्रस्तुतगुदा समझौता-पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे दोनों पक्षों ने सही होना स्वीकार किया तदुपरान्त समझौता तस्दीक किया जाकर शामिल पताचली किया गया। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य

सम्बन्धित निर्देश-विवाद के सम्बन्ध में लोक न्यायालय की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझौता सम्पन्न हो गया है और समझौते उपरान्त अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है तथा न्यायाधिकरण द्वारा भी समझौते के अवलोकन से दोनों पक्षों के हित में प्रतीत होता है और दोनों पक्ष इस समझौते से सम्बद्ध रहेंगे। अतः समझौते के आश्रय पर इसी प्रकार अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

इस अधिनिर्णय को समुचित सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 60.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, कोटा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कोटा के रैंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एस-41011/29/95-माई आर (बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 60.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Kota and their workman which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-41011/29/95-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण (केन्द्रीय) कोटा राज. पीठासीन अधिकारी : श्री महेश चन्द्र भगवती, आर. एच. जे. एस.

निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ. न्या. /केन्द्रीय/9/1997
दिनांक स्थापित : 22-2-97

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश सं. एस-41011/29/95-माई आर (बी-1) दिनांक 7-2-97

निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1)(घ)
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

कजोड़लाल एवं अन्य द्वारा सचिव, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, मण्डल कार्यालय स्टेट बैंक बिकानेर एण्ड जयपुर के सामने, भीमगंज मण्डी कोटा जंक्शन।

—प्रार्थीगण श्रमिक

एवं

डी. आर. एम. वेस्टर्न रेलवे, कोटा।

प्रतिनिधि

उपस्थित

प्रार्थीगण श्रमिक की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : श्री आर. म. गुप्ता
अधिनिर्णय दिनांक : 17-11-2000

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 7-2-97 के जरिये निम्न निर्देश-विवाद/अनुसूची, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (विवाद तदुपरान्त "अधिनिर्णय" से सम्बोधित किया जावेगा) को धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सन्निहित किया गया है :—

"Whether the action of the DRM, Western Railway, Kota in reverting the workman Shri K. Jodlal and Shri Lodakilal, well sinker from the post of well sinker skilled category grade of Rs. 950—1500 after having worked for about four years, is legal and justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?"

2. निर्देश-विवाद अनुसूची न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर पंजीकृत उपरान्त पक्षकारों को सूचना मिली जा रही थी कि गयी जिस पर दोनों पक्षों की ओर से आने-प्राने अध्यावेदन न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये गये।

3. आज पत्रावली वाले नेश होत जहाँ मांगें निराश थी, परन्तु ना तो स्वयं प्रार्थीगण आज उपस्थित हुए है और ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो जायित्व है तथा ना ही कोई कितो प्रकार को पक्ष न्यायाधिकरण के सक्षम उपस्थित कदाभी गयी है। तमकि वह पत्रावली इस प्रयोजनार्थ दि. 5-5-2000 से न्यायाधिकरण में लम्बित चली आ रही है। परान्त सारा दिये जाने, कोई युक्तिमूलक कारण नहीं बतवारी जये व आज उांओ ओर से कोई उपस्थित नहीं होत त ना तमकि हेतु और ना तमकि दिये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होत और प्रांओ पक्ष की साक्ष्य का अवसर सज्जत किया जाता है।

4. पत्रावली के अन्तर्गत से स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत कान स्टेटमेन्ट के तर्जान में कितो प्रकार को कोई साक्ष्य अनिवार्य पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जितो कि उांओ द्वारा प्रस्तुत कान में साक्ष्य तथ्यों को प्रमाणित माना जा सके। इतने निराले प्रार्थी नियोजक की ओर से भी प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कान स्टेटमेन्ट पूर्णतया अस्वीकार रहा है। प्रार्थी पक्ष पर यह भार सज्जत रहा है कि वह अपने कवेन करन को कित मोखिक अथवा प्रवेक्षण साक्ष्य से सिद्ध करे किन्तु प्रार्थीगण पर ऐसी साक्ष्य का पूर्ण अभाव रहा है। अतः प्रार्थीगण श्रमिक, अप्रार्थी नियोजक से सम्बन्धित निर्देश-विवाद/अनुसूची में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अधिनिर्णय आज दिनांक 17-11-2000 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 61.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, कोटा के प्रबन्धतंत्र के संवद्ध निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/193/94-आई आर (बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 61—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour court, Kota as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Kota and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-41012/193/94-IR(B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण / (केन्द्रीय) कोटा राज. पीठासीन अधिकारी श्री महेश चन्द्र भगवती आर.एच.जे.एम. निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ. न्या. (केन्द्रीय)-5/96
दिनांक स्थापित : 16-1-96

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या एल-41012/193/94-आई. आर. (बी-1) दिनांक 5-1-96 निर्देश अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

रोहम्मद सलीम द्वारा डिविजनल सेक्रेटरी, पी.आर.के.पी. स्टेशन रोड, कोटा।

—प्रार्थी श्रमिक

एव

धिनासी अभियन्ता (एस एण्ड सी) पश्चिम रेलवे, कोटा
—अप्रार्थी नियोजक

उपस्थित

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि : श्री ए.डी. शंकर
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : श्री जी.पी. मोनू
अधिनिर्णय दिनांक: 14-11-2000 डिप्टी सी.ई. (कंस्ट्रक्शन

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने उक्त आदेश दि. 5-1-96 के जरिये निम्न निर्देश-विवाद/अनुसूची, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of Executive Engineer (S&C) W. Rly., Kota in not giving seniority to the Workman, Shri Mohamed Salim S/o Yasin Khan, Khalasi taking into account his initial engagement as Casual Labour w.e.f. 25-12-1973 and not absorbing him in open line on permanent basis at par with the juniors is legal and justified? If not, what relief the concerned workman is entitled to and from what date?"

2. निर्देश-विवाद/अनुसूची न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर पंजीबद्ध उपरान्त पक्षकारों को सूचना विधिवत जारी की गयी जिस पर दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने अग्रभावेदन न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किये गये।

3. आज पत्रावली वास्ते साक्ष्य श्रमिक पक्ष नियत थी परन्तु ना तो स्वयं प्रार्थी श्रमिक उपस्थित हुआ है, ना ही कोई साक्ष्य उपलब्ध करायी गयी है और ना ही कोई युक्तियुक्त कारण बतलाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि पत्रावली प्रार्थी की साक्ष्य में 22-10-99 से सम्बन्धित चली आ रही है परन्तु आज दिन तक भी अपने क्लेम समर्थन में कोई साक्ष्य किसी प्रकार की प्रस्तुत नहीं की गयी है। चूंकि प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत क्लेम स्टेटमेंट के समर्थन में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर क्लेम की सम्पुष्टि नहीं की गयी है, अतः प्रार्थी श्रमिक साक्ष्याभाव में सम्प्रेषित निर्देश-विवाद में अप्रार्थी नियोजक से किसी प्रकार का कोई अनुत्तोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और तदनुसार उक्त निर्देश-विवाद अधिनिर्णित किया जाता है।

अधिनिर्णय आज दिनांक 14-11-2000 को खुले न्यायाधिकरण में सुनाया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

महेश चन्द्र भगवती, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 62.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एन. के प्रबन्धतंत्र के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, वारंगल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22025/25/2000-सी-II]

एन. के. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 62.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of S.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-22025/25/2000-C-II]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL: CUM:
LABOUR COURT: WARANGAL

PRESENT :

Sri V. Appalanarasimham, B.Sc., B.L.,

Friday, the 24th day of November, 2000

INDUSTRIAL DISPUTE (CENTRAL)
No. 8 of 1998

BETWEEN :

K. Rajanarsu, Ex-General Mazdoor,
S/o Rajamallu,
Near C.S.I. Church,
Yellandu, Khammam Dist.-507 123.

.. Petitioner.

AND

The General Manager,
M/s S.C.C. Limited,
Ramagundam-III,
Godavarikhani.

.. Respondent

This Industrial Dispute coming on before me for hearing on 24-11-2000 upon perusing the reference, counter and all material documents on record and upon hearing Sri T. Ravinder Rao, Advocate for the Respondent, the being called absent, today this court passed the following Award :—

AWARD :

This petition is by way of reference by the Central Government of India Under Section 10(1)(d) of I.D. Act to decide "Whether Kirti Rajanarsu, Ex-General Mazdoor, Opancast Project-I, M/s S.C.C. Ltd., Godavarikhani dismissed from services w.e.f. 11-4-1993 is entitled for reinstatement with back wages? and Whether the dismissal is justified, proper

and legal? If not, to what relief he is entitled?"

2. Petitioner absent. Petitioner has not engaged any advocate or representative. Petitioner has not filed Claim Statement. Petitioner is not appearing to court to pursue his case. Petition is dismissed for default. Nil Award is passed accordingly.

Written and pronounced by me in the open court on this the 24th day of November, 2000.

V. APPALANARASIMHAM, Judge

Appendix of Evidence :

Witnesses Examined :

Documents Marked :

—Nil—

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. प्रा. 63.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबन्धन के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय गोदावरीखानी के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22025/25/2000-सी-II]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 63.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal Godavarikhani as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SCCL and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-22025/25/2000-C-II]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CHAIRMAN, INDUSTRIAL
TRIBUNAL, CUM-LABOUR COURT,
GODAVARIKHANI

PRESENT :

Sri P. Gurunadha Rao, B.Sc., B.L., Chairman-
cum-Presiding Officer.

Monday, the 18th day of September, 2000

Industrial Dispute No. 40 of 1996

BETWEEN

1. Kota Ramaswamy, S/o. Ilaiyah,
Aged 39 yrs., Singareni Employee,
R/o Q. No. T-2-209, P.H.C., Colony,
Godavarikhani.
2. Mudumba Krishnama Chari,
S/o. Varada Chari, Aged 55 yrs.,
Singareni Employee, R/o Q. No. T-2,
207, P.H.C. Colony,
Godavarikhani.

—Petitioners

AND

The General Manager,
RG-II, Singareni Collieries Co. Ltd.,
Godavarikhani.

—Respondent

This petition coming before me for final hearing in the presence of Sri P. Vishweswar Rao, Advocate for the petitioners and of Sri. C. S. N. Reddy, Advocate for the respondent and having stood over for consideration till this date, the court passed the following:—

AWARD

1. This is a reference by the Government of India. The reference is whether Sri K. Ramaswamy and Sri M. Krishnamacharyulu who are presently working as Record-Assistants in Accounts Department, in Singareni Collieries Company are entitled to promotion to Grade-II on completion of 9 years of service as per settlement dt. 3-3-89 on par with other employees namely, Paul Jayachander, Akula Ramulu, N. Surender Rao and Vijay Kumar.

Sri Kota Ramaswamy and Sri Mudumba Krishnamacharyulu filed common claim statement stating that they were working as Record-Assistants Clerical Grade-III for the last 10 years. By virtue of the settlement dt. 3-3-89, they are entitled to promotion from Clerical Grade-III to Clerical Grade-II.

2. Respondent filed counter stating that the post of Record-Assistant and Clerk, Grade-III are incidentally in the same pay-scale, but they are not identical or similar posts. The post of Record-Assistant is technical, Grade-E post. Chit issuers and number takers are Clerical Grade-III posts. Pay scales of technical Grade-E posts and Clerical, Grade-III posts are one and the same.

It is further stated that the statement dt. 3-3-89 provides for cadre schemes of tradesmen and clerks. The Record-Assistants are not covered by the above settlement deed.

It is further stated that the record-Assistants in technical, Grade-E are entitled to be promoted as Technical Grade-D.

3. WW-1 and WW-2 are examined and Ex. W-1 to Ex. W-6 are marked.

MW-1 is examined and Ex. M-1 to Ex. M-3 are marked.

4. Heard both sides.

5. The point for consideration is whether the claimants are entitled to be promoted as Clerk-Grade-II from Record-Assistant post.

6. POINT : Ex. W-1 is order dt. 4-12-84 in which the claimants were promoted as Record-Assistants in Clerical, Grade-III.

Ex. W-2 is letter dt. 28-3-85 stating that the claimants satisfactorily completed three months probation period and therefore they were confirmed as Record-Assistants, Clerical, Grade-III.

7. Ex. W-3 is letter dt. 26-12-94 addressed by the workers union to the General Manager (Personnel), Kothagudem requesting for promotion of Ramaswamy and Krishnamachary to Clerical, Grade-II.

8. Ex. M-1 is Memorandum of Settlement dt. 3-3-89. Annexure-II contains cadre scheme for clerical staff. It is provided that Graduates with typewriting lower grade certificate shall be recruited as Clerk, Grade-II.

Graduates presently on rolls in Grade-III who did not qualify in typewriting and non-graduates presently on rolls in Grade-III will be eligible for promotion to Grade-II during 10th year of service as Grade-III clerks.

9. Counsel for the respondent argued that the claimants have no minimum educational qualifications prescribed for the post of clerk, Grade-II. Therefore, they are not eligible for promotion to Grade-II clerical post.

10. Ex. W-1 office order dt. 4-12-84 shows that the claimants were peons before their promotion.

Ex. M-1 settlement, Annexure-II, condition No. 3 states that typewriting and Degree qualification are exempted to the in-service candidates working in Grade-III for nine years.

That does not mean that the in-service candidates need not have any minimum educational qualification. They must be having educational qualification below Degree, that means they must be having Intermediate qualification or at the minimum 10th class qualification.

A clerk may not be a typewriting qualified, may not be a Graduate, but he must be an Intermediate or at least 10th class passed.

There is no evidence to show that the claimants have got minimum educational qualification of Intermediate or 10th class passed. They were promoted from the post of peon.

11. WW-1 is Sri Kota Ramaswamy. He deposes that Mudumba Krishnamachary and himself were working as Grade-III clerks in the Accounts department. They were promoted to Grade-III clerks from he cadre of peon with effect from 1-12-84. Krishnamachary retired from service in January, 1998.

He further deposes that Krishnamachary and himself are not qualified in typewriting and they are not Graduates. As per Ex. M-1 settlement deed dated 3-3-89, they are eligible for promotion to Grade-II post.

He deposes in his cross-examination that in Ex. M-1 settlement deed, there is no reference to the post of Record-Assistant. He admitted that work inspector post and Record-Assistant post are Grade-III posts.

He further deposes that on 16-12-96, Krishnamachary and himself were promoted to Grade-D posts w.e.f. 1-7-95.

12. WW-2 Mudumba Krishnamachary, Claimant No. 2. He also deposes the same as WW-1.

13. MW-1 is Sri K. Chandramouli, Deputy Personnel Manager. He deposes that Claimant No. 1 was working as Record-Assistant. Prior to his promotion, he was working as peon. Claimant No. 2 was also promoted from the post of peon. The claimants are not entitled to promotion to clerical, Grade-II post.

He further deposes that the claimants were promoted to technical, grade-D post.

14. The claimants are not covered by the settlement dated 3-3-89 since the Record Assistant posts are not covered by the said settlement.

The claimants do not have minimum educational qualification as required for the post of clerk, Grade-II.

There is no evidence to show that the claimants have passed Intermediate examination or 10th class examination.

I therefore, consider that the claimants are not entitled to be promoted to the post of Clerical Grade-II from the Record-Assistant post. Hence, I answer the reference accordingly.

In the result, the reference is answered against the claimants. The claimants are not entitled to be promoted to the post of Clerical Grade-II from the post of Record-Assistant since they do not possess minimum educational qualification such as Pass in Intermediate examination or 10th class examination.

Typed to my dictation, corrected and pronounced by me in the open court on this, 18th day of September, 2000.

P. GURUNADHA RAO, Chairman-cum-Presiding Officer.

Appendix of Evidence
Witnesses examined

For Workman :—

WW-1—Kota Ramaswamy, Record-Assistant.

WW-2—Mudamba Krishnamachary, Retired employee.

For Management.

MW-1—K. Chandramouli, Dy. Personnel Manager, RG-I, S.C. Co. Ltd., Godavarikhani.

Exhibits

For Workman :—

Ex. W-1 dt. 4-12-84—Office order.

Ex. W-2 dt. 28-2-95—Confirmation letter of petitioner No. 2.

Ex. W-3 dt. 26-12-94—Representation letter of M. Komuriah, General Secretary, S. C., Workers union.

Ex. W-4 dt. 24/26-3-95—Representation of Y. Gattiah, Central Vice-President of S.C. workers union.

Ex. W-5 dt. 7-6-95 —do—

Ex. W-6 dt. 12-7-95—Minutes of the discussions held at G.M., RG-I office, Godavarikhani.

For Management :—

Ex. M-1 dt. 3-3-89—Memorandum of settlement between Management of SCCL and Representatives of Union of workmen.

Ex. M-2 dt. 12/16-12-96—Office order.

Ex. M-3 dt. 23-12-95—Circular issued by General Manager, RG-I.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

को. भा. 64—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एन. के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित आदेशों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम/अथवा आदेशों को लागू करने के पत्रों को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एम-22025/25/2000-मो-II]

एन पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 64.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal Godavarikhani as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of S.C.C.L., and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-22025/25/2000-C-II]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CHAIRMAN, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CUM-LABOUR COURT, GODAVARIKHANI

PRESENT :

Sri. P. Gurunadha Rao, B.Sc., B.L., Chairman-cum-Presiding Officer.

Tuesday—the 17th Day of October, 2000

Industrial Dispute No. 49 of 1997

BETWEEN

Kasipaka Shankar, S/o. Poshaiyah,
Age 38 yrs., Oce : Ex-Badli Filler,
Vill: and Post Irukula Durshel,
Dist. Karimnagar.

—Petitioner.

AND.

1. Colliery Manager,
GDK, No. VII A Incline,
Godavarikhani.
2. General Manager,
Singareni Collieries, RG-1,
Godavarikhani.
3. Managing Director,
S.C. Company Ltd, Kothagudem,
Dist. Khammam, Post
Kothagudem.

—Respondents.

This petition coming before me for final hearing in the presence of Sri, S Bhagavantha Rao, Advocate for the petitioner and of Sri, C. S. N. Reddy, Advocate for the respondents and having stood over consideration till this date, the court passed the following:--

AWARD

1. This is a petition filed U/s. 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, as amended by A. P. Amendment Act, 1987.

2. Facts of the case briefly are as follows :—

The petitioner was appointed as Badli Filler on 1-1-78. The petitioner fell sick for 15 days in January, 1981. He was removed from the service on 21-12-81. The petitioner worked for more than 240 days before he was removed from the service.

Respondent No. 2 filed counter stating that the petitioner was removed from the service on the ground of unauthorised absenteeism.

3. Ex. W-1 to Ex. W-5 are marked on behalf of the petitioner.

Ex. M-1 to Ex. M-3 are marked on behalf of the respondents.

4. Heard both sides.

5. The point for consideration is whether the petitioner can be reinstated into service.

6. POINT :—Ex. W-1 is appointment letter dt. 7-9-80. The petitioner was appointed as badli-filler temporarily for a period of three months.

Ex. W-2 is another appointment letter dt. 8-4-81. It shows that the petitioner was again appointed as badli-filler on piece rate wages.

Ex. W-3 is letter dt. 14-2-92. It shows that the petitioner applied for reinstatement and his application was not considered for re-appointment.

Ex. W-4 is letter dt. 3-10-89. It shows that the services of the petitioner were terminated in 1983 for absenteeism and therefore, his application dt. 14-7-89 was not considered.

It appears that the petitioner was terminated on 9-9-80.

He was re-appointed w.e.f., 10-4-81. Again he was terminated in 1983. For that, the petitioner applied for reinstatement on 14-7-89 and it was rejected on 3-10-89.

The petitioner again represented by filing an application dt. 13-5-91 for reinstatement and it was rejected on 14-2-92.

7. The present petition was filed on 27-12-96 i.e., 13 years after he was removed from the service in 1983.

8. Ex. M-1 is application of the petitioner dated 14-7-89. It shows that the petitioner was terminated in the year 1983 due to absenteeism.

The petitioner applied for reinstatement six years after he was removed from the service.

Ex. M-2 is application of the petitioner dt. 13-5-91. It shows that the petitioner filed many petitions to the respondents for his reinstatement, but he was not reinstated.

9. The petitioner was finally removed from the service in the year, 1983 for absenteeism. The present petition was filed on 27-12-96, i.e., more than 13 years after his removal.

It appears that the petitioner did not question his removal from the service for absenteeism prior to filing this petition.

The petitioner was filing application to the respondents for his reinstatement and they were being rejected.

10. The respondent cited a decision reported in Nedungadi Bank Ltd., Vs. K. P. Madhavan Kutti AIR 2000 Supreme Court Page 839.

In Para No. 6, it was held "Law does not prescribe any time limit for the appropriate Government to exercise powers U/s. 10 of the Act. It is not that this power can be exercised at any point of time and to revise the matter which had since been settled. Power is to be exercised reasonably and in a rational manner. There appears to us to be no rational basis on which the Central Government has exercised powers in this case after lapse of about 7 years of order dismissing the respondent from the service. At the time reference was made, no industrial dispute exist or would be even said to have been apprehended. A dispute which is stale could not be the subject matter of the reference U/s. 10 of the Act. As to when a Dispute can be said to be stale would depend on the facts and circumstances of each case. When the matter has become final, it appears to us to be rather incongruous that the reference be made U/s. 10 of the Act in the circumstances like the present one. In fact, it could be said that there was no dispute pending at the time when the reference in question was made. The only ground advanced by the respondent was that two other employees who were dismissed from service were reinstated. Under that circumstances

they were dismissed and subsequently reinstated is nowhere mentioned. Demand raised by the respondent for raising Industrial Dispute was ex-facie bad and incompetent".

It can be deduced from the above decision, that a petition for reinstatement cannot be made after lapse of reasonable time even though there is no limitation prescribed for filing petition U/s. 2-A(2).

10. In the present case, the petitioner was removed from the service in the year, 1983 on the ground of absenteeism. But it was mentioned in the petition that the petitioner was removed from the service on 21-12-81.

He was requesting the respondents for reinstatement, but his request was not considered. Finally, he filed the present petition in the year, 1996, i.e., 13 years after his removal from the service. Hence, I consider that the petitioner cannot be reinstated into service.

In the result, this petition is dismissed. Each party do bear their own costs.

Typed to my dictation, corrected and pronounced by me in the open court on this, 17th day of October, 2000.

P. GURUNADHA RAO, Chairman-cum-Presiding Officer

Appendix of Evidence
Witnesses-examined

For workman: Nil. For Management: Nil.
Exhibits

For workman:—

- Ex. W-1 dt. 7/8-9-80—Appointment letter.
- Ex. W-2 dt. 8/9-4-81—Appointment letter as badli filler.
- Ex. W-3 dt. 14-2-92—Letter issued to the petitioner by the General Manager, Personnel.
- Ex. W-4 dt. 3-10-89—Letter addressed to the petitioner by Director, Personnel, Admn. & Welfare.
- Ex. W-5 dt. 24-8-89—Mercy petition of the petitioner.

For Management:—

- Ex. M-1 dt. 14-7-89—Representation letter of the petitioner.
- Ex. M-2 dt. 13-5-91—do—
- Ex. M-3 dt. 21-3-90—Circular and Memorandum of settlement.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 65—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार हेवी वाटर प्रोजेक्ट के प्रबन्धन के संवद्ध 2 GI/2001/12.

नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, प्रत्यक्ष में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय वारंगल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22025/25/2000-सी-II]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 65.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Warangal as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-22025/25/2000-C-II
N. P. KESAVAN, Desk Officer]

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, CUM-
LABOUR COURT, AT WARANGAL

PRESENT :

Sri. V. Appalanarasimham, B.Sc., B.L.,
Judge.

Wednesday, the 20th day of September, 2000
Industrial Dispute (C) No. 14 of 1997

BETWEEN

E. Veeramallu S/o Buchaiah,
R/o Ashwapur (M),
Chintriyal-X-Road, Khammam. ..Petitioner.

AND

The General Manager,
Heavy Water Project, Manugur.
Dist. Khammam. ..Respondent

This industrial dispute coming on before me for final hearing on 18-8-2000, upon perusing the petition, counter and all documents on record and upon hearing the arguments of Smt. Satwath Rana, advocate for the petitioner and Sri M. Sada Sivudu, A.G. for the respondent, having stood over for consideration till this day the court passed the following:—

AWARD

The petitioner filed this petition under section 2-A (2) of I.D. Act to set aside the oral termination of the petitioner on 30-9-1986 and to direct the respondent to reinstate the petitioner into service as a worker with all benefits.

2. The brief averments in the petition filed by the petitioner are as follows:—The petitioner was appointed orally as helper in the Project of the respondent on 1-11-83 on consolidated pay of Rs. 350 per month. Respondent management made the HWP (M) Contract Workmen and Employees Union entered into a settlement before the A.C.L. (Central). Viavawar under section 12 (3) of I.D. Act. As per the said settlement, daily rated temporary employees shall be

continued in service without any break till Project is completed or regular appointment are made. But the petitioner was orally terminated on 30-9-86 in violation of terms of the said settlement. The said termination is illegal for not following the provisions of I.D. Act. Respondent/Management terminated the services of all casual labourers including the petitioner on 30-9-86. The retrenched workmen filed Writ Petition 14560/86 in the Hon'ble High Court of A.P. and it was dismissed with a direction to approach Industrial Tribunal. Accordingly I.D. 55/88 was filed in the Industrial Tribunal-I, Hyderabad. Award was passed in I.D. 55/88 by ordering reinstatement of retrenched workmen. The petitioner was not reinstated on the ground that his name was not there in the reference covered by I.D. 55/88. Other workmen were reinstated in terms of the Award in I.D. 55/88. Petitioner worked continuously for more than 240 days in any year from 1-11-83 to 30-9-86. The petitioner was under the impression that his name was included in I.D. 55/88. The Petitioner filed conciliation application before A.C.L. (Central), Hyderabad. It was not referred to Industrial Tribunal till to-day. So petitioner filed this petition under section 2-A(2) of I.D. Act to set aside the oral termination on 30-9-86 and to direct the respondent to reinstate the petitioner into service. Hence the petition.

3. The brief averments in the counter filed by the respondent are as follows:—The material averments in the petition are not true and correct. The petitioner was not appointed on 1-11-83 on monthly wages of Rs. 350. The petitioner worked as daily rated semi skilled casual labour for 30 days in December, 85, for 26 days in February, 86, and for 17 days in July, 86, and was paid daily wages for the period of work. The copies of the musterrolls for the above three months are filed along with counter. On 8-7-1986, an agreement was entered into between the workers Employees Union and Management, subsequently the retrenched worker filed I.D. 55/88 in Industrial Tribunal, Hyderabad. List of 185 employees as casual employees was enclosed to the award in I.D. 55/88 passed on 3-12-1990. The award was implemented in true word and spirit. Petitioner was not one of the workmen in the list of 185 persons enclosed to the Award in I.D. 55/88. The services of the petitioner were not discontinued by the management. Petitioner might have absconded from duties long before filing I.D. 55/88. After lapse of 10 years from the date of disengagement and seven years from the date of award, petitioner approached this Tribunal with a mala fide intention to gain wrongfully. Petitioner never worked continuously from 1-11-83 to 30-9-86 and never completed working for 240 days in any calendar year in the above period. So provisions under section 25-F of I.D. Act are not applicable to the case of the petitioner. The case of the petitioner was not considered since his name is not found in award in I.D. 55/88. This petition is filed with a mala fide intention to gain wrongfully if possible. The petition is liable to be dismissed.

4. No witnesses are examined on behalf of the petitioner. MW-1 is examined on behalf of the respondent and Exs M-1 to M-6 are marked. Arguments of the advocate for the petitioner and A.G.P. for respondent are heard.

5. The point for consideration is whether the petitioner worked as helper in the Project of the respondent for any period and whether he worked continuously for 240 days in 12 months preceding the date of removal and if so, whether oral termination of the petitioner by management, is any, on any date, is in violation of section 25-F of I.D. Act and if so, to what relief the petitioner is entitled to?

6. POINT :—It is averred in the petition that petitioner was appointed orally as Helper in the Project of the respondent on 1-11-83 and that he worked continuously upto 30-9-86, when he was orally removed from service. Petitioner has not chosen to give evidence before this Tribunal in support of the averments in the petition as to the date of appointment, the period of service and date of removal. In the counter, the management has taken specific plea in para 6.2, that petitioner worked for 31 days in December, 85, for 26 days in February, 86 and for 17 days in July, 1986. It is mistakenly typed as December, 86 in the counter instead of December, 85. Retrenchment of most of the workmen were effected admittedly on 30-9-86 itself. So it is only a type mistake in para 6.2 of the counter, for typing as December, 86 instead of December, 1985. Xerox copies of muster rolls for above three months are also filed alongwith counter. It is further mentioned in the counter that petitioner was not on the rolls on 30-9-86 when several workmen were retrenched. The workers who were disengaged on 30-9-86 approached Industrial Tribunal, Hyderabad by filing I.D. 55/88. Award was passed therein on 3-12-1990 by enclosing the list of 185 persons, who shall be reinstated in terms of the award. The name of the petitioner is not amongst the said persons in whose favour the award was passed. It is specifically averred in the counter that petitioner was not on rolls by 30-9-86 and he might have left the service long before that date. It is mentioned in the petition that he was under impression that his name was included in the list of workmen in I.D. 55/88 and that in 1997 only, he came to know his name was not there in the said list, when his application to the management for reinstatement in terms of the said award was rejected.

7. On a close scrutiny of the averments in the petition and counter, it cannot be taken as a case of admission of appointment of petitioner on 1-11-83, his period of service and date of removal on 30-9-86 by the management. Management admitted only short spell of service of the petitioner between the December, 1985 to July, 1986 in specific number of days as stated in the counter. Respondent never admitted date of appointment of the petitioner as 1-11-83. Respondent also never admitted date of retrenchment of the petitioner alongwith other workmen on 30-9-86. The respondent also never admitted continuity of service for any period in between the above dates. When the respondent never admitted the date of appointment and date of removal of the petitioner, the initial burden is only on the petitioner to prove those aspects by acceptable evidence. Then only, the burden would shift on to the management to show that petitioner has not worked continuously for 240 days preceding the date of removal.

8. The advocate for the petitioner relied upon a decision reported in 1997 (3)-ALT-406(DB)—(M.

Chandrama Vs. Labour Court-I Hyderabad. It is held in the above case as follows :—

“Where relief is claimed by an illiterate person, burden lies on opposite party to prove that the petitioner is not entitled to the relief asked for.”

The facts in the above decision, disclosed that petitioner therein worked as sweeper under the employer for certain period. In those facts, it is held that burden is on the employer to prove that she has not completed 240 days, as she is illiterate workman.

In the above decision, the appointment of workman as Sweeper on a particular date and her removal on a date by management are admitted by the management. On those facts, it is held that the burden is on the management to prove that the illiterate workman has not completed 240 days. The above decision is not applicable to the facts of this matter. The respondent never admitted the date of appointment and date of removal of the petitioner. So, the initial burden will be on the petitioner only, to prove those two important aspects. Petitioner failed to give evidence in support of his averments in the petition to prove the said aspects. Petitioner is bound to examine one of the workers who worked alongwith him in the relevant period and who was retrenched from service alongwith him, besides giving evidence by himself in this petition. Without any acceptable evidence in those lines on behalf of the petitioner, it cannot be said that burden was shifted on to the respondent to show that petitioner has not worked continuously for 240 days in preceding 12 months prior to the date of removal. Admission of short service for few months without continuity between December, 85 to July, 1986 by the respondent cannot be taken as admission to the required fact, to keep the burden on management only to prove that petitioner has not worked continuously for 240 days in 12 calendar months prior to the date of removal. As the petitioner has not adduced any evidence in support of his wage the management is under no obligation to place and evidence in relation to the period of service of the petitioner.

9. However, M.W.-1 is examined on behalf of the respondent and Exs. M-1 to M-6 are marked. M.W.-1 clearly deposed that petitioner never worked for any period in November, 1983 and December, 1983. Ex. M-1 is the xerox copy of muster roll for November and December, 83. Name of the petitioner is not found in Ex. M-1 for the said two months. So the theory of the petitioner that he was appointed orally on 1-11-83 is nothing, but false. The name of the petitioner is found in Ex. M-2 for December, 85, at Sl. No. 7, in Ex. M-3 for February, 86 at Sl. No. 7 and in Ex. M-4 for July, 86 at Sl. No. 4. The respondent proved short service of the petitioner in three months covered by Exs. M-2 to M-4. Respondent also proved that petitioner was not appointed on 1-11-83. In the absence of any evidence from the petitioner, to prove the relevant aspects as stated supra, respondent is under no obligation to produce musters of all the years from November, 1983 to September, 1986. In the above circumstances and facts of the matter, no adverse inference can be drawn

against the respondent for non-production of muster rolls for the entire period from November, 1983 to September, 1986.

10. It is admitted by the petitioner himself that his name is not found in the list of workmen enclosed to the Award in I.D. 55/88. The theory of the petitioner that he came to know that fact seven years after the date of award in I.D. 55/88 cannot be believed to be true. It really the petitioner was on rolls as workman under the management of the respondent on 30-9-86, his name should have been found in the list of workmen in I.D. 55/88. Ex. M-5 is settlement between workers union and management dt. 8-7-86. Ex. M-6 is the xerox copy of award in I.D. 55/88. If there is any acceptable evidence before this Tribunal to believe that petitioner was on rolls under the employment of the respondent on 30-9-86, the relief granted by Industrial Tribunal in I.D. 55/88 can be given to the petitioner also. Award in I.D. 55/88 can be applied and the workmen returned on 30-9-86 and who were on the rolls as on 30-9-86. In this matter, the petitioner without giving any evidence before this court on any aspect and without any admission of relevant facts by the management, cannot be claim to have proved before this Tribunal that he was on rolls as workman of respondent on 30-9-86. This Tribunal has no hesitation to hold, on appreciation of facts and circumstances, that petitioner was dis-engaged long before 30-9-86 and that petitioner worked only for short period between December, 1985 to July, 1986 without any continuity of service. In these circumstances, presumption cannot be drawn that petitioner worked continuously for 240 day in a calendar months preceding 30-9-86. On appreciation of evidence available before this Tribunal, this Tribunal has no hesitation to hold that petitioner never worked for 240 days continuously in any calendar year from 1-11-83 to 30-9-86 and muchless in 12 preceding months to 30-9-86. There is no evidence to believe that petitioner was on rolls on 30-9-86. This Tribunal also has no hesitation to hold that petitioner was dis-engaged by the management long before 30-9-86 and that he was not on the rolls in the list of workmen of the respondents on 30-9-86. The petitioner slept over for 11 years from the date of alleged removal. He kept quiet for seven long years from the date of Award in I.D. 55/88 dt. 3-12-90. After laps of seven years from that date, petitioner approached this Tribunal with a mala fide intention to win wrongfully if possible, by taking advantage of relief granted to the retrenched workman in I.D. 55/88. Therefore, this Tribunal has no hesitation to hold that petitioner never worked continuously for 240 days in preceding 12 months prior to the date of removal and so, the termination is not in violation of Section 25-F of I.D. Act and so the petitioner is not entitled for any relief in this petition. The petition is liable to be dismissed. Point is answered accordingly.

11. In the result, an award is passed holding that petitioner never worked continuously for 240 days in the period if the respondent in preceding 12 months prior to the date of removal and so, the removal of the petitioner is not in the violation of section 25-F of I.D. Act, and so, the petitioner is not entitled any relief against the respondent. Petition is dismissed accordingly. This award shall become enforceable

on expiry of 30 days from the date of its publication under section 17 of the I.D. Act, by virtue of the powers conferred under section 17-A (1) of the Act.

Dictated to stenographer and transcribed by him, corrected and pronounced by me in the open court and given under my hand and seal of this court on 20th day of September, 2000.

V. APPALANARASIMHAM, Judge.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined:

For petitioner, workman :

—None—

For Respondent : Management:
M.W-1—10-8-2000 G. K. Sahoo.

EXHIBITS MARKED :

For Petitioner : Workman : —Nil—

For Respondent : Management:

Ex. M-1 — : Xerox copy of Muster Rolls for November and December, 83.

Ex. M-2 — : Xerox copy of Muster Roll for December, 1985.

Ex. M-3 — : Xerox copy of Muster Roll for February, 1986.

Ex. M-4. — : Xerox copy of Muster Roll for July, 1986.

Ex. M-5 8-7-86.—Xerox copy of Minutes proceeding before Asstt. Labour Commissioner, Vijayawada.

Ex. M-6. — 3-12-90 : Xerox copy of award in I.D. 55/88 before Industrial Tribunal at Hyderabad.

नई दिल्ली 29 दिसम्बर, 2000

का. आ. 66.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हेवी वाटर प्रोजेक्ट के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/अम न्यायालय वारंगल के पचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार ने 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-22025/25/2000-सी-II]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 2000

S.O. 66.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Warangal, as given in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of

Heavy Water Project and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-22025/25/2000-C-II]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT AT WARANGAL

PRESENT :

Sri V. Appalanarasimhan, B.Sc., B.L., Judge.

Wednesday, the 20th day of September, 2000

INDUSTRIAL DISPUTE (Central) No. 15 of 1997

BETWEEN

Kengaru Narsimha Rao S/o Jogaiah
R/o Yenkur (M) & (P),
Dist. Khammam, ...Petitioner.

AND

The General Manager,
Heavy Water Project, Manuguru,
Dist. Khammam. ...Respondent.

This Industrial Dispute coming on before me for final hearing on 18-8-2000, upon perusing the petition, counter and all documents on record and upon hearing the arguments of Smt. Satwath Rana, Advocate for the petitioner and Sri N. Sada Sivudu, A.G.P., for the respondent, having stood over for consideration till this day the court passed the following:—

AWARD

The petitioner filed this petition Under Section 2-A(2) of I.D. Act to set aside the oral termination of the petitioner on 30-9-1986 and to direct the respondent to reinstate the petitioner into service as a worker with all benefits.

2. The brief averments in the petition filed by the petitioner are as follows.—The petitioner was appointed orally as helper in the Project of the respondent on 1-11-1983 on consolidated pay of Rs. 350 per month. Respondent/management and the H.W.P.(M) contract workmen and Employees Union entered into a settlement before A.C.L. (Central), Vijayawada under Section 12(3) of I.D. Act. As per the said settlement, daily rated temporary employees shall be continued in service without any break till Project is completed or regular appointments are made. But the petitioner was orally terminated on 30-9-1986 in violation of terms of the said settlement. The said termination is illegal for not following the provisions of I.D. Act. Respondent/Management terminated the services of all casual labourers including the petitioner on 30-9-1986. The retrenched workmen filed Writ Petition 14560/86 in the Hon'ble High Court of A.P. and it was dismissed with a direction to approach Industrial Tribunal. Accordingly I.D. No. 55/88 was filed in the Industrial Tribunal-I, Hyderabad. Award was passed in I.D. 55/88 by ordering reinstatement of retrenched workmen. The petitioner was not reinstated on the ground that his name was not there in the reference covered by

I.D. 55/88. Other workmen were reinstated in terms of the Award in I.D. 55/88. Petitioner worked continuously for more than 240 days in any year from 1-11-1983 to 30-9-86. The petitioner was under the impression that his name was included in I.D. 55/88. The petitioner filed conciliation application before A.C.L. (Central), Hyderabad. It was not referred to Industrial Tribunal till today. So petitioner filed this petition under Section 2-A(2) of I.D. Act to set aside the oral termination on 30-9-1986 and to direct the respondent to reinstate the petitioner into service. Hence the petition.

3. The brief averments in the counter filed by the respondent are as follows.—The material averments in the petition are not true and correct. The petitioner never worked in the Project of the respondent in any period. Petitioner was not terminated from services by the respondent. Petitioner was not party to any dispute and settlement dated 8-7-1986. Petitioner was not a party to I.D. 55/88. There was no relationship of workman and employer between the petitioner and respondent. All the allegations in the petition about his services are absolutely false. There are no merits in the petition. The petition is liable to be dismissed.

4. The petitioner is examined as W.W.-1 and Exs. W-1 to W-4 are marked. M.W.-1 is examined on behalf of the respondent and Exs. M-1 to M-4 are marked. Arguments on the advocate for the petitioner and A.G.P. for respondent are heard.

5. The point for consideration is whether the petitioner worked as Helper in the Project of the respondent for any period and whether he worked continuously for 240 days in 12 months preceding 30-9-1986 and if so, whether oral termination of the petitioner on 10-9-1986 is in violation of Section 25-F of I.D. Act and if so, to what relief the petitioner on 10-9-1986 is in violation of Section 25-F of I.D. Act and if so, to what relief the petitioner is entitled

6. POINT.—It is averred in the petition that petitioner was appointed orally as Helper in the Project of the respondent on 1-11-1983 and that he worked continuously upto 30-9-1986, when he was orally removed from service. The petitioner as W.W.1 deposed in his evidence about said facts as stated in the petition M.W.1 categorically denied in his evidence the engagement of the petitioner on 1-11-1983 and also termination of petitioner on 30-9-86. M.W.1 deposed that petitioner never worked in the Project and that he was not removed from service by the management. It is a case of total denial of any relationship of workman and employer. So the initial burden is on the petitioner to show that he worked in the Project by oral appointment on 1-11-83 & that he worked continuously upto 30-9-86. When there is some satisfactory evidence on behalf of the petitioner in support of the averments in the petition, then only the burden would shift on to the respondent to prove that petitioner never worked continuously for 240 days in 12 months preceding the date of removal. Except the oral evidence of W.W.1, there is no supporting oral evidence for the petitioner. Petitioner has not chosen to examine any worker, who worked along with him in the relevant period and who was also removed from service on 30-9-1986. Petitioner

also has not examined any representative of the union of daily wage workers to show that petitioner worked in the Project in the relevant period. Exs. W-1 to W-4 are filed by the petitioner on his behalf.

7. Ex. W-4 is xerox copy of the Award in I.D. 55/88 dt. 3-12-90. Petitioner admitted that he was not a party in I.D. 55/88. According to the petitioner, he came to know of that fact only after disposal of I.D. 55/88 by passing award and when reinstatement was refused by the management. After passing award in I.D. 55/88, the petitioner demanded the respondents for reinstatement. Ex. W-1 is the xerox copy of minutes of conciliation proceedings held on 24-1-1995 between the management of the respondent and the petitioner, represented by Union Leader S. K. Hussain. It is clearly mentioned in Ex. W-1, petitioner cannot be reinstated as his name was not found in list Ex. C-1 of 185 employees enclosed to Award in I.D. 55/88. Ex. W-2 dated 31-3-95 is the failure report sent by A.C.L. Central Vijayawada to Secretary, Government of India Ministry of Labour, New Delhi. Exs. W-1 and W-2 are subsequent to passing of the Award in I.D. 55/88. Ex. W-3 is xerox copy of list containing names of 21 persons said to have joined on 1-10-86. There is no authenticity in any manner for Ex. W-3. There is no office seal of respondent on Ex. M-3. There are corrections in the figures 24 as '21'. Date as 1-10-86 was written on the typed paper. Ex. W-3 cannot be relied upon for any purpose. Petitioner has not filed any admissible documents to show that he was appointed on 1-11-1983 and that he worked continuously upto 30-9-86 and that he was orally terminated from service on that date. Exs. W-1 to W-4 are no way helpful to the petitioner to prove his appointment, period of service and removal on 30-9-1986.

8. Exs. 8-1 to M-4 are marked on behalf of the respondent M.W.-1 categorically deposed that petitioner never worked in the Project for any period and he was not removed from service by the management on 30-9-1986. In the counter, it is specifically pleaded that petitioner never participated in the conciliation proceedings held on 8-7-86. There is absolutely no evidence for the petitioner to any that he participated in the conciliation proceedings between the retrenched workers union and the management on 8-7-86. Ex. M-1 is xerox copy of muster roll maintained by respondent for November, 1983. Petitioner claims to have been appointed as helper orally on 1-11-1983 in the Project of the respondent. The name of the petitioner is not found in the entire month of November, 1983, as can be seen from Ex. M-1. Ex. M-2 is the xerox copy of muster roll for December, 1983. The name of the petitioner is also not found in the entire month of December, 1983. M.W.-1 clearly deposed in his evidence that original muster rolls of November and December of 1983 are filed in Industrial Tribunal-I, Hyderabad i.e. in I.D. 55/88. No management clearly explained reason for filing xerox copies of muster rolls of November and December, 1983, as Exs. M-1 and M-2 in this Tribunal. If the claim of the petitioner about the appointment on 1-11-1983 is true, his name should have been found in muster rolls for November and December, 1983 in Exs. M-1 and M-2. But his name is not found in the two months

as found supra. It would clearly throw a genuine doubt as to the theory of the petitioner about his appointment in November, 1983 and his services from 1-11-83 onwards. Ex. M-3 is the xerox copy of muster roll for February, 1986. The name of the petitioner is not found in Ex. M-1 also. Ex. M-4 is the xerox copy of attendance register of 24 retrenched casual labourers by showing the date of joining respectively against their names. Those 24 workers joined on 1-9-1986 and earlier and not after 1-9-1986.

9. On appreciation of oral and documentary evidence on behalf of the petitioner, this Tribunal has no hesitation to hold that petitioner failed to place any acceptable evidence to show that he was appointed orally as Helper in the Project of the respondent on 1-11-1983. He also failed to show that he worked continuously from 1-11-1983 to 30-9-1986. Petitioner also failed to prove that he was removed from service by retrenchment on 30-9-1986 alongwith other workers. On the other hand, the respondent proved that petitioner was not a workman in the Project of the respondent in any period. The name of the petitioner is not found in muster rolls of November and December, 1983 as in Exs. M-1 and M-2. His name is also not found in muster roll for February, 1986 under Ex. M-3. Respondent clearly proved that petitioner never worked in the Project for any period and muchless continuously for 240 days in 12 calendar months prior to 30-9-1986. So this Tribunal is not inclined to believe that petitioner worked in the Project of the respondent for any period and that he was retrenched alongwith other workers on 30-9-1986. If real, he was retrenched alongwith other workers on 30-9-86, his name should have been included in the list of workers attached to the Award in I.D. 55/88. Award in I.D. 55/88 was passed on 3-12-90. Petitioner approached this Tribunal after lapse of seven long years from the date of Award in I.D. 55/88. This Tribunal has no hesitation to hold that petitioner filed this petition with a mala-fide intention to gain wrongfully, if possible, basing on Award in I.D. 55/88. This Tribunal has no hesitation to hold that petitioner was not a workman for any period under the respondent and he was not removed from service by respondent on 30-9-86 and so petitioner is not entitled for any relief. Petition is liable to be dismissed. Point is answered accordingly.

10. In the result, an award is passed holding that petitioner never worked as workman in the Project of the respondent for any period and that he was not removed from service on 30-9-1986 by the respondent. The petitioner is not entitled for any relief against the respondent. Petition is dismissed accordingly. This award shall become enforceable on expiry of 30 days from the date of its publication under Section 17 of I.D. Act by virtue of the powers conferred under Section 17-A(1) of the Act.

Dictated to stenographer and transcribed by him, corrected and pronounced by me in the open court and given under my hand and seal of this court on 20th day of September, 2000.

V. APPAI ANARASIMHAM, Judge

APPENDIX OF EVIDENCE ; WITNESSES EXAMINED :

For Petitioner/Workman :

W.W.1. 15-2-2000—K. Narasimha Rao.

For Respondent/Management :

M.W.1. 30-6-2000—C. K. Sahoo.

EXHIBITS MARKED :

For Petitioner/Workman :

Ex. W-1. 24-3-95—Minutes of Conciliation Proceedings between the Management and their workmen.

Ex. W-2. 31-3-95—Failure Report submitted to the Government of India by the A.C.L. Vijayawada.

Ex. W-3. — —Xerox copy of list of 21 persons.

Ex. W-4. 3-12-90—Xerox copy of award in I.D. 55/88 before the Industrial Tribunal, Hyderabad.

For Respondent/Management :

Ex. M-1. — —Xerox copy of Muster Roll for November, 1983.

Ex. M-2. — —Xerox copy of Muster Roll for the month of December, 1983.

Ex. M-3. — —Xerox copy of Muster Roll for the month of February, 1986.

Ex. M-4. — —Xerox copy of Statement showing the 25 retrenched Casual Labourers.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का. आ. 67.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मद्रास एटोमिक पावर स्टेशन, कल्पाक्कम के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित आदेशों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय केनई 6 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-42012/22/2000-आई आर (डी यू)]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December 2000

S.O. 67.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai-6, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Madras Atomic Power Station, Kalpakkam and their workman, which was received by the Central Government on 26-12-2000.

[No. L 42012/22/2000-IR(DU)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Wednesday, the 22nd November, 2000

PRESENT :

K. Karthikeyan, Presiding Officer.

Industrial Dispute No. 1/2000

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) and Sub-Section 2(A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of the (Station Director), Madras Atomic Power Station, Kalpakkam).

BETWEEN

P. Chinnasamy
S/o Sri Poongavanam

Workman/I Party

AND

The Station Director,
Madras Atomic Power
Station, Kalpakkam.

Management/II Party

APPEARANCE :

For the Workmen : Shri M. Gnanasekar, Advocate.

For the Management : Sri T. Ravikumar, Addl. Central
Government Standing Counsel.

REFERENCE :

No. L-42012/22/2000/TR(DU) dt. 31-5-2000 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

This dispute on coming up before me for final hearing on 8-11-2000, upon perusing the reference, Claim Statement, Counter Statement and other material papers on record, and the documentary evidence let in on either side and upon hearing the arguments of Shri M. Gnanasekar Advocate for the Workman and Sri T. Ravikumar, Addl. Central Government Standing Counsel for the Management and this dispute having stood over till this date for consideration, this Tribunal passed the following :—

AWARD

This reference by Central Government in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 in respect of dispute between Sri P. Chinnasamy, Workman and the Station Director, Madras Atomic Power Station, Kalpakkam Management mentioned as schedule appended to the order of reference.

The Schedule reads as follows :

“Whether the termination of Shri P. Chinnasamy by the management of Nuclear Power Corporation, Madras Atomic Power Station, Kalpakkam is legal and justified? If not, to what relief the Workman is entitled?”

On receipt of this reference, this Industrial Dispute has been taken on file of this Tribunal on 26-6-2000 as Industrial Dispute No. 1/2000. On receipt of the notice from this Tribunal, the Workman with his Authorised Representative and the Management with their Counsel appeared and filed their respective Claim Statement and Counter Statement.

1. The averments in the Claim Statement of the Workman/I Party/Petitionere are briefly as follows :—

The First Party Claimant (hereinafter mentioned as the Petitioner) was appointed in March 1971 as Helper-A and thereafter he was promoted as Helper-B in 1972 and he was further promoted as Tradesman-Mon-A in 1973. Thereafter, he was promoted as Tradesman-B, C, D, E and F. The promotion was ordered periodically after four years as there was no adverse remarks in his Confidential Report. He has not

faced any Departmental Enquiry nor he received any Memo from the department regarding his work and conduct. He has been diligently discharging his duties with devotion to the utmost satisfaction of his superiors. While so, he was issued a Charge Memo dated 18-6-1996. In that Charge Memo, three articles of charges were mentioned, as that, he, while functioning as Tradesman in Madras Atomic Power Station married another woman while his first wife was living, that he has suppressed the fact of his second marriage with another woman and by misrepresenting the facts, he applied for availing medical facilities for the children born out of his second marriage and that he nominated his second wife and the children born out of her for the purpose of death-cum-retirement gratuity/family pension and LTC/TA etc. prior to and after his absorption in Nuclear Power Corporation of India Ltd. leaving behind his legitimate wife and children and that he has acted in a manner that is unbecoming of a corporation employee. A preliminary enquiry was held by Mr. V. G. Uma-maheshwaran, Asstt. Personnel Officer. The marriage between himself and Smt. Muthu took place during the younger age without knowing about the legalities of the matter. Though, he applied for the Medical Card for the children born out of second wife, he has not taken the Medical Card or he has not taken any medical treatment in the DAE Hospital. It is true, that he nominated his second wife and the children born out of her for the purpose of death-cum-retirement gratuity/family pension, LTC etc. A regular enquiry was held by the Enquiry Officer and he submitted a report dated 23-11-96 holding the charges true. During the enquiry, he was not given sufficient opportunity to explain the circumstance in which he has conducted the second marriage. The marriage between himself and Smt. Kalyani took place in 1971 and immediately after the marriage, she could not lead a normal family life and she deserted him. In spite of the steps taken by him and the elder members of his family, no reconciliation could be done. His first wife gave a complaint in 1972, complaining that he was not maintaining her. He submitted his reply, stating that he has been maintaining her and providing her the basic facilities. Thereafter, a Memo was issued in 1975 on the same lines. For that also, he gave a reply that from 1974 onwards, his first wife is permanently staying away and leading a life of her choice, however at his cost. The fact that there is no complaint from his first wife to the Department from more than 25 years, only shows that there is an actual separation for more than 25 years and it is only under these circumstances, his second marriage took place with one Muthu. The nomination was given by him in the year 1987, more than 10 years ago. He was under the impression that the matter has been closed by the Department. In any event, the unfortunate event that took place in his personal life, never interfered with, nor influenced in discharging his duties as a responsible Government servant. The fact that he has put in 28 years of unblemished service cannot be easily ignored by the Department particularly while choosing the punishment. Though, he has stoutly denied the second charge in his representation dated 26-3-97 to the Disciplinary Authority, he has specifically requested the Disciplinary Authority to forgive him by taking note of his past service in the Station. He requested the authority to enforce any other punishment which may not affect his future. Even that human aspect has not been considered by the Disciplinary Authority. The punishment that may be imposed in the Departmental Enquiry should commensurate with the gravity of the alleged misconduct. In fact, the provisions regarding the prohibition of the second marriage in the Conduct Rules was introduced in order to protect the interest of the first wife. When the first wife has no grievance and she is leading a life of her own choice for nearly 25 years, suo-moto action under the CCS and CCA Rules should not be taken normally. He has not committed any serious misconduct by misappropriation, corruption, embezzlement of public money. Therefore, ignoring his 28 years of unblemished service is illegal. The Petitioner has two daughters at the marriageable age and one son. The Petitioner filed an appeal before the Appellate Authority to set aside the order of Disciplinary Authority and to reinstate him in service with all service benefits or to modify the punishment of removal from service by imposing other minor punishment, which may not affect his further employment, considering the length of his service and his family problems, explained already. The enquiry proceedings are vitiated for the reason that, the charges levelled against him were demonstrably vague and devoid any particulars. Hence, the charge Memo dated

18-6-96 is illegal. The Charge Memo does not disclose any misconduct or the provisions of the Standing Order said to have been violated by the Petitioner. No punishable misconduct was made out in the Charge Memo dated 18-6-90 and hence, the proceedings initiated in pursuance of that Charge Memo are illegal and liable to be set aside. The alleged occurrence relates to the year 1973. The Petitioner was allowed to continue in the Department for more than 30 years, after the alleged incident. It is settled law that, disciplinary proceedings for any misconduct should be initiated within a reasonable period of time. As per the decisions of the Supreme Court, the delay in initiating enquiry vitiates the enquiry itself, if there is extraordinary delay, it prima-facie causes prejudice, when it remains unexplained. The report submitted by the Enquiry Officer on 23-11-96 is illegal and in violation of the principles of natural justice. The Respondent ought to have seen that imposing the penalty of removal from service is highly arbitrary, excessive and shockingly disproportionate to the gravity of the misconduct. In the name of the enquiry, the petitioner's life has been taken away in the fag end of his career. The Petitioner cannot afford to go to any employment at this stage of his life. He has got social obligations to be performed. The application filed by the Petitioner before the Regional Commissioner of Labour (C) for conciliation, ended in a failure. Thereafter, the dispute regarding the Petitioner's non-employment has been referred to this Tribunal. Hence, it is prayed that this Tribunal may be pleased to set aside the order passed by the Disciplinary Authority to remove the Petitioner from service and consequently direct the Respondent to reinstate the Petitioner in service and to give him all attendant benefits including backwages from 1-10-1998.

2. The averments in the Counter Statement of the Management/II Party/Respondent are briefly as follows:—

The fact of the Petitioner, appointed in March 1971 and he got promotion as per the norms, from time to time, is admitted. It is incorrect to state, that the Petitioner was not issued earlier any Memo during his service. Once a Memo has been issued to the Petitioner for bringing a visitor inside the plant premises (Restricted Area) in the year 1974 and another Memo for violating the conditions of house allotment and during several occasions, he remained absent unauthorisedly from duty and that periods have been treated as "Dues-Non". Subsequent to his appointment in Atomic Power Station the Petitioner has declared Smt. Kalvani as his wife and had nominated her for Workman Contributory Provident Fund in his application dated 23-7-73. Further, for the purpose of ITC, Transfer TA etc. he had declared Smt. Kalvani as his wife in his application dated 4-11-1978. As a corporation employee and also being a Hindu, the Petitioner should not have a second wife, which is against law. With the mala fide intention and motive of availing medical facilities in respect of children, born out of the second wife, the Petitioner applied for medical cards. Thus, he intended to cheat the Department for obtaining medical card for children who are not entitled to under the scheme. An enquiry was conducted to enquire into the charges, regarding his second marriage. The Enquiry Officer has submitted his report dated 23-11-96, holding the charges as proved. The enquiry proceedings were conducted following the principles of natural justice and the Petitioner was given reasonable opportunity to defend the charges levelled against him. The Petitioner has accepted that he has taken Smt. Muthu as his second wife due to certain circumstances, leading to strained relations between him and his wife, Smt. Kalvani which is not relevant with the charges levelled against him. His first wife Smt. Kalvani has given a complaint in the year 1972. The contention of the Petitioner that his first wife is staying away from him and he had been maintaining her is not relevant and germinate to the charges levelled against him. The actual separation takes place only after the competent Family Court passes an order to that effect in a legal proceeding which has not been followed by the Petitioner. In the complaint dated 27-12-71 the first wife of the Petitioner, Smt. Kalvani had complained that the Petitioner has married another woman 4 years back and has started ill-treating her without looking after her and her children. If the separation has taken place as alleged by the Petitioner, he would not nominate his first wife, Smt. Kalvani in the year 1995. The Disciplinary Authority after taking into account the material on record the charges levelled against the Petitioner in the enquiry arrived at proper

conclusion and imposed the punishment of removal of the Petitioner from his service. It commensurates with the gravity of misconduct committed by the Petitioner. No bias has been alleged against the officials and it is the subjective satisfaction of the official who come to a conclusion and renders the punishment. The Petitioner made an appeal to the Appellate Authority to modify the punishment of removal from service to any other minor penalty. The Appellate Authority on due consideration has concurred with the decision of the Disciplinary Authority in view of the circumstances, evidence on record and also the due acceptance of the charges by the Petitioner and after obtaining concurrence from the Department of Atomic Energy, Government of India while imposing the penalty. Thus, continuance of Sri Chinnasamy in service would send wrong message to the other employees of the plant and society in general. The charges have been clearly brought out in the Charge Memorandum dated 18-6-96. The Petitioner knew and understood the same. The enquiry was conducted following the principle of natural justice under the model Standing Order applicable to the Petitioner. The applicability of the model Standing Order to the Petitioner has been clearly mentioned in the terms and conditions for absorption in Nuclear Power Corporation of India Ltd. services which has been duly accented by him. The Petitioner's contention that the Department had taken action after a period of 30 years of the misconduct, which is time barred is not correct and acceptable. The Department had initiated disciplinary action, only after the Petitioner submitted revised claim for medical card in respect of children born out of Smt. Muthu, his second wife on 30-8-95 and other nomination. Disciplinary action was initiated on 18-6-96 and concluded on 1-10-98. There is no belated action on the part of the Department for taking the disciplinary action. The disciplinary action was initiated under model Standing Order. Though, medical facility was not availed by the Petitioner for his children through his second wife, submitting a request for medical card for his second wife children, who are not entitled, is itself a misconduct of the Petitioner, because he has misrepresented the facts before the Department, with an intention to avail illegitimate advantages under rule of availing medical facilities for the children of his second wife. The Petitioner has admitted that charge before the enquiry authority. The Petitioner having accepted the charges, during the course of the enquiry, cannot at this juncture say that the Charge Memo is not sustainable. It is purely an afterthought. It is not necessary to have a complaint from the first wife of the Petitioner to initiate disciplinary action against him. This act of the Petitioner, having a second wife, which is contrary to Hindu Marriage Act and also an offence under Section 494, Indian Penal Code, required stern action under Service Rules and appropriate disciplinary measures were taken by the Department. Any penalty lesser than removal from service would have sent wrong message to other employees and the society and would have given room for encouragement for others. Having two wives, the Petitioner cannot continue to remain in the employment of this Department and hence the punishment of removal from service was specified and commensurate with the gravity of misconduct committed. Any lesser punishment would have entailed him to continue in the service which could not have been allowed while still having a second wife. Infact, the service continuously rendered by him in the Department need to be seen as a grace to him. Hence, it is prayed that this Tribunal may be pleased to dismiss this Industrial Dispute with cost.

4. The Point for my consideration is:—

"Whether the termination of Sri P. Chinnasamy by the Management of Nuclear Power Corporation, Madras Atomic Power Station, Kalpakkam is legal and justified? If not, to what relief the Workman is entitled?"

Point.—When the matter was taken up for enquiry, the counsel appearing on either side represented that they have no oral evidence to let in. 13 documents on the side of the workman and 16 documents on the side of the second party management were marked by consent as Ex. W1 to W13 and Ex. M1 to M16 respectively. On completion of evidence on either side the counsel advanced their respective arguments.

The respondent originally a government department was functioning as Madras Atomic Power Station which subsequently converted as a public sector undertaking with effect

from 17-9-87 as the Nuclear Power Corporation of India Ltd., a Govt. Company incorporated under the Companies Act, 1956. The first party claimant was appointed as a helper-A in the erstwhile Govt. department in March 1971. And subsequently, he got his promotions periodically. Then on conversion of the Govt. department into a public sector undertaking, 1 party workman was absorbed as an employee under Nuclear Power Corporation of India. The 1 Party Workman Shri P. Chinnasamy was a married man when he got appointed in March 1971 and his wife's name is Smt. Kalyani. While he was functioning as tradesman in Madras Atomic Power Station having another woman, Smt. Mathu, when his first wife Kalyani was living, and he was continuously in service in Nuclear Power Corporation of India, he was issued a Charge Memo dated 18-6-1996 and that Charge Memo, three articles of charges were mentioned, as he was working as Tradesman in Madras Atomic Power Station, married another woman when his first wife was living and that he has suppressed the fact of his second marriage with another woman and by mis-representing the fact, he applied for availing medical facilities for the children born out of his second marriage and that he nominated his second wife and the children born out of her for the purpose of death-cum-retirement gratuity/family pension and LTC/TA etc. prior to and after his absorption in Nuclear Power Corporation of India Ltd. It is admitted that a preliminary enquiry was held by Mr. V.G. Umamaheshwaran, Asstt. Personnel Manager of the Company. The Enquiry Officer conducted a regular enquiry and he submitted a report dated 23-11-96 holding the charges as true. On the basis of the finding of the Enquiry Officer in his report, the disciplinary authority passed an order imposing a punishment of removal of the delinquent official, P. Chinnasamy from service. Aggrieved by that order, the Petitioner/Workman preferred an appeal to the Appellate Authority. The Appellate Authority concurred with the decision taken by the disciplinary authority and confirmed the penalty imposed against the Petitioner/Workman. Then the Petitioner/Workman preferred an application before the Regional Commissioner of Labour (C), Chennai for conciliation. Since the conciliation was ended in a failure, the Conciliating Authority submitted a Failure of Conciliation Report to the Govt. and Govt. in turn has made this reference for adjudication by this Tribunal.

6. It is the grievance of the Petitioner/Workman that during the enquiry he was not given sufficient opportunity to explain the circumstances in which he has performed the second marriage and that he has already submitted a reply for an earlier memo issued to him in 1975, that from 1974 onwards, his first wife is permanently staying away and leading a life of her choice and under those circumstances, his second marriage took place with one Smt. Mathu. He would further contend that the enquiry proceedings are vitiated for the reason that the charges levelled against him were demonstrably vague and devoid of any particulars and that the Charge Memo dated 18-6-1996 is illegal. It is his further contention that as per the settled law, disciplinary proceedings for any misconduct should be initiated within a reasonable period of time and the delay in initiating the enquiry vitiates the enquiry itself. So, the report submitted by the Enquiry Officer on 23-11-96 is illegal and in violation of the principles of natural justice and that the penalty of removal from service imposed by the disciplinary authority is highly arbitrary, excessive and shockingly disproportionate to the gravity of the misconduct. So, the action of the Management by ordering termination of service is illegal and unjustified. The Respondent Management has denied all this averments in the Claim Statement. It is admitted that prior to imposing of punishment by the disciplinary authority, there was a proper enquiry conducted by an Enquiry Officer and in view of the conclusion in the enquiry he submitted a report with the findings that the charges levelled against the Workman, the delinquent official were proved. It is the further contention of the Second Party Management that the enquiry was conducted by the Enquiry Officer, giving sufficient opportunity to the delinquent official to defend the imputations and that the delinquent official has admitted the misconducts mentioned the charges as true and he prayed for a lesser punishment, considering his long service in the Company. So, it is to be found whether there is no proper, valid enquiry by the

Enquiry Officer, following the principles of natural justice and whether the Enquiry Officer has given a perverted finding, not supported by any evidence and whether it is a fit case for this Tribunal to interfere with the findings of the Enquiry Officer and is there any scope for such interference.

7. The First Party Workman has filed 13 documents on his side. Ex. W1 is the Charge Memo dated 18-6-1996, issued to the First Party Workman by the Management. In that Charge Memo, three articles of charges have been mentioned as the misconducts committed by the First Party Workman. First charge is that he married another woman while his first wife is living. The second one is that he mis-represented the facts for availing of medical facilities for the children born out of his second marriage and the third one is he nominated his second wife and her children for the purpose of death-cum-retirement benefits/family pension/LTC/TA etc. For that Charge Memo, the Petitioner/Workman, Chinnasamy has given an explanation dated 8-8-96 in his own handwriting admitting the fact of his second marriage and also applying for medical facilities for his issues through the second wife and has also stated that he repents for the misdeeds and he may be pardoned. That reply is Ex. W2. Ex. W3 is the proceedings of the preliminary enquiry conducted by the Enquiry Officer on 15-11-96. In that, the Enquiry Officer, the Presenting Officer and the Workman Chinnasamy have subscribed their signatures in all the three pages of the document. In that preliminary enquiry report, it is stated that the Enquiry Officer asked the charged official whether he is accepting the above charges or denying the charges. For that, the charged official accepted the charges and pleaded guilty and has stated as his reply for every charge that he got married to Smt. Mathu and it had happened in his younger age and he did not knowing about the legality of those matters and that he had applied for the medical cards for the children born out of his second marriage but he has not taken the medical cards and have not taken any medical treatment in the DAE Hospital. He had earlier taken medical cards for his members of the family, Kalyani (Wife), Lakshmi (Daughter), Poongavanam (Father) and Ponnammal (Mother). For the third charge the delinquent officer, the Petitioner herein has informed the Enquiry Officer that what are all the details he has given is true and he nominated his second wife and the children born out of her for the purpose of death-cum-retirement family pension/LTC/TA etc. In that enquiry report itself it is stated that the above proceedings were read over in Tamil to the charged official and the same was accepted by the charged official. So, from this it is seen that sufficient opportunity has been given to the charged official, the Workman, Chinnasamy and he has also signed the entire proceedings. Ex. W4 is the enquiry report, submitted to the Enquiry Officer, it is dated 23-11-96. The Enquiry Officer has given a finding in his report that Shri P. Chinnasamy is proved to be guilty of the charges mentioned in the articles 1, 2 and dated 18-6-1996. Ex. W5 is a letter dated 11-12-1996 issued to the Workman, Chinnasamy by the Department alongwith the report of the Enquiry Officer. It is stated therein that the disciplinary authority will take a suitable decision considering the report and if the Workman wishes to make any representation or submission, he may do so in writing to the Sr. Manager within 15 days of the receipt of the letter. Ex. W6 is a representation made by the Workman Chinnasamy dated 26-3-97. In that, he has stated that would like to convey his reply after a deep thought and determination with reference to the enquiry held on 15-11-96 and he has nothing to explain or deny the charges initiated against him and he can only beg or plead to forgive him based on the consideration of his past service in the Company and is ready to undergo the punishment which cannot affect his life. Ex. W7 is the order dated 1-10-98, passed by disciplinary authority, Sr. Manager (P&IR) imposing a punishment of removal from service. In that order itself, he informed that if he prefers to file an appeal, he can do so within 45 days of the receipt of that order. Ex. W8 is the copy of the appeal preferred by the Workman, Chinnasamy dated 15-10-98 to the Station Director Madras Atomic Power Station, Kalpakkam. In that appeal itself, he clearly stated that during the enquiry, he was given sufficient opportunity to explain the circumstances in which he married the second wife, Smt. Mathu in the year 1972. In that appeal itself, the Workman, Chinnasamy has requested for minor punishment to be imposed instead of the punishment of removal from service. Ex. W9 is the order passed

the Appellate Authority dated 23-4-1999. The Appellate Authority has stated in that order that he confirms the penalty of removal from service imposed on the Workman by the disciplinary authority. Ex. W10 is the petition, the Workman, Chinnaasamy has presented before the Asstt. Labour Commissioner (C), Chennai for conciliation. Ex. W11 is reply filed by the Second Party Management before the Conciliating Authority. Ex. W12 is the Failure of Conciliation Report of Asstt. Labour Commissioner (C), Chennai to the Ministry of Labour, Government of India. Ex. W13 is filed by the First Party Petitioner, Workman, Chinnaasamy. It is a document dated 8-1-1992, issued to the Workman, Chinnaasamy by Asstt. Personnel Officer with the letter dated 27-12-81 received from the wife of the Workman, Smt. Kalyani and in that letter, the Management wanted the Workman to submit his explanation within 7 days from the receipt of that letter. From this, it is seen that as early as 27th December, 1981 itself, the First Party Workman, Chinnaasamy's first wife Kalyani had preferred a complaint before the authority informing them that when she is living as first wife of the Workman, Chinnaasamy, her husband has brought another woman into their house some four years back and is living with her, ever since then and with three children born to her. From all these documents and the particulars available from these documents, it is seen that the Workman, Chinnaasamy has admitted the fact that he married a second wife, when the first wife is living and that marriage took place as early as 1972. It is seen from Ex. W1, the Charge Memo, that the documents on which the articles of charges have been framed were shown in Annexure-III. They are Master Medical Card, Declaration dated 23-7-73 for the purpose of PF nomination and family details dated 4-11-78 for the purpose of LTC/TA, Death Gratuity/Retirement Gratuity nomination dated 14-7-87, Application dated 30-8-95 for CHES Facility and the nomination dated 31 under Rule 7 of CCS Rules, nomination dated 31 for Death Gratuity/Retirement Gratuity and details of family (Rule 54-12) submitted for bonus sum in view of 100 per cent pro-rata commutation. From all these documents, it is seen that the Enquiry Officer has conducted a fair and proper enquiry giving sufficient opportunity to the delinquent official, Workman, Chinnaasamy and the enquiry has been conducted, based on the documentary evidence and that after hearing the Workman, Chinnaasamy, his reply to the charges levelled against him, in person, the Enquiry Officer has come to the proper conclusion and held that the charges levelled against the Workman, Chinnaasamy has been proved. None of the charges levelled against him, was denied by him, in the enquiry as false or incorrect. He never expressed before the Enquiry Officer or before the disciplinary authority or in his appeal that he has not been given sufficient opportunity and the enquiry has been conducted in an unfair manner. From this, it is seen that the contention of the Petitioner, Chinnaasamy that there was no fair and proper enquiry and the Enquiry Officer has not followed the principles of natural justice are all not correct, besides being false. Ex. M1 to M8 are various forms submitted by the Petitioner/Employee, Chinnaasamy as nomination forms and details of his family members. All these documents have been signed by Chinnaasamy himself. These documents have not been disputed by the First Party Workman. These documents clearly show that the contention of the Second Party Management that the employee, Chinnaasamy has balked the fact of his second marriage and has filed nominations for availing the benefit of medical facilities for his second wife and his children through his second wife, when the first wife is all the more alive. The Ex. M11, the medical card No. 430 of the Petitioner and Ex. M12, the application dated 30-8-95 given by the Workman Chinnaasamy for addition of names of beneficiaries are also the documents in support of the Second Party Management's contention. All these documents filed on the side of the Management viz. M1 to M16 have not been disputed by the First Party Workman, Chinnaasamy. On the basis of the evidence available on either side as documents it is clearly seen that the Enquiry Officer on the basis of the materials available by way of documents and on the basis of the admission of the Workman, Chinnaasamy himself he has come to a correct and proper conclusion that the charges levelled against Chinnaasamy has been proved. It cannot be said that the Enquiry Officer has acted in a biased manner or he has given his findings without evidence. Under such circumstances, there is no scope for this tribunal to interfere with the findings given by the

Enquiry Officer in his report. Ex. W4 and that finding given by the Enquiry Officer cannot be interfered with.

8. It is an admitted case that the Petitioner/Employee was a Government employee who subsequently opted to join NPCIL w.e.f. 17-9-94 and that consequent to his joining the corporation, he is governed by Certified Standing Orders of the corporation. It is not disputed that since the Standing Orders for Madras Atomic Power Station has not been certified so far, hence he is governed by the Model Standing Orders in accordance with the Industrial Establishment (Standing Orders Act 1946). Hence, the fact that the Model Standing Orders are applicable to the Petitioner/Workman after his absorption in NPCIL services cannot be denied. It is seen from the materials available in this case that the absorption of the employees of erstwhile Madras Atomic Power Station has been made for NPCIL at the option given by the employees. Like that, the First Party Employee was absorbed at his option in the services of the NPCIL on and from 17-9-94. From this, it is seen that the First Party Employee is governed by the Model Standing Orders in accordance with the Industrial Establishment (Standing Orders Act 1946). The learned counsel for the First Party Petitioner/Employee has advanced an argument that it is settled law that the employer has got disciplinary jurisdiction with regard to the allegations of misconduct committed by the employee while the employee is in service with the employer and the disciplinary jurisdiction of the employer cannot be extended to cover the cases of alleged misconduct said to have been committed by the employee while the employee was in service in respect of some other employer and not with reference to employment and hence the alleged misconduct of the Petitioner/Employee of marrying a second wife when the first wife is living had happened when he was an employee in Madras Atomic Power Station and the disciplinary action was taken for the said misconduct by the subsequent management, NPCIL cannot be considered as a correct action taken by the employer. He would further argue that the misconduct of the Petitioner's second marriage, said to have been committed by the Petitioner in the year 1973, the NPCIL has no jurisdiction or authority to initiate disciplinary action. For this, the learned counsel for the Management would submit his argument that even though the employee, Chinnaasamy has contracted the second marriage in 1973 when he was under the services of Madras Atomic Power Station, subsequent to his absorption on 17-9-94 by NPCIL to its services, he has committed a misconduct in pursuance of his earlier misconduct of contracting the second marriage, by furnishing details of family particulars, Ex. M2, M6, M7 and on that basis by furnishing required forms of nomination under Ex. M1, M3 and M4 with a dishonest intention to avail the medical benefits for the second wife and the children through second wife. Thereby he committed fraud which is a misconduct as enumerated under the Model Standing Order and this is done by the employee, only when he came to the services of NPCIL. So, under such circumstances, the argument advanced by the learned counsel for the First Party Petitioner/Employee cannot hold good. This argument of the learned counsel for the Second Party Management is plausible and acceptable.

9. It is the argument of the learned counsel of the Petitioner/Employee that nowhere in the Model Standing Order, it is stated that contracting the second marriage by the employee, while in service and when the first wife is alive, as a misconduct. In Clause 14, Sub-clause (3), various misconducts have been enumerated in the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946. Under those various misconducts enumerated as A to K, committing or contracting a second marriage by the employee, when the first wife is alive or the first marital status is in subsistence has not been stated as a misconduct. So, in the absence of one such act to be considered, as a misconduct, in the Standing Orders, it is incorrect to state that as per the Standing Orders, he has committed a misconduct punishable by the disciplinary authority. It is admitted that no such act has been described as one among the misconducts enumerated under the said Standing Orders. On the other hand, it cannot be denied that the Petitioner/Employee after becoming an employee under NPCIL had submitted to the Management, Ex. M1 to M8 for the purpose of availing the medical facilities for his second wife and also for the children through the second wife, without disclosing the fact that they are the children

through his second wife. This act of the First Party Employee can be very well considered as a misconduct when he is intentionally burked some facts before the Management only for availing some benefits in pursuance of his service under the Management and that misrepresentation of facts to the Management with the dishonest intention, amounts to fraud only. The same act has been admitted by the employee himself during the enquiry conducted by the Department through an Enquiry Officer and he has admitted the same by giving it in writing as his explanation under Ex. W2. This can be considered as misconduct enumerated as Sub-clause G in Sub-clause (3) of Clause 14 of Industrial Employment (Standing Order) Central Rules 1946. It has been mentioned as "habitual breach of any law applicable to the establishment". So, the action taken by the Employer, against the employee, for that misconduct, through a Departmental Enquiry and found the First Party Employee, Chinnasamy guilty of the charge for that misconduct and on the basis of that Enquiry Officer's report, Ex. W4, the disciplinary authority proceeded further to impose punishment can be considered proper, valid and justifiable. The learned counsel for the First Party Employee, Chinnasamy, would further argue that when the act committed by the employee by marrying a second wife during the lifetime of his first has not been mentioned as a misconduct under the Model Standing Order, it is wrong to say that he has committed a misconduct and on that ground, imposing a punishment by the disciplinary authority is incorrect. In support of his contention, he is relying upon a judgement rendered by High Court of Madras. It is a case reported as 1995-1-LLJ, Page 931 between J. Dhanraj and TNEB and others. In that case, the Hon'ble High Court of Madras has held that no disciplinary action could be taken in respect of an act not enumerated as an act of misconduct under the Certified Standing Orders. As per the facts of the sighted case, decided by the Hon'ble High Court of Madras, the employee was an Asstt. Operator belonging to the regular work establishment in the Tamil Nadu Electricity Board. He was served with a Charge Memo that he contracted the second marriage when the first wife is alive and that he claimed MRI Bills in the name of the second wife. He was called upon to submit his explanation as to why disciplinary action should not be taken against him. He submitted an explanation. Not satisfying with the explanation offered by the employee, disciplinary proceedings were initiated against him and he was guilty of bigamy. Then, a show-cause notice was issued to him directing him to show-cause as to why he should not be punished by reverting him to the post of Helper for a period of 3 years from the rank of Asstt. Operator. On submission of his explanation, a Memo was issued to him on 11-9-84 mentioning that the show-cause notice issued earlier on 5-8-83 was cancelled and another memo was issued on the same day calling upon to show-cause as to why the punishment of removal from service should not be imposed on him. That show-cause notice was sought to be quashed by the High Court in the Writ Petition preferred by him. The Hon'ble High Court of Madras held in that case, following the decision rendered by the Supreme Court, reported as 1984-1-LLJ SC Page 16, "Glaxo Lab. (I) Ltd. vs. Labour Court, Meerut & Others" that some acts of misconduct not enumerated in the Standing Orders, as the acts of misconduct, cannot be considered enough to impose penalty against a worker who is governed by the Standing Orders. A division bench of High Court of Madras in a case reported as 1990-1-LLJ-96, "S. Alampelu vs. S. E. Electricity System" followed the Supreme Court judgement has held that "No

doubt Regulation 25(2) of Tamil Nadu Electricity Board Employees Conduct Regulations would be an embargo on a woman employee contracting a marriage with any person who has a wife living, without obtaining the permission of the board, but the Standing Orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act having got formulated and certified and they having not provided for such a misconduct and there being no provision therein for such an eventuality, the Regulation would not prevail and could not be invoked to take disciplinary action". Following these decisions, Hon'ble High Court of Madras has held in that case that "In the absence of bigamous marriage of an employee, enumerated as a misconduct in the relevant Standing Order, it cannot be considered as a misconduct" and passed an order in the Writ Petition quashing the show-cause memo, for punishment of removal from service, issue to the Petitioner/Employee by the Employer. This decision the Hon'ble High Court, following the decision of the Supreme Court in that case is squarely applicable to this case also. In the absence of any Certified Standing Order the Second Party Management has followed the Model Standing Order under Industrial Employment (Standing Orders) Act. Admittedly, in that Model Standing Order Central Rules 1946 under Clause 14, Sub-clause (3), A to this bigamous marriage has not been mentioned as an act of misconduct for a disciplinary action to be taken against an employee. Hence, the action of the Second Party Management, Disciplinary Authority, treating it as a misconduct on the basis of a finding to that effect by an Enquiry Officer in his report, for awarding a major punishment of removal from service is incorrect.

It is seen from the materials available in this case Ex. M1 to M8, the First Party Workman, Chinnasamy submitted his forms of nominations and family particulars avail the medical benefits of the second wife and the children through the second wife. As the learned counsel for Second Party Management stated in his argument, this been done by the First Party Workman with the dishonest intention to avail the medical benefits for his kith and who is not legally entitled for that benefits and thereby has committed a fraud, which is enumerated as a misconduct in the Model Standing Order adopted by the Second Management, which is applicable to this First Party employee. Under such circumstances, the finding of the Enquiry Officer in his report that the charges framed on this have been proved, can be considered as correct. The disciplinary authority, in pursuance of the finding of the Enquiry Officer, for the charges levelled against the First employee, for the above misconduct, has imposed a punishment of removal from service. This imposition of extreme punishment of removal from service, by the disciplinary authority, is excessive and disproportionate to the gravity of the misconduct. Hence under such circumstances, this Tribunal is of the opinion that the extreme punishment imposed

disciplinary authority, against the First Party Workman is unjustified. In view of these findings, it is held that the termination of Shri P. Chinnasamy by the Management of Nuclear Power Corporation, Madras Atomic Power Station, Kalpakkam is not legal and justified and the Workman, Shri P. Chinnasamy is entitled to be reinstated in service with some conditions. Thus, I answer the point accordingly.

In the result, an award is passed setting aside the order of removal from service dated 1-10-98 by the Management, Second Party and thereby directing the Second Party Management to reinstate the First Party Workman, P. Chinnasamy in service forthwith, treating the period from 1-10-98 to this date as extraordinary leave with half pay and with other consequential monetary and other attendant benefits. In the circumstances of the case, there is no order as to cost.

Dictated to the Stenographer and typed by him direct and corrected and pronounced by me in the open court on this day, the 22nd November, 2000

K. KARTHIKEYAN, Presiding Officer

Witness Examined

For Claimant/I Party—None.

For Management/II Party—None

DOCUMENTS MARKED

For Claimant/I Party :

- Ex. W1 18-6-96—Charge Memo.
- Ex. W2 8-8-96—Representation made by the Petitioner.
- Ex. W3 15-11-96—Proceedings of preliminary hearing
- Ex. W4 23-11-96—Enquiry Report.
- Ex. W5 11-12-96—Letter from the 3rd Respondent
- Ex. W6 26-3-97—Representation made by the Petitioner.
- Ex. W7 1-10-98—Order of removal.
- Ex. W8 15-10-98—Appeal preferred by the Petitioner.
- Ex. W9 23-4-99—Order rejecting the Petitioner Appeal
- Ex. W10 12-8-99—2-A, Petition filed by the Petitioner.
- Ex. W11 3-12-99—Comments filed by the Respondent.
- Ex. W12 31-1-2000—Failure report of the Conciliation Proceedings.

For Management/II Party :

- Ex. M1 — —Form 1—Nomination for death-cum-retirement gratuity.
- Ex. M2 — —Form 3—Details of family.
- Ex. M3 — —Form 5—Nomination under Rule 7 of CS Rules, 1961.
- Ex. M4 — —Form 4—Nomination for Employees Provident Fund.
- Ex. M5 — —Form B—Fresh nomination.
- Ex. M6 14-6-87—Form 3—Details of the family.
- Ex. M7 — —Form 3—Details of the family.
- Ex. M8 14-7-57—Form I—Nomination for death-cum-Retirement Gratuity.
- Ex. M9 4-8-73—Letter from Mrs. Kalyani dated 4-8-73.
- Ex. M10 27-12-81—Letter from Mrs. Kalyani dated 27-12-81.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2000

का. आ. 68—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कमाण्डेंट, आर्मी बेस वर्कशॉप के प्रबन्धन के संवद्ध गियोअकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2000 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14011/7/97-आई आर (डी यू)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th December, 2000

S.O. 68.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Commandant, Army Base Workshop and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2000.

[No. L-14011/7/97-IR(DU)]

KULDIP RAJ VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI R. P. PANDEY, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR,
KANPUR

Industrial Dispute No. 14 of 1998

In the matter of dispute between—

The Secretary,

Defence EME Employees Union
74, A/25 B Pura Dalel Allahpur
Allahabad.

AND

Commandant and MD
508 Army Base Workshop
Allahabad Fort 211005.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-14011/7/97-IR (DU) dated 1-1-98 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of 508 Army Base Workshop Allahabad in awarding punishment to TN 3674 TCS Shri G. S. Pathak vide their order No. 21206/3674-GSP/Est. Ind. dated 10-11-94 is justified? If not what relief the workman is entitled?"

2. The claim statement has been filed by Defence EME Employees Union on behalf of the workman with the allegations that the applicant union is the representative union of the workman of Army Base Workshop Allahabad and Sri G. S. Pathak the punished employee is a member of Works Committee constituted under Section 3 of Industrial Disputes Act, 1947 and rules made thereunder in the said Industrial Establishment. 1st October, 1994 was Saturday and working hours of the industrial establishment of 508 Army Base Workshop Allahabad were from 0815 hours to 1345 hours. The monthly wages for the industrial personnel were to be paid on that day by the management. Since the payments could not be started till 1415 hours on that day, Sri G. S. Pathak as a member of Works Committee alongwith other members of the same committee went to the Office General-Manager (Admn.) Col. S. C. Verma at about 1415 hours and requested him to arrange opening of the workshop for full day and compensate this extra period of this day on 3-10-94 by opening workshop upto 1345 hours. It has been alleged that Sri Verma did not listen to them and he himself misbehaved with the members of the Works Committee. It has been alleged that to cover up his misbehaviour Sri Verma served a show cause notice vide letter 3-10-94, the copy of which is annexure 1 to the statement of claim. Sri G. S. Pathak submitted its reply vide his letter dated 7-10-94 a true copy of which is annexure 2 to the statement of claim. Instead of dropping the matter Sri S. C. Verma himself under his own signatures served a chargesheet under Rule 16 of CCS (CC&A) Rules 1965, framing charges against the workman. The copy of that memo of charge is annexure 3 to the claim statement. Sri G. S. Pathak submitted his reply vide his letter dated 27-10-94 in which he denied the charges

levelled against him. The workman demanded that a regular enquiry be made in the case but Col. S.C. Verma, the disciplinary authority did not pass any order for holding regular enquiry and passed impugned order of punishment dated 10-11-94 awarding penalty of withholding of increment for three years without cumulative effect. The copy of order dated 10-11-94 is annexure 5 to the statement of claim. It has been alleged that aforesaid order of punishment is illegal because it has been passed by the disciplinary authority who was himself in the position of a complainant, hence the action taken by him against the workman is hit by principles of natural justice. It has also been alleged that impugned order of punishments non speaking order and is, therefore, illegal and is liable to be quashed. The workman filed an appeal against the order of punishment which was rejected. Then he filed revision against the appellate order which was also rejected. Then an industrial dispute on his behalf has been raised and the matter has been referred to this Tribunal for decision. On the basis of aforesaid allegation it has been prayed that impugned order of punishment may be quashed.

3. The management has filed written statement in which it has been alleged that G. S. Pathak is not a workman hence the dispute raised before this tribunal does not come within the definition of Industrial Dispute and this tribunal has no jurisdiction to decide the dispute referred to this tribunal. It has also been alleged that on 1-10-94 Sri G. S. Pathak instigated approximately 8 other workers of the same establishment and personally led them indulging in riotous behaviour from 1400 hours to 1445 hours on the same day in corridors of the Administrative Block and did not obey the orders of Administrative Officer Sri Verma when he asked them to leave the block. Thus he indulged in an act unbecoming of a Government Servant and thereby violated the provisions of Rule 3 of CCS (Conduct) Rules. It has been alleged that Sri S.C. Verma being the disciplinary authority was competent to issue memo of charge to the delinquent employee under Rule 16 of CCS (CC&A) Rules 1965, and after considering his explanation he was competent to pass the impugned order of punishment. It has been alleged that there is no illegality in the order of punishment passed against Sri G. S. Pathak. It has been prayed on behalf of the management that the reference should be decided against the workman.

4. On behalf of the workman rejoinder has been filed in which facts alleged in the claim statement has been reiterated.

5. The parties of the case have not adduced any oral evidence. On behalf of the workman 14 documents have been filed which have been marked Ext. W-1 to Ext. W-14 and on behalf of the management 10 documents have been filed which have been marked as Ext. M-1 to M-10.

6. I have heard the representative for both the sides and have gone through the record of the case. The representative for the management has argued that this Tribunal has no jurisdiction to decide this case because the dispute is not covered under Industrial Disputes Act, 1947. After going through the record of the case, I do not find any force in this contention. From the perusal of Ext. W-10 it is clear that Works Committee was constituted under Rule 43 of I.D. (Central) Rules, 1957. The management has admitted that Sri Pathak was a member of the Works Committee. The contention of the union that Sri Pathak was a member of Works Committee constituted under Industrial Disputes Act and Rules made thereunder has not been disputed before me. I, therefore, hold that the concerned establishment was governed by Industrial Disputes Act and the Rules made thereunder and the concerned employee comes within the definition of workman as defined under the Act. At the dispute has been raised by his union on his

behalf the dispute comes within the definition of Industrial Dispute as defined under the Act and the dispute has been referred to this Tribunal by Government of India under Section 10 of the I.D. Act, hence this Tribunal has jurisdiction to decide the dispute. The contention of the management to the contrary is hereby rejected.

7. It has been contended on behalf of the workman that when the workman had demanded full fledged enquiry in this case, the disciplinary authority must have held full fledged enquiry in this case but this was not done, hence the order of punishment is vitiated. After going through the record of the case and rule 16 of CCS (CCA) Rules, 1965, I do not find any force in this contention. It was within the discretion of the disciplinary authority to hold enquiry according to the procedure prescribed for minor penalty. In this case the disciplinary authority did not think it proper to hold regular enquiry specially when the misconduct was a minor one for which minor punishment has been awarded. In these circumstances impugned order of punishment cannot be said to be illegal merely because the procedure prescribed for major penalty was not followed in this case.

8. The representative for the workman has argue that impugned order of punishment is a non speaking order, hence it is liable to be quashed. After going through the impugned order of punishment, the memo of charge and the reply given by the workman against the memo of charge, I do not find any force in this contention. The reply given by the concerned workman against the charge sheet has been fully considered by the punishing authority while passing the impugned order of punishment. Almost all the points raised by him have been fully replied by disciplinary authority and the reasons for awarding punishment have been given. I, therefore, hold that impugned order of punishment is a speaking order and cannot be set aside on the ground that it is a non speaking order.

9. It has been contended on behalf of the workman in the statement of claim and also during the course of arguments that S. C. Verma disciplinary authority was not competent to pass impugned order of punishment specially when he was in position of a complainant and the impugned order of punishment is vitiated because Sri Verma could not be the judge of his own cause. After going through the record of the case and the relevant rules, I do not find any force in this contention. The record shows that Sri S. C. Verma was victim

awarded to the concerned workman Sri G. S. Pathak comes within the definition of minor punishment. The memo of charge could be issued under signature of the disciplinary authority and he was competent to consider the reply submitted by the delinquent employee against the charges. Thus Sri S. C. Verma has acted according to the rules while passing impugned order of punishment against the concerned workman. The present case is covered by Rule of Necessity as the disciplinary authority had no option but to exercise the powers under rules given to him in these circumstances the impugned order of punishment cannot be said to be illegal merely because it has been passed by disciplinary authority who was victim of misbehaviour committed by the concerned workman.

10. In view of finding recorded above, I do not find any illegality in the impugned order of punishment dated 10-11-94. I therefore hold that the action of the management of 508 Army Base Workshop Allahabad in awarding punishment to T.N. 3674 TCS Shri G. S. Pathak vide their order No. 212061 A 3674-GSP/Est. Ind. dated 10-11-94 is justified. Consequently, the concerned workman is not entitled to any relief. The reference is answered accordingly.

R. P. PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2001

का. प्रा. 69.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा "प्रवृत्त शक्तियों" का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 फरवरी, 2001 की उक्त तारीख के रूप में प्रवृत्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अनुच्छेद-4 अनुच्छेद-5 धारा 66 धारा 76 की उप धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है, के संशोधन अधिनियम 1999 के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, यथा :-

अजमेर, अजमेर के अजमेर शहर में राजस्थान ग्राम मंडलकुपम, सिद्धादीपुरम, कुडिहारा, पंचगुप्तन, पेरिय-कर्मगणकुपम, विन्तनगणकुपम, त्यागवल्ली, करीकाहु, जेला-कर्मगणकुपम, जिलाकारिका, कडवा (उत्तर गंगानदी में)

New Delhi, the 3rd January, 2001

following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

S.O. 69.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 2001 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (i) of Section 76 and Sections, 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the

"Areas comprising the Revenue Villages of Manjakuppam, Thiruvandhi Puram, Kudikadu, Pachaianguppam, Periakangananguppam, Chinna Kangananguppam, Thiyagavalli, Karaikadu, Chellanguppam, Cuddalore (Municipal), Cuddalore (Non-Municipal), Thiruppapuliyur, Vilvarayanatham, Vanniyarpalayam, Devanampattinam, Kondur (Municipal), Kondur (Non-Municipal), Chemmanguppam, Ponniyanguppam of Cuddalore Taluk of Cuddalore District."

[No. S-38013/54/2000-SS.I]

J. P. SHUKLA, Dy. Secy.

